हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

01 मार्च, 2017 (द्वितीय बैठक)

खंड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 01 मार्च, 2017 (द्वितीय बैठक)

	पृष्ठ संख्या
वॉक – आउट्स	3
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	4
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	10
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन	19
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	19
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	46
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	48
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन पर चर्चा (पुनरारम्भ)	49
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	50

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 01 मार्च, 2017 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

वॉक–आउट्स

(i)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, उस पर आपने सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया, जिसके लिए हम सभी सदस्यगण आपके आभारी हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से हर बात का गोल मोल करके जवाब दिया गया है। सरकार के दिए गए जवाब से हमारी पार्टी के सदस्य बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार से जो–जो सवाल पूछे थे उनमें से किसी एक का भी जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया गया है इसलिए इण्डियन नैशनल लोकदल वॉक–आउट कर रही है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, अभी प्रैस के प्रतिनिधि सदन की कार्यवाही नहीं देख रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, प्रैस के प्रतिनिधि सदन की कार्यवाही देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस स्थगन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने के प्रोटैस्ट में सदन से वॉक–आउट कर रहे हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य राज्य में विभिन्न स्थानों पर जाट समुदाय के अनिश्चितकालीन धरनों से संबंधित उनके स्थगन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए उत्तर से संतुष्ट न होने के विरूद्ध विरोध के रूप में वॉक–आउट कर गए।)

(ii)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में कहना चाहता हूँ कि आपने स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी फिराखदिल्ली से सारी बातें सुनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेहनतकश लोग विधान सभा की ओर टक–टकी लगाए हुए हैं। उनको उम्मीद है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस समस्या का समाधान निकालेंगे।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे विकल्प दे दिए हैं और यह भी कह दिया है कि सभी दल आपस में मिल बैठकर समस्या का समाधान निकाले।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह आधा अधूरा जवाब था। यह कोई समस्या के समाधान का रास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसके समाधान का रास्ता नहीं निकला तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं समाज के ताने–बाने को ठेस लगेगी और हजारों साल से चल रही प्रदेश की संस्कृति पर भी ठेस लगेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने सुझाव दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में पांच मंत्रियों और सरकार के ऑफिसर्ज के साथ एक कमेटी गठित की जाये। उस कमेटी में आंदोलनकारियों के नेताओं को आमंत्रित किया जाये और इस समस्या का समाधान निकाला जाये। वह काम सरकार ने नहीं किया है इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सदन से वॉक–आऊट कर रही है। कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक लोगों के साथ और शांतिपूर्वक धरने के साथ खड़ी है।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य राज्य में विभिन्न स्थानों पर जाट समुदाय के अनिश्चितकालीन धरनों से संबंधित उनके स्थगन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए उत्तर से संतुष्ट न होने के विरूद्ध विरोध के रूप में वॉक–आउट कर गए।)

.....

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक बात कहना चाहती हूं। मैंने आपको अपनी पार्टी की तरफ से ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया हुआ है। आप उसके फेट के बारे बताएं। यह ऐडजर्नमैंट मोशन ग्वाल पड़ाही के बारे में है जो बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इसमें करोड़ों रूपये इधर–उधर करने की कोशिश की गयी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का नाम शामिल किया गया है। उनके नाम से यह काम करने की कोशिश की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला है जिसके ऊपर पूरे सदन को चर्चा करनी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ सकें। इस बारे में मुख्यमंत्री जी बतांए कि ये आडर्ज उन्होंने जारी किये हैं या फिर किसी और अधिकारी ने किये हैं। जिस अधिकारी ने ये आडर्ज किए हैं क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष जी, आपके पास भी सारे सबूत हैं आप सब जानते हैं कि यह मुद्दा पूरे एक महीने से सभी अखबारों की हैडलाईन पर छाया हुआ है। यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की जीरो टॉलरैन्स की नीति है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, किरण जी, मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं कल सुबह आपको इस एडजर्नमैंट मोशन का फेट बता दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरीः सर, आप मुझे हर रोज टाल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, मैने यह कल देखा नहीं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, आपने कल कहा था कि इस मुद्दे को कल सुबह टेक–अप करेंगे आज आपने कहा कि इसको दोपहर बाद करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि इस पर कल सुबह विचार करेंगे। यह बहुत संगीन मामला है और सब जानते हैं कि सारा हरियाणा इसके उपर टकटकी लगाये हुए बैठा है। किस तरह से इस विषय पर लीपापोती करके भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के नाम से इस मामले में गड़बड़ी की गयी है और जो क्वासी–ज्युडिशियल ऑफिसर जिसने यह आर्डर पास किया है वह भी यह बात कह रहे हैं कि हम तो उच्च अधिकारियों की डायरैक्शन के अनुसार यह काम कर रहे हैं। मुझे इस मामले में सारे तथ्य सामने लाने हैं इसलिए आप मुझे इसका फेट बताएं ताकि मैं इसके लिए अपनी तैयारी कर सकूं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, इसके फेट के बारे में मैं आपको कल प्रश्न काल के बाद बता दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह 450 एकड़ जमीन का मामला है। आप इस मामले पर कल चर्चा करना चाहते हैं। फिर कल ही कर लेना पर इसको कल से आगे न बढायें।

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं आपको इसका फेट कल तक बता दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप 2 दिन से मुझे टाल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल सुबह आपको इसका फेट देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या कल आप इस एडजर्नमैंट मोशन पर चर्चा करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः नहीं, कल इसको डिस्कस तो नहीं कर पायेंगे परन्तु मैं आपको टाईम अवश्य दे दूंगा। मैं एक बार इसको देख लेता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसको भेजे हुए 4 दिन हो गये हैं लेकिन आप हर सिटिंग में इसको आगे बढाते जा रहे हैं। प्रैस वाले यह देख रहे हैं वे इसका क्या अर्थ निकालेंगे।

श्री अध्यक्षः वे सब यही सोच रहे हैं कि यह सरकार किसी भी विषय पर बहस कराने के लिए तैयार है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार डर रही है कि असलियत सामने आ जाएगी। आपके विधायकों ने यह बात उठायी है वह बेचारे तो आएंगे ही नहीं। यह काम हमको ही करना पड़ेगा। आप यह ज्यादती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैनें कल इसको देखा नहीं क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था। मैं कल इसका फेट आपको बता दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, कल बताने का क्या मतलब है।

श्री अध्यक्षः बहन जी, यह ऐडजर्नमैंट मोशन स्वीकार है या नहीं यह तो बताना पड़ेगा?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, आपने 4 बार इसी सदन में इस विषय को टाला है आज सुबह वाली बैठक में आपने कहा कि इसको दोपहर को ले लेंगे। कल आपने कहा कि कल देख लेगें। परसों आपने कहा कि कल ले लेंगे । अब इससे बात नहीं बनेगी। यह ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरे के पूरे ग्वाल पहाड़ी इलाके को बेचने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, एक दिन में एक एडजर्नमैंट मोशन ही आ पायेगा दो एडजर्नमैंट मोशन एक ही दिन में नहीं लाये जा सकते।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस जमीन को इस तरह से बेचने की कोशिश की जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री जी का नाम भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, एक दिन में एक ऐडजर्नमैंट मोशन ही आएगा। आपने एक पर डिस्कशन कर ली है। दूसरा ऐडजर्नमैंट मोशन कल लिया जाएगा इसलिए कल मैं आपको इसके फेट के बारे में बता दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, इसका मतलब आपने इस ऐडजर्नमैंट मोशन के लिए कल का दिन तय कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, मैं यह कह रहा हूं कि उसका कल ही तो निर्णय लेना है। मैं आपको कल सुबह इसका फेट बता दूंगा। आज तो आपका एक ऐडजर्नमैंट मोशन स्वीकार कर ही लिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, केवल निर्णय नहीं, बल्कि कल आप इस मुद्दे पर चर्चा करवा दीजिएगा। अध्यक्ष जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो यदि कल नहीं आया तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी की बात तो छोड़िये, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, कल मैं इसका निर्णय दे दूंगा।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो तो आप उसको टाल देते हो।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा टाला नहीं गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम लोग आज आपके आश्वासन पर बैठ रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : किरण जी, आप बड़ी जल्दी थक गई।

श्रीमती किरण चौधरी : चौटाला जी, मैं थकी नहीं हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : तो फिर आप आज ही अध्यक्ष महोदय से हां करवा ही लो।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए कल के लिए हां कर ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, मैं आपके ही पक्ष में हूं इसलिए मैं किसी और को खड़ा होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कल आपकी पार्टी के सदस्यों को सदन में खड़े कराऊंगा तब जब आपके पूरे 14–15 लोग होंगे। (शोर एव व्यवधान) बहन जी, इस समय आपके 7 लोग बैठे हैं और इन में से कादियान साहब भी आपके साथ नहीं हैं, हालांकि वे बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब भी आपकी पार्टी के 11 लोग नहीं हुए हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, ये तो पार्टी का मसला है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, जो नियम है, उसको तो मानना ही होता है। जो नियम है उसके अनुसार ही हम चलेंगे । अभी तो आपकी पार्टी के 8 सदस्य सदन में हैं जबकि नियमों के तहत ऐडजर्नमैंट मोशन को स्वीकार करने के लिए 11 लोगों का समर्थन चाहिए। (रूल बुक को दिखाते हुए) इसमें लिखा है कि इसके लिए 11 लोगों का समर्थन चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप कल इस ऐडजर्नमैंट मोशन को टेकअप कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं रुल्ज को थोड़ा सा पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि यदि कम–से–कम 11 सदस्य खड़े हो जाएं, तब अध्यक्ष सूचित करेगा कि ऐडजर्नमैंट मोशन की अनुमति दी गई है। (शोर एवं व्यवधान) मैं नियम का पालन तो करूंगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये सारी प्रैस देख रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप हमारी मंशा देखो। आपके साथ 11 सदस्य नहीं हैं उसके बावजूद भी हम यह कह रहे हैं कि आज इस विषय को न रखो। कल जब पूरे सदस्य मौजूद होंगे तब इस विषय को रखना लेकिन आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो। सरकार इस पर बहस कराना चाहती है। आपसे किसने कहा है कि हम बहस नहीं कराना चाहते हैं, हम तो बहस कराना चाहते हैं। अभी आपकी पार्टी के 11 मैम्बर्ज सदन में मौजूद नहीं हैं इसलिए आपका यह ऐडजर्नमैंट मोशन कैंसिल हो जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरे पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम कल हाउस में लेकर आयेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातें आधारहीन हैं अर्थात् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी आधी अधूरी बातों का जिक्र है जिसकी वजह से सच्चाई को छुपाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें सही बातों का जिक्र किया गया होता तो मैं सौ फीसदी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आधी अधूरी बातों का जिक्र है इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा एस.वाई.एल कैनाल का है। स्पीकर महोदय, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हमारे प्रदेश की जीवन–रेखा एस.वाई.एल नहर के बारे में 10 नवम्बर को एक बड़ा फैसला किया था। उस फैसले में उन्होंने लिखा था कि केंद्र की सरकार एस. वाई.एल नहर को बना करके हरियाणा के हिस्से का पानी उसको देने का काम करेगी। इस इशू को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सर्व दलीय बैठक भी बुलाई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पानी का बंटवारा कब हुआ क्योंकि यह आज का मामला नहीं है । देश आजाद होने के बाद वर्ष 1950 से लेकर 1954 तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में पानी का बंटवारा नहीं हुआ था । उसके बाद हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में 1955 में नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था । उस वक्त भी ये बातें रखी गई थी कि हरियाणा और पंजाब में पानी का बंटवारा किस प्रकार से हो । सिंधु जल समझौता 19 दिसम्बर, 1955 को हुआ और बाकी नदियों का जल समझौता 1960 में हुआ । भारत के हिस्से में पूर्व की नदियां सतलुज–ब्यास और रावी का पानी तथा पाकिस्तान के हिस्से में तीन नदियां आई थी जिनमें चिनाव, झेलम आदि नदियां हैं । इस तरह से दो नदियों का पानी हमें मिला और तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला । भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस समय नदियों का समझौता हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपये देकर दो नदियों का पानी अपने हिस्से में लिया था । उस समय हरियाणा को पानी देने के लिए सिंचाई विभाग की दो समितियां बनाई गई

थी । एक विकास समिति और दूसरी खाद्य समिति बनाई गई थी । अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस.वाई.एल. नहर का सवाल है । इस नहर की लम्बाई 212 कि.मी. है। इसमें से 91 कि.मी. नहर हरियाणा में बननी थी और 121 कि.मी. नहर पंजाब की सीमा में बननी थी । एस.वाई.एल. नहर को लेकर कई बार विधान सभा में भी और बाहर भी बयान बाजी होती रही । अनेकों दफा एस.वाई.एल. नहर को लेकर लोगों ने टिप्पणियां की और अपनी पीठ थप–थपाई कि उन्होंने इस नहर का कार्य करवाया है । अध्यक्ष महोदय, विकास समिति और खाद्य समिति ने रावी–ब्यास का अधिकतर पानी हरियाणा को देने की सिफारिश की थी । आज के दिन सिंचाई विभाग के सर्वे के मुताबिक हरियाणा को 36 मिलियन एकड़ फीट पानी की जरूरत है और भाखड़ा तथा यमुना के माध्यम से केवल 14 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज के दिन यमुना और भाखड़ा नहरों से हमें बढ़कर पानी नहीं मिल सकता । आज के दिन हमें 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की और आवश्यकता है। सतलुज–ब्यास का पानी हमें मिलना है । वह पानी हमारे दक्षिणी हरियाणा के जिलों में आता है । जिनमें खास करके भिवानी, हिसार, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुरूग्राम और मेवात भी शामिल है। जहां–जहां से यमुना से नहरें निकाली गई हैं अर्थात जहां–जहां से यमुना का पानी लाकर किसी जिले को दिया गया है उन सभी जिलों में यानि करीब 12 ऐसे जिले बनते हैं जहां पर सतलुज–ब्यास नदी का पानी जाता है। अगर वह पानी हमें नहीं मिलता है तो मानकर चलें कि आज पानी के मामले में हमारे हरियाणा प्रदेश की जो दशा है, आज जो पानी हमें मिल रहा है और जितने पानी की आज हमें जरूरत है और सरकार पानी के मामले में जिस प्रकार से निर्णय ले रही है इस सबसे आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि पानी के बंटवारे के बाद केवल ये दो ही समितियां ही नहीं बनी बल्कि सन् 1971 में एक कमेटी बनी जिसको योजना मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद धर की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस कमेटी ने सन् 1973 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश को 25.4 मिलियन एकड़ फीट पानी टोटल पानी में से दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया गया। इसी प्रकार से जनवरी, 1985 में जो टोटल पानी पंजाब तथा पैप्सू के लिए आंका गया था वह 7.20 मिलियन एकड़ फीट पानी था, जम्मू तथा कश्मीर के लिए 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी था, राजस्थान के लिए 0.8 मिलियन एकड़ फीट पानी रखा गया था। उस समय जो सतलुज और ब्यास नदी में पानी की टोटल उपलब्धता थी वह थी 15.85 मिलियन एकड़ फीट। इस पानी का जो

बंटवारा उस वक्त किया गया था वह जैसा मैंने आपको बताया उसके अनुसार सभी सम्बंधित राज्यों के हिस्से के तौर पर किया गया था। इसके बाद फिर एक कमेटी बना दी गई थी जिसका नाम श्री राम कमेटी था। उस कमेटी ने हरियाणा प्रदेश के बारे में कहा था कि इसमें से 42 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा को दिया जाये और 28 लाख एकड़ फीट पानी पंजाब के हिस्से में छोड़ दिया जाये अर्थात पंजाब को दे दिया जाये। इस कमेटी की सिफारिशों को भी पंजाब सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि आप इस मामले को किसी प्रकार से सुलझाने का काम करें लेकिन वे भी इस मामले को सुलझाने में असफल रहे। ये सारी बातें मैं सारे सदन को इसलिए बता रहा हूं ताकि यह क्लीयर हो जाये कि इस पानी के बंटवारे को लेकर के कितनी बार समितियां बनाई गई और कितनी बार इन समितियों की सिफारिशों को पंजाब सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा 02 मार्च, 1976 को फिर इस सम्बन्ध में एक फैसला ले लिया गया । उस समय जो वहां पर पानी की उपलब्धता देखी गई वह भी 15.85 मिलीयन एकड़ फीट पानी ही माना गया था। उस वक्त फिर जब भारत सरकार की तरफ से बंटवारा किया गया उस बंटवारे में पंजाब को 3.50 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया था। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश को भी 3.50 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया था। इसमें से दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया था। राजस्थान को 0.8 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया था। जम्मू व कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया था। यह बंटवारा सन् 1973 के अंदर हुआ था। इस बंटवारे के मुताबिक हरियाणा प्रदेश को 3.50 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था लेकिन तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा इस समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया गया। इन्होंने यह समझौता भी नहीं माना । उसके बाद फिर एक कमेटी बनी जिसका नाम वधवा कमेटी रखा गया। इस कमेटी ने भी हरियाणा को 48 मिलियन एकड़ फीट पानी देने की सिफारिश की और पंजाब को 48 मिलियन एकड़ फीट पानी देने की सिफारिश की। पंजाब की तत्कालीन सरकार ने इस समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया। अब मैं अगली बात बताता हूं भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 1981 को इसी पानी के सम्बन्ध में एक समझौता और किया। इसमें पानी की जो उपलब्धता थी वह बढ़ी। जब पानी की उपलब्धता बढ़ी तो हरियाणा के हिस्से के पानी की मात्रा भी 15.85 मिलियन एकड़ फीट से बढ़कर 17.17 मिलियन एकड़ फीट हो गई। इस प्रकार से पानी बढ़ गया और पानी बढ़ने के बाद जब दोबारा से उस पानी का बंटवारा किया गया तो फिर हरियाणा के साथ भेदभाव किया गया। उस समय पंजाब में भी, हरियाणा में भी और केन्द्र में भी तीनों जगह

कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस कांग्रेस सरकार में यह भेदभाव हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया । उस समय पंजाब को 4.22 एम.ए.एफ. पानी दे दिया गया तथा हरियाणा को 3.50 एम.ए.एफ. पानी दिया गया । दिल्ली और राजस्थान का हिस्सा भी जितना था उतना ही रख दिया गया तथा वह बढ़ा हुआ सारा का सारा पानी पंजाब को मिल गया । ज्यादा पानी मिलने के बावजूद भी पंजाब ने उस समझौते को मानने से इन्कार कर दिया । उसके बाद 5 नवम्बर, 1981 को पंजाब की विधान सभा में प्रस्ताव पास किया गया तथा उस वक्त 1981 तक के जितने भी जल समझौते थे उनको रद्द कर दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समझौता पहली बार रद्द नहीं हुआ है बल्कि 1981 में भी रद्द हो चुका है । उसके बाद 30 जनवरी 1987 को न्यायमूर्ति श्री बी.बी. सिंह की अध्यक्षता में इराडी कमीशन बनाया गया जिसके अनुसार पानी की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ गई थी। पहले जहां 17.17 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध बताया गया था वहीं अब 18.28 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध बताया गया । चाहे यह बारिश की वजह से हुआ हो या और किन्हीं कारणों से रहा हो लेकिन पानी की उपलब्धता पहले से अधिक बढ़ गई थी। उसके बाद जब फिर बंटवारा हुआ उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार तीनों जगह पर थी। पंजाब को तो पानी बढ़ा कर दे दिया गया। पहले जहां पंजाब को 4.22 एम.ए.एफ. पानी मिलना था वहीं अब पंजाब को 5.00 एम.ए.एफ. पानी दे दिया गया। इसमें हरियाणा का भी थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा जिसके तहत 3.50 एम.ए.एफ. से 3.83 एम.ए.एफ. कर दिया गया। बाकी बढ़ा हुआ पानी सारा पंजाब को दे दिया गया तथा उस समय भी केन्द्र की सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की अनदेखी की गई। यह जो समझौता हुआ उसको भी पंजाब की सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया। उसके बाद जब भी इस तरह के समझौते हुये उनको पंजाब सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया। अब यह पानी कैसे आये उसके लिए फिर चौधरी देवी लाल जी की तरफ से प्रयास किये गये। जब हरियाणा और पंजाब दो अलग–अलग प्रदेश बने थे तो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए एक नहर बननी थी। उस नहर का निर्माण मुंड की तरफ से किया जाना चाहिए था लेकिन इस नहर का निर्माण मुंड की तरफ से न करके टेल की तरफ से किया गया । वर्ष 1966 से लेकर 1977 तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा । इन 11 वर्षों में ज्यादातर समय तक मुख्यमंत्री स्व0 चौधरी बंसी लाल जी रहे । अगर वे चाहते कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले तो फिर 100 फीसदी उस नहर का

निर्माण वे मुंड से करते । इसको जहां से हरियाणा के लिए पंक्चर होना था वहां से न बनवा कर टेल की तरफ से शुरू करवा दिया ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । सारी जनता और सारा प्रदेश जानता है कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य चौधरी बंसी लाल जी ने करवाया था । उस समय चौधरी बंसी लाल जी प्रदेश के मुख्यमत्री थे तो बसों में लोगों को बैठा कर वहां पर ले जा कर दिखाया गया था कि किस तरह से खुदाई का काम हो चुका है । अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय बाद उनकी सरकार चली गई और नई सरकार आ गई । यदि इन्होंने राजीव लौंगोवाल अकोर्ड को माना होता तो आज हरियाणा को उसके हक का पानी मिल गया होता । आज जिन लोगों का पंजाब के अकाली दल के साथ भाईचारा है उसके कारण ही हरियाणा को उसके हितों से वंचित किया गया । चौधरी बंसी लाल जी के बारे में सभी जानते हैं कि वे एक लोहपुरूष ही नहीं बल्कि एक विकास पुरूष थे जिन्होंने हरियाणा के विकास की नीव रखी । अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो तथ्य रख रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं और बेबुनियाद हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी जी ने बड़े जोर–शोर से कहा कि चौधरी बंसी लाल जी ने 95 प्रतिशत नहर बनवाई थी ।

15:00 बजे

श्रीमती किरण चौधरी :अध्यक्ष महोदय, आज मैं इसकी डिटेल लेकर नहीं आई इसलिये मैं आज इस मुद्दे पर नहीं बोल रही हूं । मैं चौधरी बंसी लाल जी की सारी चिट्ठियां लाकर अवश्य दूंगी जो उन्होंने वाजपेयी जी को और सैंटर गवर्नमैंट को लिखी थी ।

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आप कल अपनी स्पीच के समय यह चिट्ठियां दे देना ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें उनकी चिट्ठियों की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वह सबके सामने है । 19 दिसम्बर, 1991 के अन्दर इसी विधान सभा में एस.वाई.एल. नहर पर चर्चा हो रही थी । हमारा और चौधरी बंसी लाल जी का कोई राजनैतिक तालमेल नहीं था । उन्होंने स्वयं इस विधान सभा के अन्दर खड़े होकर कहा था कि हमें तथ्यों से परे नहीं जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, चाहे उस समय की विधान सभा की कार्यवाही को निकाल कर देख लिया जाए । अगर बहन किरण चौधरी जी ने वह कार्यवाही नहीं देखी तो उनको लाईब्रेरी में जाकर

उसको जरूर पढ़ना ताकि उनको सारी बातों की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए ।

श्रीमती किरण चौधरी :अध्यक्ष महोदय, मुझे उनके बारे में सारी जानकारी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने खुद विधान सभा में यह बात कही और वह कहीं न कहीं एस.वाई.एल. नहर को लेकर अपनी राजनैतिक ताकत दिखा रहे थे । उस समय चौधरी बंसी लाल जी ने खड़े होकर यह कहा था कि हमें तथ्यों से परे नहीं जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अगर इस एस.वाई.एल. नहर की खुदाई का काम और इस नहर के पुलों का निर्माण किसी व्यक्ति ने करवाया है तो वह चौधरी देवी लाल जी ने करवाया है और चौधरी देवी लाल जी तो उस समय विधान सभा के सदस्य भी नहीं थे । इस नहर के निर्माण में सबसे ज्यादा काम चौधरी देवी लाल जी के समय में हुआ है । यह बात चौधरी बंसी लाल जी ने स्वीकार की है । बहन जी, आप भी यह कागज पढ़िये और पढ़ने के बाद आपकी भी तसल्ली हो जाएगी ।

श्रीमती किरण चौधरी :अध्यक्ष महोदय, कागज तो मैं भी इनको कल दिखा दूंगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये तो पता नहीं कहां से टाईप करवा कर लाएंगी ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, कल आप अपने कागज जरूर पढ़ा देना ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के रिकॉर्ड की बात करता हूं कि विधान सभा के रिकॉर्ड में ये सारी बातें लिखी हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर बहन जी की तसल्ली नहीं हो रही तो आप अपने किसी एक अधिकारी को कहो कि वह रिकॉर्ड को निकाल कर ले आए और आप उसको पढ़कर के बता दो कि उन्होंने क्या कहा था । इसके बारे में श्री राम बिलास शर्मा जी को भी पता है कि वर्ष 1991 में चौधरी बंसी लाल जी ने विधान सभा में यह बात मानी थी या नहीं । उन्होंने माना था कि चौधरी देवी लाल जी के समय में एस.वाई.एल. नहर की खुदाई का काम और पुलों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ था ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज का पूरा सत्र माननीय विपक्ष के साथियों के जिम्मे है । चौधरी अभय सिंह चौटाला को पिछली सिटिंग में आपने 1 घण्टा 18 मिनट बोलने का समय दिया था । मैं सदन में बताना चाहता हूं

कि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा में बहुत काम किया है। एस.वाई.एल. नहर के मामले में (शोर एवं व्यवधान) गंगवा जी बात यह है कि थारो अनुभव महारो जितनो नहीं है । वर्ष 1991 में चौधरी बंसी लाल जी थे, हम थे और करण दलाल जी थे अब दलाल जी के पैर में थोड़ी चोट लगी है इसलिये वह कहीं गये हुए हैं । उस समय जो ये बड़े लोग थे इनके बारे में कोई विवाद ही नहीं है । कल अभय सिंह जी कह रहे थे कि आप बात को घुमा देते हो । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने इस बात को स्वीकार किया था ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने 95 प्रतिशत एस.वाई. एल. कैनाल का निर्माण करवाया था। राम बिलास शर्मा जी, आपने तो वह समय देखा है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सारे सदन को बताना चाहूँगा कि चौधरी बंसी लाल और हमारे कार्यकाल के दौरान बहन किरण जी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुआ करती थी। (हंसी व विघ्न) यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हरियाणा की एक बहन दिल्ली विधान सभा की डिप्टी स्पीकर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दो–दो प्रांतों को संभालने का अनुभव है। दो प्रांतों को संभालने का अनुभव किसी अन्य के पास नहीं है? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः किरण जी, इस बात को तो हम पहले से ही मान रहे हैं। आपने जो बात कही है, उस बारे में तो मैं समय–समय पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को चेताता रहता हूँ। (हंसी व विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, अनुभव होने के कारण ही तो किरण जी कांग्रेस पार्टी में चिंता का कारण बनती जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहूँगा कि श्री दुर्गा दत्त अत्री, पूर्व विधायक स्पीकर गैलरी में विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं, हम पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी किरण जी कह रही थी कि एस.वाई.एल. कैनाल को बनवाने का 95 प्रतिशत काम तो चौधरी बंसी लाल जी द्वारा किया गया था, उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि यदि यह नहर 95 प्रतिशत हैड की तरफ से बनाई जाती तो निःसंदेह आज सारा सदन चौधरी बंसी लाल जी को बधाई देता। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने तो कभी नहीं सुना कि नहर को केवल हैड की तरफ से ही बनाया जाना जरूरी होता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है बहन जी ने अपना ज्यादातर समय तो दिल्ली में ही बिताया है, जिसकी वजह से इनको पता नहीं है कि नहर का पानी का बहाव हैड से ही शुरू होता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब आप बैठिए, जब कल आप राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा करेंगी तब आप अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से तो सदन का सारा समय खराब हो जायेगा। वैसे देखा जाये तो किरण जी, सत्ता पक्ष की तरफ से तो आपकी तारीफ ही की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यदि चौधरी बंसी लाल जी के बारे में सदन में कोई गलत बात कहेगा तो सीधी सी बात है मैं चुप रहकर टिकने वाली नहीं हूँ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनको टिक कर बैठना भी नहीं चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, यह टिक कर के क्यों बैठेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, सदन में चौधरी देवी लाल जी की भी तारीफ हुई है और चौधरी बंसी लाल जी की भी तारीफ हुई है और आपने यह सब होते हुए खुद देखा भी है अतः आप प्लीज बैठिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल की चौधरी बंसी लाल जी ने खुदाई करवाई थी और जब इसका कार्य अंतिम चरण में था तो इसी बीच इनैलो सरकार सत्ता में आ गई। अगर उस समय इनकी सरकार सत्ता में न आई होती तो आज हरियाणा के लोगों को एस.वाई.एल. कैनाल का पानी मिल रहा होता। यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि इनके सत्ताकाल में नहर की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से यह नहर रेत व अन्य दूसरी चीजों से भरती चली गई और नहर खुदवाने का जो मकसद था वह एक तरह से व्यर्थ हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा आप तब बोल लेना। अभय जी अपनी बात रख रहे हैं अतः उन्हें उनकी बात रखने दीजिए और आप अपनी सीट पर बैठिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल एक बहुत ही सीरियस इशू है। किरण जी, इस विषय पर बोलना चाह रही है। अतः जब आपकी तरफ से इनको समय दिया जायेगा तो आप इन्हें इस विषय पर बोलने का पूरा मौका दे देना ताकि यह अपनी पूरी भड़ास निकाल ले लेकिन मेरा सुझाव है कि इस भड़ास को तथ्यों के साथ निकाला जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 1966 से 1977 तक के 11 साल की समयावधि में एस.वाई.एल. कैनाल को केवल और केवल टेल की तरफ से बनाने का काम भिवानी में और विशेषकर तोशाम में किया गया था और टेल की तरफ से निर्माण होने की वजह से आज भी इस क्षेत्र में नहरो के पानी को लिफ्ट करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट आधारित सिंचाई व्यवस्था पर आधारित नहरों के रखरखाव पर प्रदेश सरकार को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करने का कारण यह है कि इस रेत बहुल इलाके में जब गर्मी के महीने में अंधेरियां चलती हैं तो नहरें बालू रेत व मिट्टी से भर जाती हैं और इस मिट्टी को खुदाई के जरिये बाहर निकालने में हरियाणा सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अगर एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण हैड की तरफ से किया जाता तो संभव है कि आज जिस एस.वाई.एल कैनाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है तथा आंदोलन करने पड़ रहे हैं, आज उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, वर्ष 1987 से वर्ष 1990 तक चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी। यदि ये लोग एस.वाई.एल. कैनाल पर सीरियस थे तो तब इन्होंने इसकी खुदाई क्यों शुरू नहीं करवाई? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट आफ आर्डर है अतः मुझे बोलने की इजाजत दी जाये और किरण जी को बिठाया जाये। जब मैं सच्चाई बयान करते हुए बंसी लाल का नाम लेता हूँ तो इनको बड़ी तकलीफ होती है और यह मुझे बोलते हुए बाधित करने का प्रयास करती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) शुक्र है कि इस समय कुलदीप जी सदन में नहीं बैठे हैं वरना वह इस मामले को किसी ओर दिशा में मोड़कर विषय को कुछ और ही रूप दे देते। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री(श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, इनैलो पार्टी को अब मौका मिला था नहर खोदने का लेकिन यह तो पंजाब में जाकर सड़क खोद आए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, अभय सिंह चौटाला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और आप प्लीज बैठिए?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही है वह विधान सभा की डिबेट्स में लिखी हुई हैं। आप चाहे तो उन डिबेट्स को निकलवा सकते हैं ताकि किरण जी की तसल्ली हो जाये और सदन के दूसरे सदस्यों को भी पूरी बात का पता लग जाये। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी अन्य सदस्य बेवजह बीच में उठकर मुझे इस विषय में बाधित नहीं करेगा और जो बार–बार उठ कर बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह टिक के आराम से बैठ जायेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग जायेगा कि जो आज यह स्थिति एस.वाई.एल. कैनाल पर प्रदेश में बनी हुई है, यह विकट स्थिति उनकी स्वयं की देन है और वर्ष 1966 से वर्ष 1977 तक की 11 वर्ष की समयावधि में उनके अपने लोगों द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल के लिए वास्तव में सही प्रयास नहीं किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, देश में एमरजैंसी हटने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया था जिसकी वजह से केन्द्र और हरियाणा प्रदेश में दोनों जगह जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी देवीलाल जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि सतलुज व व्यास नदियों का पानी जोकि आज पाकिस्तान में जा रहा है और जिस पानी के लिए

आज भी हमें पाकिस्तान को मुआवजे के रूप में पैसा देना पड़ रहा है, उस पानी को किस प्रकार से हरियाणा में लाया जाये। इसके लिए उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर बादल साहब से बात की । कुछ दलों के माननीय सदस्य रोज बादल परिवार के साथ हमारी दोस्ती की बात करते हैं कि आपकी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है । मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी उनके साथ दोस्ती है, दोस्ती थी और ये दोस्ती आगे भी रहेगी । इस दोस्ती का हरियाणा प्रदेश को उस वक्त बहुत बड़ा फायदा मिला था । (शोर एवं व्यवधान) मैं पुनः कहता हूं कि हमारी बादल परिवार के साथ दोस्ती है । हमारी उनके साथ पारिवारिक दोस्ती है लेकिन हमारा जो राजनैतिक गठबंधन था वह अब खत्म हो चुका है । कुछ दल तो अभी तक पंजाब में उनके साथ गठबंधन किये हुए हैं । कुछ दलों का तो अभी तक भी पंजाब में गठबंधन है । मैं पुनः कहता हूं कि अब हमारा राजनैतिक रिश्ता खत्म हो चुका है लेकिन उनके साथ हमारा पारिवारिक और दोस्ती का रिश्ता आज भी ज्यों का त्यों है और यह रिश्ता हमेशा रहेगा । कुछ लोग इस दोस्ती को अपनी तरफ से तोड़ने के बहुत प्रयास करेंगे लेकिन ये लोग जितने ज्यादा प्रयास करेंगे वह रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा । यह बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारा रिश्ता आज भी ज्यों का त्यों है लेकिन हमारे राजनैतिक रिश्ते हमने उसी दिन खत्म कर दिये थे जिस दिन उन्होंने अपनी असैम्बली में एस.वाई.एल. नहर के संबंध में गलत फैसला लिया था । उन्होंने पिछले साल मार्च महीने की 24 तारीख को एस.वाई.एल. नहर के संबंध में फैसला लिया था । मैं बात कर रहा था कि वर्ष 1977–78 में चौधरी देवीलाल की सरकार यहां पर बनी थी । उसके बाद इस नहर में पानी लाने के लिए प्रयास किये गए । स्पीकर महोदय, चौधरी देवीलाल जी ने प्रयास करके पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मनाया कि कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी आज पाकिस्तान में जा रहा है और उस पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक करके हरियाणा को दिया जाए । इसके लिए उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री महोदय से कहा कि पंजाब में नहर का निर्माण करवाइये और उसके लिए जमीन एक्वायर की जाए । यह बात मैं अपनी तरफ से लिखकर नहीं लाया हूं बल्कि यह रिकॉर्ड की बात है । चौधरी देवीलाल जी ने 20 फरवरी, 1978 को जमीन अधिग्रहण के लिए पंजाब से बात की और 20 फरवरी, 1978 को जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन हो गया । चौधरी देवीलाल जी ने इस जमीन अधिग्रहण के लिए पंजाब को 31 मार्च, 1979 को एक करोड़ रुपये दिए । उसके बाद 30

अप्रैल, 1979 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और उसमें 24 मार्च, 1976 के भारत के फैसले को लागू कराने की अपील की गई । यह भी चौधरी देवीलाल का प्रयास था । जमीन अधिग्रहण करके एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के काम को शुरू करने के लिए पंजाब को पैसा दे दिया गया लेकिन कुछ लोगों ने उसमें रूकावट डालने के लिए प्रयास किये । इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई और उसमें कहा गया कि वर्ष 1976 का फैसला लागू होना चाहिए और उसके बाद वह सरकार चली गई । इसके बाद एस.वाई.एल. नहर का काम रूक गया । उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार केन्द्र में भी थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में भी बन गई तथा कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में भी बन गई थी लेकिन उस समय नहर की खुदाई का जो काम चल रहा था उस काम को रोक दिया गया और उसे फिर कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया । इसे राजनीति की भेंट चढ़ाने के मसले पर अभी किरण चौधरी जी कह रही थी कि जब चौधरी देवीलाल जी भारत के उप–प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने दोबारा प्रयास क्यों नहीं किये ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब वर्ष 1987 में चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किये ? किरण चौधरी जी, यह बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं । अतः आप इसको ध्यान से सुन लेना । 20 फरवरी, 1991 को जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त हमारे हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मास्टर हुकम सिंह जी थे । उन्होंने बाकायदा तौर पर उस समय के देश के प्रधानमंत्री चंद्र शेखर जी को एक चिट्ठी लिख करके उनसे ऑर्डर करवाया कि इस नहर का निर्माण किया जाए क्योंकि उस समय कोई कानूनी अड़चन नहीं थी । नहर की खुदाई करने के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से कोई रूकावट नहीं थी । उसका काम केवल और केवल आतंकवाद की भेंट चढ़कर रूका हुआ था । चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसका काम पुनः शुरू करवाने के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर चंद्र शेखर जी से मिले और इसके निर्माण करने का कार्य बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे लगवाया । यह ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः बॉर्डर पर सड़क बनाने का काम करती है और मिलिट्री के नये–नये रास्ते तैयार करती है । उन्होंने इस काम को बी.आर.ओ. के जिम्मे लगाकर इस काम की जिम्मेवारी तय की थी लेकिन बी.आर.ओ. इस पर काम शुरू करने वाला ही था कि उस दौरान वह सरकार गिर गई । सरकार गिरने के बाद चुनाव हुए और कांग्रेस

पार्टी की सरकार बनी। अध्यक्ष महोदय, जो ऑर्डर उस समय हुआ था, उसको फिर रोक दिया गया था। कांग्रेस सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश के किसानों को उसके हिस्से का पानी ना मिले उसके लिए रोड़े अटकाने का काम करती रही।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने इनकी सरकार तो नहीं गिराई ।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि सरकार गिराने के भी बहुत प्रयास किए गए थे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चौधरी बंसी लाल ने विधान सभा में यह माना था कि नहर के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयास किया है तो सिर्फ चौधरी देवी लाल ने किया है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 को प्रदेश के अंदर नहर के शेष काम को पूरा करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया था। अध्यक्ष महोदय, नहर के काम को चालू करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी लेकिन सरकार बदलने के बाद काम को रोक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में अगली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई। अगली हियरिंग में डेट–टू–डेट नहर के पानी को कैसे लाया जाये इसके लिए प्रयास किए गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रयास से दिनांक 15 जनवरी, 2002 को सफलता भी मिली। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.वाई.एल. कैनाल के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला हरियाणा के हक में दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के तुरंत बाद नहर का निर्माण कैसे हो इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, उस पत्र में यह भी लिखा गया कि पंजाब सरकार भी एक वर्ष के अंदर इस नहर को बनाने का काम पूरा करें लेकिन एक वर्ष में पंजाब सरकार ने इस नहर को बनाने का काम पूरा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पंजाब प्रदेश में भी कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी की यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पंजाब प्रदेश में कैप्टन की कांग्रेस सरकार ने पानी को कैसे रोका जाये उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिव्यू पैटीशन डालने का काम किया। रिव्यू पैटीशन डालने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय का दूसरा फैसला दिनांक 4 जून, 2004 को हरियाणा के पक्ष में आया। उस फैसले में भी वही बात आ गई थी जो बात पहले आई थी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार कहीं ना कहीं अपनी

पीठ थपथपाने का काम करते रहे और कहते रहे कि राजीव लौंगोवाल समझौते को नहीं माना गया जिसकी वजह से आज तक हरियाणा को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल सका। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, यदि सदन में उपस्थित होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या आपने राजीव लौंगोवाल समझौते की सभी धाराओं को बारीकी से पढ़ने का काम किया है? उस समझौते में कौन–कौन सी बातों का जिक्र किया गया यदि इन बातों को हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी के सदस्य पढ़ लेते तो शायद कभी भी अखबारों में लोगों के सामने खड़े होकर यह बात नहीं कहते कि चौधरी देवी लाल ने धारा 7 और 9 का विरोध नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, राजीव लौंगोवाल समझौते के अनुसार धारा 7 में साफ लिखा हुआ था कि चण्डीगढ़ पंजाब को सौंपी जाये इसलिए चौधरी देवी लाल ने धारा 7 का विरोध नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी धारा 12 और 9 का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उस धारा के अनुसार हमारा जो पानी का हिस्सा था वह कम किया जा रहा था और पंजाब को ज्यादा दिया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह लड़ाई लड़ने वाले चौधरी देवी लाल जी अकेले नहीं थे बल्कि उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, डॉ. मंगल सैन, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे और विधान सभा के उनके दूसरे साथी थे। उन्होंने भी इस लड़ाई में अहम योगदान दिया था। उन्होंने भी राजीव लोंगोवाल के समझौते के खिलाफ विधान सभा से इस्तीफा दिया था। ये दोनों भाई डा0 साहब तथा दांगी साहब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे तथा उस वक्त चौधरी देवीलाल के साथ उस आंदोलन में शामिल थे। आज पता नहीं इनको किस बात का दर्द हो रहा है कि चौधरी देवीलाल ने वह आंदोलन क्यों किया और क्यों हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ी। इनको तो यह कहना चाहिए कि अगर ये चौधरी देवी लाल जी के साथ उस समय नहीं होते तो आज ये दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। मैं जो बात कह रहा हूं वह सौ फीसदी सही है।

श्री अध्यक्षः आनंद सिंह दांगी जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, हमने डटकर लड़ाई लड़ी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं, आज हम किस मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ें, क्या फैसला है तथा सरकार क्या करना चाहती है हमें यह बात

करनी चाहिए। जब से हरियाणा बना है तब के इतिहास पर आज बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन को सारी बातों की जानकारी होनी जरूरी है। इस नहर के निर्माण के रूकावट में कौन–कौन लोग थे। इस बात का जिक्र जरूर सदन के अन्दर होना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे नये सदस्य इस सदन में चुनकर आएं हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों भी उस समय हमारे साथ थे।

डा0 पवन सैनीः स्पीकर सर, चौधरी साहब की बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। चौधरी देवी लाल जी से उस वक्त एक चूक हुई थी अगर उस समय वे वी.पी. सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने के स्थान पर श्री चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवा देते तो दो मसले हल हो जाते, एक एस.वाई.एल. का तथा दूसरा राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन उनको थोड़ा समय मिला और वह सरकार चली गयी। चूक हुई।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, मैं भी इस बारे कुछ कहना चाहती हूं। सन् 1987–90 तक चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी तथा पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। उस समय तो एस.वाई.एल. नहर की कोई खुदाई नहीं हुई थी। सन् 1986 में चौधरी बंसीलाल जी ने इसकी खुदाई करवाई और उसके बाद 1988 के अन्दर पंजाब में आतंकवाद था और जो मिस्टर सीकरी एस.ई. इन्चार्ज थे उनकी डैथ हो गयी जिस कारण वहां नहर की खुदाई का काम बन्द हो गया। माननीय विपक्ष के नेता ने यह कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने बी.एस.एफ. की देखरेख में वह खुदाई करवाई। श्री देवी लाल जी वर्ष 1989–90 में डिप्टी प्राईम मिनिस्टर बन चुके थे, इसलिए नेचुरली बी.एस.एफ. के माध्यम से ही नहर की खुदाई करवाई गयी क्योंकि उस समय पंजाब में आतंकवाद की हवा चल रही थी इनका यह कहना कि चौधरी देवीलाल के समय में खुदाई हुई और चौधरी बंसीलाल जी के समय में नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध किया, यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह बात चौधरी बंसीलाल जी ने कही है। मैं यह नहीं कहता।

श्री रामबिलास शर्माः स्पीकर सर, मुसीबत यहां यह हो रही है कि कोई अपने भूतकाल को लेकर और कोई भविष्य को लेकर यानि सभी सदस्य टैंशन में हैं।

लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो टैंशन में नहीं है। अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1987 में चौधरी देवीलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे नेता डा0 मंगल सैन जी और हम साथ–साथ चले थे। चौधरी देवीलाल चौटाला ने कटड़ा रामलीला (हिसार) से पद यात्रा शुरू की और चौधरी आनंद सिंह दांगी जी ने उस पद यात्रा का महम में प्रवेश करते ही गाजे–बाजे के साथ स्वागत किया और हमें उस यात्रा में रहने का मौका मिला। स्पीकर सर, यह तो हालत की मजबूरी हो जाती है कि आदमी बदल जाता है। डा0 रघुबीर सिंह कादियान 1987 में हमारे साथ कोआप्रेटिव मिनिस्टर थे। यह तो समय बदलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग होते हैं जो दबाव में हर हाल में एक साथ रहते हैं, चेरवती–चेरवती।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो शर्मा जी अपनी कहानी बता रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपकी बात कम्पलीट हो गई है, इसलिए आप बैठिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं किरण जी से कहना चाहता हूं कि जितने समर्थक हम आपके हैं और जितना आदर आपका हम करते हैं, उतना कोई नहीं करता। ये लोग तो आपके खिलाफ अलग से मीटिंग करते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी को कहना चाहती हूं कि मैं इनका कोई खुलासा नहीं करती। मैं इनको कहना चाहती हूं कि जब मेरी और इनकी एक ही बात है तो ये इस तरह की बात को यहां न लेकर आया करें।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जी का मुकाबला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत विद्वान आदमी हैं। ये पढ़े–लिखे हैं और इन्होंने कई सब्जैक्ट्स में एम.ए कर रखी है। ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं लेकिन यहां कई बार मामला कुछ और तरह का आ जाता है। 3–4 दिन पहले मैंने टी.वी पर देखा कि ये हमारी जो दो होनहार बेटियां हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहे थे और बोल रहे थे कि he is our daughters Gita & Babita। (हंसी) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ये मुख्यमंत्री जी को कि भी She is Manohar Lal न कह दें। इस बात का ये जरूर ध्यान रखें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात एस.वाई.एल के मुद्दे पर मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा और उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 12.07.2004 को सभी जल समझौतों को पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने यानी कैप्टन साहब की सरकार ने रद्द करने का काम किया था। अब जब असैम्बली के चुनाव हो रहे थे तो उस असैम्बली के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस की तरफ से पोस्टर छापा गया और उस पोस्टर के अंदर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि चौधरी देवी लाल की और बादल साहब की दोस्ती की वजह से पंजाब में एस.वाई. एल नहर के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ। उसमें यह भी लिखा गया कि बादल साहब ने मुआवजे के रूप में जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनसे मुआवजे के रूप में पैसे भी लिये हैं। उस वक्त में भी हमने तो प्रयास किए जब कांग्रेस कहीं न कहीं इसको राजनीति की भेंट चढ़ा रही थी। आज हमारे प्रदेश में पानी के जो हालात हैं उसके बारे में मंत्री जी जानते हैं। मंत्री जी इस समय सदन से चले गए। आज की तारीख में जो हमें भाखड़ा का पानी मिलता है। भाखड़ा का जो पानी है वह जो राजपुरा के पास पटियाला नदी जो गुजरती है जो नरवाना ब्रांच के नाम से जानी जाती है। वहां पर एक साइफन बना हुआ है और उस साइफन के अंदर 4 बड़े पाईप हैं, जो एक–एक हजार क्यूसिक के करीब क्षमता के पाईप हैं। उनमें से एक पाईप ऐसा है कि जिसकी लम्बाई 120 मीटर है और उस पाईप के अंदर से पानी नहीं जा रहा है और वह पाईप बंद कर रखी है। हमारी सरकार की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या प्रयास हुआ है? अब तक कमाल की बात यह है कि सरकार इस बात का पता नहीं लगा पाई कि उस पाईप के अंदर क्या फंसा हुआ है। अब कहीं कह रहे हैं कि अप्रैल में जाकर के जब बिजाई हो जाएगी, गेहूं की फसल कट जाएगी, अगली फसल के लिए पानी चला जाएगा तो उसके बाद उसको बंद करके उसमें देखेंगे कि उसमें क्या फंसा हुआ है। मतलब सरकार के पास इतने साधनों की कमी है कि उस एक पाईप के अंदर क्या फंसा हुआ है, उस चीज की जानकारी नहीं ले सकी। आजकल तो ऐसे–ऐसे कैमरे हैं जो पानी के अंदर दो–दो, चार–चार, पांच–पांच हजार फीट तक, ऊपर से झांककर सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। मेरी जानकारी में यह बात भी आई थी कि वहां नेवी को बुलाकर यह पता लगाने की कोशिश की गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि कोशिश की है आपने, लेकिन आप अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाये हैं कि उस पाईप से पानी क्यों नहीं जा रहा। क्या

यह दुर्भागयपूर्ण बात नहीं है? हमारे प्रदेश में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उस पाईप के अंदर क्या फसा हुआ है और किस प्रकार से उसको ठीक किया जायेगा, इस बारे में सरकार पता नहीं लगा पाई है । अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में जहां पहले दो हफ्ता नहर चलती थी और एक हफ्ता बंद रहती थी आज वही नहर 32 दिन बंद रहती है और एक हफ्ता पानी मिलता है । यानी एक महीने बाद हमें एक हफ्ता पानी मिलता है ।

कृषि मंत्री(श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 32 दिन नहर बंद रहने के कारण अलग हैं । ऐसा नहीं है कि पाईप बंद होने के कारण कम पानी दिया जा रहा है । कम पानी मिलने का कारण भाखड़ा में पानी का लैवल कम होना है । हमारा भाखड़ा में 9 हजार क्यूसिक पानी का हिस्सा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को 9 हजार क्यूसिक में से 8 हजार क्यूसिक पानी ही भाखड़ा से दिया जा रहा है । उन चार पाईपों से 4 हजार क्यूसिक पानी आता है लेकिन एक पाईप बंद होने के कारण वहां से कम पानी आ रहा है जिसके कारण नहरों में कम पानी दिया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पानी का लैवल कम होने के कारण पीछे से ही कम आ रहा है इसलिए कम पानी दिया जा रहा है । ऐसा नहीं है कि पाईप बंद होने के कारण पानी की कमी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक पाईप बंद होने के कारण पानी कम आ रहा है । सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रही ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पीछे से पानी पूरा नहीं आ रहा । ऐसा नहीं है कि पानी निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही । हम मानते हैं कि एक पाईप बंद है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कम पानी दिया जा रहा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में 32 दिन बाद एक हफ्ता पानी आता है । यदि आज इस तरह के हालात हैं तो गर्मियों में किस तरह के हालात होंगे । गर्मी के दिनों में सरकार लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पायेगी। ये लोग पहले कहते थे कि हर टेल पर पानी पहुंचायेंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि हमारी बैस्ट वाटर मैनेजमैंट वाली सरकार है । हमने गर्मियों में पहले भी पानी दिया था जिसके कारण प्रदेश में धान की फसल भी अच्छी हुई थी और हरियाणा प्रदेश को कृषि ग्रामीण अवार्ड भी मिला था । हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा रहेगी, हम पानी का बैस्ट मैनेजमैंट करेंगे और पूरे प्रदेश में पानी पहुंचायेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जो नहरें हैं उनमें से 225 नहरों की टेल पर एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच रहा और वहां के किसान खेती के लिए तरस रहे हैं । यदि किसी ने टेल पर ढाणी बना ली है तो उसको एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा और वे प्यासे ही मर जायेंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में टोटल 1400 टेल्ज हैं जिनमें से जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा कि 225 टेल्ज पर पानी नहीं पहुंच रहा । इसका कारण यह रहा कि एक बार तो मानसून कमजोर रहा था और एक बार भाखड़ा में पानी का लैवल कम रहा । माननीय विपक्ष के नेता ने हमें सर्टीफिकेट दिया है कि 1400 में से 225 टेल्ज पर पानी नहीं पहुंच रहा, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि हर टेल पर पानी पहुंचायेंगे और वहां से सैल्फी लेकर अधिकारी रिपोर्ट देंगे । इनकी वह सैल्फी कहां गई ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने हमें सर्टीफिकेट दिया है इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिन टेल्ज पर पानी नहीं पहुंच रहा वहां के लोग तरसते हैं कि उन्हें भी पानी मिले लेकिन सरकार ने उनको पानी के लिए तरसाया है । जो टोटल टेल्ज हैं उनमें से पांचवा हिस्सा ऐसा है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे जो जल मार्ग हैं जिनकी सिंचाई विभाग द्वारा पहचान की गई है उनकी संख्या 15404 है । जिनमें से 7500 की हालात बहुत खराब है, उनमें आगे पानी नहीं चलता। यह बात विभाग ने अपने सर्वे में कही है । उनको दोबारा से बनाने के लिए स्कीम बनाई गई है । उनमें आगे पानी नहीं जा रहा है । यह बात विभाग ने अपने सर्वे में मानी है । 125

चैनल और 400 जल मार्गों को भी ठीक करने की योजना सरकार ने बनाई है । इस योजना को सिरे चढ़ाने में जिस ढंग से विभाग काम कर रहा है आप यह मानकर चलें कि इसको पूरे होने में कम से कम 12 वर्ष लगेंगे। अगर 12 वर्ष लगेंगे तो ऐसी स्थिति में उन किसानों की हालत क्या होगी जिनकी ज़मीनें और जिनके गांव इन जल मार्गों के नीचे आते हैं। उन सभी लोगों के लिए इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। इसके साथ ही साथ मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यहां पर इस बात का कई बार जिक्र आया है कि सरकार द्वारा रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध को बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है कि ये बांध बनेंगे और हरियाणा प्रदेश का इतना–इतना फायदा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर जाकर पूरी स्थिति को देखकर आये हैं और वहां का सर्वे करके आये हैं लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों की जमीन इस कार्य हेतु एक्वॉयर की गई है और जिनको इस जमीन के पैसे दिए जाने हैं वे भी अभी तक पूरे नहीं दिये गये हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब तक उन लोगों को पूरे पैसे नहीं दिये जायेंगे तब तक काम कैसे शुरू हो पायेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस स्पीड से सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है ऐसी हालत में यह काम 2025 तक भी पूरा नहीं हो पायेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह बात भी सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कई नहरों में पानी नहीं है जिसकी वजह से वहां के लोगों को अपनी फसल की सिंचाई में परेशानी हो रही है। वहां के और पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के 37 हज़ार से भी ज्यादा किसानों ने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के लिए एप्लाई कर रखा था कि उन्हें ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दे दिये जायें ताकि वे कहीं न कहीं ट्यूबवैल्ज से अपनी फसल की सिंचाई कर सकें लेकिन उनके ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शंज अभी तक पैंडिंग हैं। होना तो यह चाहिए था कि जिस प्रकार से किसानों को नहरों से पानी नहीं मिल रहा है ऐसी हालत में किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज जल्दी से जल्दी दिये जाये लेकिन इसके विपरीत सरकार द्वारा डार्क जोन की आड़ लेकर किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं और उनको यह कहा जा रहा है कि वे अपने इस कार्य हेतु जमा करवाई गई सिक्योरिटी को वापिस ले लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में डार्क जोन कोई आज ही डिक्लेयर नहीं किये गये हैं। सरकार द्वारा डॉर्क जोन के बहाने किसानों को ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन देने से साफ तौर से मना किया जा रहा है। अगर इन 37 हजार किसानों

को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज नहीं मिलेंगे तो उन्होंने जो अपनी जमीन को कहीं उपजाऊ बनाया था वह सारी की सारी बंजर हो जायेगी। वह सारी की सारी जमीन खराब हो जायेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए और किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन देने चाहिएं ताकि किसान उनसे अपनी जमीन की सिंचाई कर सके।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कहने से पहले ही इस मामले में यह निर्णय लेकर तय कर दिया है कि डॉर्क जोन में भी जिनके भी ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज पैंडिंग हैं, जो–जो किसान ये संकल्प पत्र साथ में देंगे कि मैं माईक्रो इरीगेशन से सिंचाई करूंगा तो उन सभी किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज दे दिये जायेंगे। आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यही सही तरीका है ताकि हमारे प्रदेश की जल सम्पदा को सम्भाला जा सके। धीरे–धीरे हम इसको पूरे प्रदेश के लिए लागू करने जा रहे हैं अर्थात हमारी सरकार की यही कोशिश है कि धीरे–धीरे पूरे हरियाणा प्रदेश को माईक्रो इरीगेशन के अंतर्गत लाया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय स्पीकर महोदय, जो बात माननीय कृषि मंत्री जी ने बताई है ये इन्होंने कनैक्शन देने बंद करने का सही तरीका निकाला है। ऐसा करके सरकार ने सारे के सारे हरियाणा का बिजली और पानी बंद करने का सही तरीका निकाला है। स्पीकर सर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो एस.वाई.एल नहर है यह पूरे हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। इस एस.वाई.एल. नहर का माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया । आज भी माननीय मुख्यमंत्री, किसी मंत्री की तरफ से बयान आ जाता है और कहीं न कहीं हमारे दूसरे साथियों की तरफ से भी इस बारे में बयान आते रहते हैं कि हमने इस पानी को लेकर के जो मुहिम चलाई थी कि हम एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए पंजाब जायेंगे, इसको कहीं न कहीं सरकार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजाक के रूप में लेने का काम किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारे साथ बहुत बड़े–बड़े मजाक किये गये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अभय सिंह जी, हमने तो आपकी हौसला अफजाई की थी कि आप नहर की खुदाई करके पानी लेकर आयें हम आपको फूल मालायें

पहनायेंगे। जब आप वापिस आये तो उस समय भी मैंने आपका स्वागत किया था। आपका अभी भी स्वागत है और आपके लिए हमारी फूल मालायें अभी भी तैयार हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर महोदय जी, हमने तो अभय सिंह चौटाला जी के इस कृत्य पर इनको बहुत बड़ी–बड़ी उपमायें दी थी कि भागीरथ पंजाब में गया है और वह एस.वाई.एल. का पानी जरूर लेकर आयेगा। अगर वह पानी के साथ आयेगा तो हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे लेकिन हमारे वह भागीरथ बिना पानी के ही आ गये और उनका स्वागत करने के हमारे अरमान धरे के धरे रह गये।

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय स्पीकर महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो सरकार की जिम्मेदारी थी सरकार ने उसको नहीं निभाया अर्थात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला कर दिया था इसके बाद सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी सरकार ने उसको किसी भी सूरत में नहीं निभाया। मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम भी उस बैठक में गये थे और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे और महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति से किस लिए मिलने जा रहे थे? अगर नहर की खुदाई हमें ही करनी थी तो फिर वह सर्वदलीय बैठक किस लिए बुलाई गई थी। क्यों जा कर राष्ट्रपति से मिला गया और क्यों प्रधानमंत्री से आपने समय मांगा । अगर आप सीरियस होते तो 100 फीसदी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय लेते । मुख्यमंत्री जी, जब केजरीवाल जी ने पंजाब में यह बयान दिया था कि हम हरियाणा को पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे तो आपने तो उसके विरोध में बयान भी नहीं दिया अन्यथा केजरीवाल को तो आप यह बात महसूस करवा सकते थे कि पानी सबके लिए बहुमूल्य चीज है । आप एक दिन एक बयान दे देते कि हम दिल्ली का पानी बंद कर देंगे लेकिन आपने तो बयान भी नहीं दिया । हमने किसी अखबार में आपका बयान नहीं पढ़ा । केजरीवाल को यह बात सोचनी चाहिए कि दिल्ली का जो पानी है वह हरियाणा से हो कर जाता है । आप एक मिनट में उनको अहसास करवा सकते थे । आप 2 दिन ही दिल्ली का पानी बंद कर देते तो केजरीवाल तो आपके आगे आ कर नाक रगड़ता और कहता कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लेकिन आपका तो बयान भी नहीं आया ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल के खिलाफ तो बयान भी दे दिया था और उनको ज्ञान भी दे दिया था जो कि सदन के रिकॉर्ड में आना ठीक नहीं है । उसके बाद उनके बयान भी बदल गये थे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि केन्द्र की सरकार पर दबाव बने और उसके लिए मैं पूरे प्रदेश के 550 से ज्यादा गांवों में गया जहां और जिस–जिस इलाके में एस.वाई.एल. नहर का पानी जाना था वहां जा कर मैंने लोगों से कहा कि जो जिम्मेदारी सरकार की है सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे । हम आपको पानी ला कर देंगे । यह एस.वाई.एल. का पानी केवल पानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जीवन रेखा है और यह पानी लाने के लिए हम सभी लोगों को मिल कर संघर्ष करना पड़ेगा । हमने उसके लिए बाकायदा 23 फरवरी का दिन भी निश्चित कर दिया था कि अगर 23 फरवरी तक यह नहर खोदने का काम शुरू नहीं होगा तो हम नहर खोदने जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम नहर खोदने के लिए अम्बाला से पंजाब की तरफ बढ़े उस समय हरियाणा सरकार की तरफ से पहला बैरियर लगा कर रूकावट डाली गई । मेरा खुद का ट्रैक्टर रोक कर एस.डी.एम. ने आ कर मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप आगे नहीं जा सकते । मैंने उनसे कहा कि इसमें तो एक लाइन भी ऐसी नहीं लिखी हुई है कि हम आगे नहीं जा सकते । सुप्रीम कोर्ट ने तो यह लिखा है कि कानून व्यवस्था बना कर रखना प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है । हम किसी से युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे थे । हम अपनी मांग मनवाने के लिए लाखों की संख्या में वहां गये थे । पहले बैरियर पर हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन लोगों ने पहला बैरियर तोड़ दिया । उसके बाद दूसरे बैरियर पर भी रोकने की कोशिश की गई लेकिन हम तो प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे और यह प्रदेश की सरकार हमें रोकने की कोशिश कर रही थी । हमने दूसरा बैरियर भी तोड़ दिया । उसके बाद तीसरा बैरियर भी तोड़ा गया और उस समय मेरे साथ 12 से 15 हजार लोग थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई अन्दर जाना हुआ कि ये 4 दिन जेल में भी जा आये और जमानत की भी जरूरत नहीं पड़ी और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी सरकार होती तो हमारे खिलाफ मुकदमा अवश्य दर्ज हो जाता । इनको अभी भी तकलीफ है कि क्यों हम हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों हम आगे बढ़ रहे थे इसीलिए ये अब भी इस तरह की बात करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुये । ये तो हरियाणा के विरोधी हैं । अगर ये हरियाणा के हितैषी होते तो ये नहर खोदने में 100 प्रतिशत हमारे साथ चलते । ये ऐसे चेहरे हैं जो इस हरियाणा को बर्बाद करने के लिए सारा दिन बैठ कर योजनाएं बनाते हैं । आज जो हजारों लोग धरनों पर बैठे हुये हैं अगर इनके कारनामे गलत न होते तो आज यह नौबत नहीं आती ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है । सरकार इन्कवायरी करवा ले सारा पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो कहकर हमारा मजाक उड़ाया गया कि वहां जाकर 75 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी हम 71 लोगों ने गिरफ्तारी दी । हमने कम से कम हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ कर गिरफ्तारी तो दी । मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब इस ईश्यु पर अपना जवाब दें तो 100 फीसदी हरियाणा प्रदेश के लोगों को यह जानकारी दें कि पंजाब सरकार के मदन मोहन मित्तल की तरफ से एक प्रस्ताव पंजाब की विधान सभा में आया था कि पंजाब किसी भी राज्य को एक बूंद भी पानी नहीं देगा । उस समय हम सभी इसी विधान सभा में बैठे थे । हमने यहां से उनके खिलाफ एक निन्दा प्रस्ताव पास करके भेजा था और हमारी पार्टी के सभी एम.एल. एज. उनकी असैम्बली में जाकर कह कर आए थे कि आपका जो यह फैसला है वह संवैधानिक नहीं है । आप आज इस तरह का फैसला लेकर हरियाणा प्रदेश के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हो तो आज से हमारे और आपके रिश्ते खत्म हैं ।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, ये तो पंजाब सरकार के चुनाव प्रचार में भी गये हुए थे । **(विघ्न)**

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ पिछले साल की 24 फरवरी से लेकर आज तक एक साल होने जा रहा है अर्थात 11 महीने हो गये तथा कुछ

दिन ऊपर भी चले गये । मुख्यमंत्री जी, इस बीच में आपने एक सर्वदलीय बैठक भी बुला ली थी । जब पंजाब की असैम्बली में यह फैसला आया था उसके बाद क्या आप प्रधान मंत्री जी से मिलकर उनको कह कर आए कि कोई पंजाब की तरफ से ऐसा असंवैधानिक फैसला हुआ है । इस दौरान क्या आपने ऐसे प्रयास किये कि जो पानी हमारे हिस्से में आ रहा था उस पानी में रूकावट के जो इस तरह के असंवैधानिक फैसले लिये जा रहे हैं उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए । आपकी तरफ से इस पर एक भी कोई छोटी–मोटी स्टेटमैंट भी नहीं आई । आप तो उस मामले में पता नहीं क्यों चुप्पी साध गये । आपको जहां हरियाणा के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी वहां आपने उस पर मौन व्रत करके रख लिया । इस बात को लेकर हमें बड़ा खेद हुआ कि हम एस.वाई.एल. की लड़ाई लड़ रहे थे और आपके मंत्री मंडल के सहयोगी कहीं न कहीं उस बात को लेकर इस हरियाणा प्रदेश की लड़ाई में अपना सहयोग देने की बजाए मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे । हम 23 तारीख को पंजाब में गये और मैं आज फिर आप सबको निमंत्रण देता हूं कि अगर आप हरियाणा प्रदेश के हितेषी हैं, तो हमारे साथ चलें । (शोर एवं व्यवधान) हम फिर से 15 मार्च, 2017 को पार्लियामैंट का घेराव करने के लिये जाएंगे और हजारों लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे । हरियाणा प्रदेश के हित की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाए । उसके लिये मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप भी उसमें हमारे साथ चलें और साथ चल कर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं ताकि आपको हरियाणा प्रदेश के हिस्से का एस.वाई.एल. नहर का पानी नहर खुदकर मिल सके । सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछली तारीख पर अपने फैसले में खुलकर कहा था कि यह एस.वाई.एल. नहर 100 फीसदी बनकर रहेगी । इसके लिये आपको दबाव बनाना चाहिए । इसके लिये आपको आगे आना चाहिए । जो अभी यह कह रहे थे कि हमने आपके लिये जलेबियां बना रखी थी, जो कह रहे थे कि हम दूध लेकर आए थे । ये चोकलेट खाकर पैदा हुए थे । इनको शायद इस बात का पता नहीं था कि जो लड़ने जा रहे हैं उन्होंने बाजरे के रोट खाए हैं । अध्यक्ष महोदय, इनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । कोई बीकासुल के कैपसूल की बात कर रहा था । हमें न बीकासुल के कैपसूल चाहिएं और न ही हमें चोकलेट चाहिए । उनको तो तुम खाओ और मौज उड़ाओ । आप बीकासूल्स के कैपसूल और चोकलेट खाकर

आते हो और यहां भाषण देते हो । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद । मैं मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि मैंने हाउस में जो बातें कही हैं वे उनकी जानकारी सदन में दें ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में पूरा इतिहास व पूरे तथ्यों के साथ बात कही है। राजस्थान बार्डर पर स्थित ढाणियों व साथ लगते इलाके लोहारू, महेन्द्रगढ़, नांगल चौधरी, अटेली व रिवाड़ी में पानी का स्तर हजार फुट से भी नीचे चला गया है और इस जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए एस.वाई.एल. कैनाल के पानी की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक याद है आपने भी एस.वाई.एल. कैनाल के पानी की बाबत दसवीं हरियाणा विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति के 8 महीने पहले विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था और इस विषय को लेकर एक जनचेतना यात्रा भी निकाली थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, मैंने दसवीं हरियाणा विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति के 9 महीने पहले विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष जी, आप ठीक कह रहे है। यहा इस अवस्था में मेरे कहने का आश्य यह है कि एक गांव का जो सरपंच है वह अपने कार्यकाल के पूर्ण अवधि के एक दिन पहले भी अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए लिए तैयार नहीं होता है और आपने तो प्रदेश के हितों के ध्यानार्थ 9 महीने पहले विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह दिया है कि हम तो उनकी अगुवानी में भी एस.वाई.एल. के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे आगे बढ़ें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप प्लीज बैठिये और माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल विषय को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी भपेून्द्र सिंह हुड्डा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी तथा सदन के कई अन्य सदस्य राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए गए और

उन्होंने बड़ी ही तन्मयता के साथ बात सुनी और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आ गया और फलस्वरूप आज भारत सरकार एस.वाई.एल. कैनाल के विषय पर बहुत ही गम्भीर हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में मेरा नेता प्रतिपक्ष से एक ही अनुरोध है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए तथा दूध–जलेबी जैसी बातों को परे रखकर, इवेंटबाजी से दूर कि 'एस.वाई.एल. कैनाल का पानी दक्षिण हरियाणा में आयेगा' तथा पार्टी प्रोग्राम्ज से ऊपर उठकर तथा छोटी–मोटी बातों को दूर रखते हुए, हमें विगत में बुजुर्गों द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल के लिए लड़ी गई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हित में काम करना चाहिए। यह अलहदा बात है कि कईं पार्टियों के पास काम नहीं होता इसलिए वह इस तरह के कार्य करते रहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री पिरथी सिंह नम्बरदारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वे सदन में जिस तरह का कटाक्षपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इससे तो यह लगता है कि शायद इनके लिए एस.वाई.एल. कैनाल के पानी का कोई महत्व ही नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पिरथी जी, मंत्री जी ज्ञान की बात कर रहे हैं आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, सदन को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी बलवान सिंह जी को बताना चाहूँगा कि वे सदन के एक नए सदस्य हैं इसलिए उन्हें बात को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बलवान जी, राम बिलास शर्मा जी एक सीनियर मंत्री है। आपको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एस.वाई.एल. कैनाल के विषय पर चर्चा हुई और सबने एकमत से माना कि चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में ईमानदारी से एस.वाई.एल. कैनाल के लिए एक लड़ाई लड़ी गई तथा चौधरी बंसीलाल की रहनुमाई में इस कैनाल का बहुत काम हुआ परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी एक ऐसे वंडरफुल प्राईम

मिनिस्टर हैं जिसने कईं पार्टियों की दुकानें बंद कर दी हैं। इनसे घबराकर उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में दो छोरे एक साईकल पर बैठ गए और वह साईकल पैंचर हो गया। इस वंडरफुल प्राईम मिनिस्टर की वजह से कई पार्टियां मुद्दाविहीन हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार आदमी पर संगति का दोष भी हो जाता है? यह अखिलेश सारे चुनाव में तो ठीक बोलता रहा और बोलते–बोलते उसने गुजरात के गधों की ऐसी चर्चा कर दी कि उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की बात ही बन गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, अब जबकि एस.वाई.एल. कैनाल की बात सदन में चल ही रही है तो इस परिस्थिति में मैं एक बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था क्या वही समझौता आज भी स्टैंड करता है? क्या इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ है। जो आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल के विषय में फैसला आया है उसमें एक बात साफ नहीं झलकती कि किस प्रतिशतता में इस कैनाल का पानी दोनों प्रदेशों को प्राप्त होगा। अतः मैं इस विषय में सरकार के स्टैंड के बारे में जानना चाहता हूँ और यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि हम सबको एकजुटता का परिचय देते हुए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि एस.वाई.एल. कैनाल बनाने की दिशा में सब कुछ क्लीयर हो सके और यह कैनाल जल्द से जल्द बन सके।

श्री अध्यक्षः दांगी जी, आपको इस बात का स्वयं पता चल जायेगा? आप प्लीज बैठिए।

.....

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में सदन को अवगत कराने दें। माननीय सदस्यगण, जैसा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय बिजनेस के अनुसार सोमवार दिनांक 6 मार्च, 2017 को दोपहर बाद वर्ष 2017–18 का बजट पेश करना तय हुआ था उसके बारे में कुछ विधायकों के सुझाव आये हैं जोकि इस प्रकार हैं : –

1. आज दिनांक 01.03.2017 (प्रथम बैठक) में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के कारण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो सकी, इसलिए यदि सदन

सहमत हो तो कल वीरवार, दिनांक 2 मार्च, 2017 को गैर सरकारी कार्य की बजाय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करवा ली जाए ताकि बहुत–से विधायक चर्चा में भाग लेकर अपनी बात कह सके और अगर जरूरत हुई तो थोड़ा बहुत समय बढ़ा दिया जाएगा ।

2. कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय बिजनैस के अनुसार वर्ष 2017–18 का बजट सोमवार, 6 मार्च, 2017 को दोपहर बाद आना है, उसको सोमवार, 6 मार्च, 2017 को ही सुबह 11:00 बजे ले लिया जाए क्योंकि पत्रकार भाईयों का सुझाव है कि दूसरी बैठक में बजट आने के कारण समाचार पत्रों में पूरी तरह कवर नहीं हो पाता।

हाउस अगर सहमत है तो तदानुसार आगे की कार्यसूची में संशोधन कर लिया जाए ।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि अगर आप वीरवार को ऑफिशियल डे में कंवर्ट कर रहे हो तो बजट भी फ्राइडे को ही पेश किया जाए ताकि उस पर तैयारी कर उस पर बोलने के लिए सबको शनिवार और रविवार दो दिन का समय मिल जाए । (विघ्न) इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा । आप विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों से पता कर लो कि क्या यह संभव है ? अगर ऐसा हो सकता है तो आप मानकर चलो कि हमें बजट पर तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शुक्रवार को बजट प्रस्तुत कर सकते है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के शुक्रवार को बजट प्रस्तुत करने के निवेदन पर कहना चाहता हूँ कि बजट पेश करने का समय एक दिन आगे कर दिया जाए । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर फ्राइडे को बजट पेश कर दिया जाएगा तो हमें सैटरडे और संडे दो दिन पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर बजट को शुक्रवार को पेश करेंगे तो सदस्यों का राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का टाइम और कम हो जाएगा ।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 30 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 2 मार्च, 2017 को सरकारी कार्य किये जाएं ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 2 मार्च, 2017 को सरकारी कार्य किये जाएं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 2 मार्च, 2017 को सरकारी कार्य किये जाएं ।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

.....

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन पर चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों से पता करा लें कि क्या सोमवार को सदन 11 :00 बजे शुरू कर सकते हैं ? हमारा अनुरोध है कि अगर इस नियम का ज्यादा उल्लंघन न होता हो तो कम से कम बजट सवेरे जल्दी पेश कर दिया जाए । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सत्र सोमवार को 2:00 बजे शुरू होता है उसे सोमवार को सुबह 11:00 बजे ही शुरू कर

दिया जाए । स्पीकर महोदय, जब सारा सदन इस निर्णय से सहमत है तो आप सोमवार को 11:00 बजे ही सत्र प्रारम्भ करवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर सभी की सहमति है तो हम सोमवार को सत्र की शुरूआत प्रातः 11:00 बजे से भी कर सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक चीज यह भी हो सकती है कि आप मंगलवार को विधान सभा सत्र की छुट्टी कर दीजिए । अगर आप एक दिन छुटट्ी का रख लेंगे तो हमें एक दिन और तैयारी करने का समय मिल जाएगा । (विघ्न) अध्यक्ष जी, आज कल सी.डीज. आती हैं । उन सी.डीज. को चलाकर देखने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसलिए बढ़िया है कि मंगलवार को एक दिन छुट्टी कर ली जाए । आप मंगलवार की छुट्टी कर लीजिए और अगले दिन की डबल सिटिंग कर लीजिए । (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने विधान सभा के बजट सत्र की बैठकों का जो शिड्यूल तय किया था उसे सारे सदन ने अप्रूव भी किया था । अतः मेरी गुजारिश है कि उसी के मुताबिक 6 मार्च को प्रातः बजट पेश कर लिया जाए और 7 तारीख को डबल सिटिंग कर ली जाए ।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं । सरकार ने गवर्नर एड्रैस में जो अपना विजन दिया है उसमें कोई नई चीज नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई ।)** पिछले गवर्नर ऐड्रस में सरकार के अगले साल के लिए किये जाने वाले प्रोग्राम्ज का जो विजन था उसको और हाल में दिये गए राज्यपाल अभिभाषण को पढ़ने से पता चलता है कि इस वर्ष के लिए कोई नया प्रोग्राम नहीं है । इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो इस प्रदेश की और गरीब आदमी की भलाई के लिए हो । 14 मार्च, 2016 को दिये गए गवर्नर एड्रैस में सरकार का जो प्रोग्राम था उसमें भी यही महा ग्राम योजना, हाउसिंग फॉर ऑल जैसी योजनाएं थी । शिक्षा विभाग में 1647 लैक्चरार्स को पक्का करने का,

टैक्सटाईल पार्क बनाने का, आदर्श ग्राम योजना का, डॉयरेक्ट रिक्रूट्मैंटस का, जीरो टॉलरैंस का, गौ–अभ्यारण्य आदि पिछले जितने भी प्रोग्राम्ज थे, कोई भी पूरे नहीं हुए हैं और अगला विज़न दे दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी उसका भी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। हांसी बुटाना नहर ब्रांच जो हरियाणा प्रदेश के किसानों की लाइफ लाइन कही जाती है उसका भी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की तरफ से सैक्शन–7 की अमेंडमैंट की बात कही गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात पर सरकार चल रही है। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2017 सरकार 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने जा रही है लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गरीबों के कल्याण लिए कोई भी स्कीम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्यों गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, अभिभाषण में कोई भी स्कीम नहीं होने की वजह से माननीय राज्यपाल महोदय ने केवल पांच पेज पढ़ने के बाद अभिभाषण को केवल 15 मिनट में ही समाप्त कर दिया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल 15 मिनट में ही समाप्त हो गया। उपाध्यक्ष महोदया, सभी विभागों की अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस विभाग की स्कीमें अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ा प्रोग्राम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जो पानीपत से माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू किया था, उसकी भी पोल खुल चुकी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना में बैग और मग खरीदे जा रहे हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की हर तीन महीने में एक बैठक होनी चाहिए थी लेकिन 15 महीने में केवल एक बैठक हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, स्कूल में लड़कियों के लिए 15 लाख रूपये के अवॉर्ड वितरण होने थे लेकिन सरकार ने वह राशि 5 लाख रूपये की कर दी है। उपाध्यक्ष महोदया, लड़कियों की शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाया गया था लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर आपके माध्यम से दो बातें सदन में बताना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में आई उसने नहर बनवाने के लिए अपने हिसाब से प्रयास किया है। वह अलग बात है कि किसी सरकार ने ज्यादा प्रयास किया है और

किसी पार्टी ने कम प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदया, इस नहर का पानी आने पर पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, नारनौल और झज्जर इन जिलों को फायदा होने वाला था। चौधरी बंसी लाल जी एस.वाई.एल. कैनाल नहर के लिए काफी सजग रहते थे, इसलिए अमैंडमेंट से लेकर न्यायालय की पैरवी तक पूरा ध्यान रखते थे। चौधरी हुड्डा साहब ने भी नहर के लिए जहाँ अमैंडमेंट करने की जरूरत थी वहाँ पर अमैंडमेंट की इसलिए सभी सरकारों ने अपने–अपने लैवल पर बहुत प्रयास किए थे। लेकिन एक ही पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदया, असली बात तो यह है कि वर्ष 1987 में चौधरी देवी लाल के हस्ताक्षर से एस.वाई.एल. के हिस्से का 9000 क्यूसिक पानी भाखड़ा ब्रांच में गया था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1988 में नहर की खुदाई के लिए सिंचाई विभाग के एस.ई. श्री सीकरी और 17 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नहर की खुदाई के लिए कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदया, एक आईडिया आया कि जो भाखड़ा मेन लाइन का एग्जिस्टिंग चैनल है, उसकी क्षमता को थोड़ा चौड़ा किया जाये या थोड़ा ऊपर किया जाये, जिससे पानी ज्यादा आ सके। इस तरह से साढ़े तीन लाख एकड़ फीट पानी जो आना है उसका आधा यानि 18 लाख क्यूसिक पानी बी.एम.एल. सिस्टम से सिरसा की तरफ चल रहा है। अगर एस.वाई.एल. नहर पूरी हो गयी तो वह पानी भी डायवर्ट हो जाएगा। हांसी, बुटाना नहर अगर चालू हो जाएगी तो वही 18 लाख क्यूसिक पानी इधर आ जाएगा। वहां के सरपंचों और दूसरे लोगों को साथ मिलकर चौटाला साहब एस. वाई.एल. नहर को खोदना चाहते हैं जबकि यह पूरे प्रदेश का मामला है। एस.वाई. एल. नहर के पूरा होने से सिरसा को पानी जाएगा और इधर आ जाएगा । जहां पहले से ही आधा पानी चल रहा है वह सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, पीछे चौधरी बंसीलाल जी ने भी नहर की सफाई करवाई थी। इनकी रूचि नहीं है कि यह नहर खोदी जाए, क्योंकि खुदाई होती है तो वहां का पानी जाता है। इस हांसी बुटाना ब्रांच पर स्टे किसने लिया ? चाहे तो हाईकोर्ट की जजमैंट को पढकर देखें। उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि यह मुकदमा करवाया गया है, तथा उन व्यक्तियों ने नहीं किया जिनके नाम मुकदमें में हैं। वह पानी इधर डाईवर्ट न हो और हांसी बुटाना ब्रांच में काई पंचर न हो, इसीलिए यह मुकदमा करवाया गया था, और हारने

के बाद उसकी अपील करवायी गयी है। हमारे इलाके को पानी से वंचित करने के लिए इस तरह के स्वांग किए जा रहे हैं और एस.वाई.एल. नहर का पानी लाने का ढोंग रच रहे हैं । वे अकेले श्रेय लेना चाहते हैं जबकि इनको यह कहना चाहिए था कि सरकार के सारे एम.एल.एज. विधानसभा में प्रस्ताव पास करके और माननीय प्रधानमंत्री से टाईम लें उनको रिक्वैस्ट करें। वे सारी एजेंसीज जो इसको खोदने में सक्षम हैं या मिलट्री की मदद लें इस नहर को खोदा जाए। पंजाब की जो सरकार बनेगी उसको कांफिडेंस में लेकर इस नहर को खुदवाया जाये। सारे का सारे हाउस एक रैजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री से टाईम लेकर इस बारे में मिले ताकि इसका केन्द्र सरकार पर पूरा प्रैशर बनें क्योंकि इंडिविजुअल पार्टी की कोशिश करने से यह काम नहीं बनेगा। अब मैं सरकार के विकास की बात करना चाहता हूं । बहुत सारी बातें विकास की हो रही हैं कि सरकार ने बहुत विकास कार्य किया हैं। लेकिन जो आंकड़े बोलते हैं उनके हिसाब से इस सरकार के समय में कोई काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुल 3500 के लगभग घोषणाएं की हैं लेकिन इनमें से कितनी घोषणाएं लागू हुई इसके लिए सरकार की पार्टी मीटिंग में भी विचार–विमर्श हुआ होगा। यह बात भी आयी होगी कि दूसरे कामों को छोड़कर ये घोषणाएं लागू की जाएं। उन घोषणाओं में से सबसे पीछे विज साहब का महकमा है जिसमें 88 प्रतिशत घोषणाएं पैडिंग हैं। (विघ्न) यह आर.टी.आई. का खुलासा है। मुख्यमंत्री जी के विभाग की 80 प्रतिशत घोषणाएं पैंडिंग हैं। श्री रामबिलास शर्मा जी के विभाग की 72.97 और धनखड़ साहब के विभाग की 65.07 प्रतिशत घोषणाएं पूरी होनी बाकी है। किसी भी मंत्री के विभाग की घोषणाएं 50 प्रतिश्त से कम नहीं हैं लगभग 60, 70 तथा 80 प्रतिशत के करीब लम्बित हैं। क्या यह सरकार की कार्यशैली है ? मेरे हल्के में डेढ़ साल पहले घोषणा की गई थी। (विघ्न) लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : मलिक जी, पिछली सरकार के समय में हुई घोषणाओं के बारे में भी बता दें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, मैं पिछली सरकार की बात करता हूं। ओवरब्रिज पिछली सरकार ने बनाया उद्घाटन ये मुख्यमंत्री जी करके आए। कालेज पिछली सरकार ने बनाया उद्घाटन इस मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी, जो काम हमारी सरकार ने गोहाना में किये थे उनका उद्घाटन आप करके आए।

सरकार यह बता दें कि इस सरकार ने कौन से प्रोजेक्ट की नींव रखी है और किसका उद्घाटन किया।

श्री नायब सैनी : मलिक जी, आप अपनी सरकार के बारे में भी बताईये।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी सरकार की बात भी बता देता हूं। अखबारों में छपा है कि सड़क निर्माण में हुड्डा से पिछड़े मनोहर। हुड्डा साहब के दो साल के कार्यकाल में 269 किलोमीटर सड़क बनायी गई और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 53 किलोमीटर सड़क बनाई गई हैं।(शोर एवं व्यावधान) यह रिकार्ड आर.टी.आई. के द्वारा प्राप्त किया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, अभी तो हमारी सरकार का दो साल का कार्यकाल बाकी रह रहा है।(शोर एवं व्यावधान)

श्री जगवीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सही आंकड़े दे रहा हूं और शायद मेरे बोलने से किसी माननीय सदस्य को तकलीफ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सही आंकड़े बोले हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस अखबार की खबर पढ़कर बोल रहा हूं। मैं तो रिकार्ड भी दे दूंगा, एक भी बात बाहर से नहीं आयी होगी।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, क्या आप यह कम्पैरीजन 2 सालों का बता रहे हैं? या दो साल और 10 साल का। (विघ्न)

श्री जगवीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, यह 2 सालों का ही कम्पैरीजन है। आर.टी.आई में खुलासा हुआ है जिसमें लिखा है कि हुड्डा साहब ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 269 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनवाई और श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में 53 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनवाईं। अब मैं स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता हूं। सरकार कहती है कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, हमने राज्य में ओ.डी.एफ कर दिया। इन्होंने कुल टोटल 6207 गांवों में 1380 शौचालय बनाए हैं और यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि पलवल जिले में 8, फरीदाबाद में 17, सोनीपत में 32, रोहतक में 6 शौचालय बनाये हैं। ये कहते हैं कि हमने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सारे डिस्ट्रिक्टों को ओ.डी. एफ कर दिया है। क्या इन आंकड़ों के बल पर ये कहते हैं कि हमने काम किया है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सी.एम की घोषणाओं को पूरा होने का

गोहाना के लोगों का इंतजार कब खत्म होगा ? बीते वर्ष 21 अक्तूबर को सी.एम साहब गोहाना के विकास के लिए ग्रांट देने के साथ–साथ पश्चिमी बाईपास की सौगात भी देकर आए थे, अब तक उस के लिए बजट जारी नहीं हुआ है। पिछले साल से आज तक उसके बारे में जमीन का कोई सर्वे नहीं हुआ है, बनने की बात तो बहुत दूर की है। बराला साहब खुद कहते हैं कि जनता का विश्वास न जीता तो दिखा देगी बाहर का रास्ता। इसके अलावा ये विकास की बात करते हैं जबकि कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट की फाइनैंशियल पोजीशन क्या है, हरियाणा के एक आदमी पर 47155 रुपए का कर्जा है और ये तो 31 मार्च 2016 तक के आकड़े हैं। आज सरकार का 1 लाख 20 हजार 718 करोड़ रुपये का घाटा है और अगले साल तक हरियाणा पर बहुत खतरनाक मोड़ वित्तीय संकट का गहरा सकता है। यह फाइनैंशियल मैनेजमैंट की बात है, अगर यह गलत हो गई तो इसका तुरन्त ऑब्जैक्ट कर देना रिकॉर्ड की बात है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय जगबीर सिंह मलिक जी की बड़ी इज्जत करता हूं। वे बड़े काबिल वकील हैं और इन्होंने फाइनैंशियल पॉजीशन की बात की है, इसके बारे में मैं इनको अलग से बैठकर बता दूंगा। मुझे उपाध्यक्ष जी इजाजत दे देंगी तो मैं अलग से बैठकर मलिक जी को बता दूंगा।

श्री जगवीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी के पास आ जाऊंगा, ये मुझे इस बारे में बता देंगे। अब मैं दूसरे महकमे मार्केटिंग बोर्ड की बात करता हूं। कैग की रिर्पोट में यह कहा गया है कि मार्केटिंग बोर्ड में 125 करोड़ रुपये की बकाया वसूली जान–बूझकर नहीं की जा रही। इसी प्रकार से पी.जी.आई रोहतक के हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेजों का भी बुरा हाल है। कल्पना मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदल दिया गया है, इसके बारे में मुझे पता लगा है वैसे मुझे इस बारे में पक्की इन्फार्मेशन तो नहीं है। कल्पना चावला जिसने विश्व में भारत का और प्रदेश का नाम रोशन किया। मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से उसका भी नाम बदला जा रहा है जोकि बड़े दुख की बात है।

कैप्टन अभिमन्यु : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, थोड़ी सी कुछ कुछ गलतफहमियां लग रही हैं, क्योंकि जगबीर सिंह मलिक जी ने कुछ गलत बात बोली है। मेडिकल कॉलेज का नाम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ही है। यूनिवर्सिटी का नाम प्रारंभ

में हमने कोई नहीं रखा था अब उसका नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय रखा गया है। यूनिवर्सिटी अलग है और मेडिकल कॉलेज अलग है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज अभी भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के नाम से है जो अभी निर्माणधीन है और उसका अगले महीने में उद्घाटन होना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों अलग–अलग बन रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी सही कह रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी भी कल्पना चावला के नाम से बननी थी लेकिन अब उसका नाम बदलकर पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रखा जा रहा है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, उस यूनिवर्सिटी का नाम कभी भी कल्पना चावला के नाम से नहीं रखा गया ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, उस यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला के नाम से ही होना चाहिए क्योंकि बनाते वक्त कहा गया था कि उसका नाम कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा जायेगा ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, जब उस यूनिवर्सिटी का नाम रखने की बात आई तो हमने उसका नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ही रखा। हमने यह कभी नहीं कहा कि उस यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला यूनिवर्सिटी रखा जायेगा ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, करनाल मेडिकल कालेज कल्पना चावला के नाम से है । मेडिकल कालेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों अलग–अलग जगहों पर हैं । मैं कल करनाल गया था तो वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि जिस दिन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस दिन उसका नाम कल्पना चावला के नाम से रखने की बात कही थी । यह बात सच है या नहीं इस बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर सभी को यही लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बदला जा रहा है ।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, जिस दिन मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई उस समय कल्पना चावला मेडिकल कालेज को ही यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी, इसलिए नाम रखने वाली कोई बात नहीं थी । उसके बाद

उस मेडिकल कालेज का अध्ययन किया गया और यह बात निकल कर सामने आई कि उस कालेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता । क्योंकि मेडिकल कालेज के लिए भी जितना स्थान चाहिए वह उतना स्थान नहीं है । बाद में कुटेल गांव की पंचायत ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जगह दे दी । इसलिए वहां पर अलग से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और उसका नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रखा जा रहा है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे वहां लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि यदि वहां यूनिवर्सिटी बनेगी तो वह कल्पना चावला के नाम से बनेगी ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, यदि उस मेडिकल कालेज में यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो उसका नाम कल्पना चावला के नाम से ही होता ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, जिस समय कल्पना चावला मेडिकल कालेज बना उस समय भी कुटेल गांव के लोग मेरे पास जमीन देने के लिए आये थे। मैं कल ही करनाल में था । वहां सभी लोगों ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कल्पना चावला के नाम से वहां यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी । यह आपके रैपुटेशन की बात है । आप इसको चैक कर लें यदि आपने कल्पना चावला के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी तो वह उसी नाम से होनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप दूसरी जगह पर कोई भी चीज बनायें और उसका नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रख लें ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेडिकल कालेज का नाम कल्पना चावला के नाम से रखा जा चुका है । मेडिकल कालेज के लिए अलग जमीन ली गई है और दोनों अलग–अलग इकाईयां हैं । एक मेडिकल कालेज है और दूसरा मेडिकल यूनिवर्सिटी है । दोनों एक जगह पर नहीं हैं । इनकी दूरी 12–13 कि.मी. की है । एक शहर में दोनों का एक नाम रखना ठीक नहीं है । यदि यह मेडिकल कालेज दूसरे जिले में होता तो इसका नाम कल्पना चावला के नाम से रखा जा सकता था। यह यूनिवर्सिटी अलग नाम से बनेगी और मेडिकल कालेज का नाम कल्पना चावला के नाम से ही रहेगा ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाना चाहूंगा । मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हुडा

विभाग की जमीन गलत तरीके से पट्टे पर दे दी गई जिसके कारण सरकार को 417 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । यह नुकसान कम नहीं है । इसके अतिरिक्त 8 करोड़ रुपये का किराये का नुकसान हुआ है और 3 करोड़ रुपये का ब्याज का नुकसान हुआ है । इसी तरह से सरकार की बाल विकास योजनाओं में भी काफी खामियां पाई गई हैं । इसके अतिरिक्त स्टैंप डयूटी के 42.33 करोड़ रुपये और 60.56 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई है । जबकि आम जनता का पुलिस द्वारा चालान कर दिया जाता है और जनता को पकड़ लिया जाता है । लेकिन स्टैम्प ड्यूटी की वसूली की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है । इसी तरह से रोहतक के मेडिकल कालेज(पी.जी.आई.) के ट्रॉमा सैंटर में 57 करोड़ रुपये की मशीने ऐसे ही पड़ी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है । इसके अतिरिक्त वहां की ओ.पी.डी. आधी रह गई है ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य यह भी बता दें कि ये मशीनें कब से पड़ी हैं ?

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ज्यादातर मामलों में सिर्फ सिविल वर्क करके चली गई थी । हुड्डा साहब ने वहां पर अपने नाम का पत्थर लगवा दिया। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, इनको सुनने का माद्दा तो रखना ही चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, मैं श्री अनिल विज को यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये हमारी सरकार द्वारा बनाये गये गड्ढ़ों को ऐसे ही रहने दें। हम दो साल बाद वापिस आकर उनको अपने आप ही भर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं हुड्डा साहब को यह कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि उनकी उम्र बहुत बढ़ रही है क्योंकि उनके पुतले शहर–शहर में फूंके जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग पी.जी.आई., रोहतक में एक ढांचा बनाकर चले गये। न उसकी मैन पॉवर सैंग्शंड की गई, न उसके लिए काई इक्यूपमैंट्स की खरीद का कोई प्रावधान किया गया । यह मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको हम ट्रॉमा सैंटर कहते हैं। मैंने वहां जाकर उसको सारे के सारे को एयर कंडीशंड करवाया। उसमें गैस पाइप–लाइन लगवाई। सारे का

सारा इक्यूपमैंट्स खरीदकर दिया। मैन–पॉवर की व्यवस्था की और एक महीने के अंदर–अंदर वह ट्रॉमा सैंटर चालू हो जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह भी तो उन्होंने ही किया होगा कि खानपुर मेडिकल कालेज के कितने डॉक्टर्स कल्पना चावला मेडिकल कालेज में गये। वहां पर कोई नई भर्ती नहीं हुई । वहां पर सारे का सारा कबूतरखाना बना दिया। वहां पर विटामिन डी, बीटा, एक्स.सी.जी., पी.एस.ए., टी.पी.ओ., प्रोक्लिन, लिपिड प्रोफाईल इत्यादि कोई टैस्ट नहीं होता इस कारण से मरीजों को सब टैस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। वहां पर किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं मिलती। यह रिकार्ड की बात है और यह हर रोज अखबारों में आ रहा है। वहां पर सारे मेडिकल कॉलेज में केवल मात्र एक एम्बुलैंस है। आपने इस मेडिकल कालेज को सी.एच.सी. से भी बदतर बना दिया है। ये मुझे बतायें कि इन्होंने वहां पर क्या काम किया है?

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि श्री मलिक का बेटा वहां पर नियुक्त है वह इनको गलत जानकारी देता है। वहां पर जांच के लिए कोई भी कमेटी बना ली जाये मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पर एक भी दवाई की कमी नहीं है। ऐसे ही एक भी ऐसा टैस्ट नहीं है जो वहां पर न होता हो। वहां पर सारी दवाईयां हैं। हमारे जो वेयर–हाउसिज़ हैं वे दवाईयों से भरे हुए हैं। हमने सारी की सारी परचेजिज़ कर रखी हैं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य जो न्यूज आईटम दिखा रहे हैं यह इन्होंने अपने आप ही छपवाई है। (शोर एवं व्यवधान) अखबार वाले भी बेचारे क्या करें? क्योंकि अगर एक पूर्व मंत्री उनको कुछ छापने के लिए कहे तो उनको तो वह छापना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, आप प्लीज़ जल्दी कंकल्यूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ–साथ पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में 5670 गर्भवती महिलायें हर रोज़ हॉस्पिट्ल्ज़ में पहुंचती हैं और हमारे पास पूरे प्रदेश में गाईनाकोलॉजिस्ट है सिर्फ 72 अर्थात 5670 गर्भवती महिलाओं के लिए केवल मात्र 72 डॉक्टर्ज हैं। ऐसी हालत में डिलीवरी कैसे करवाई जायेगी? इसमें 8 दिन की वेटिंग है। यह आर.टी.आई. के माध्यम से प्राप्त हुई इनफर्मेशन बता रही है। यह

बात मैं पूरी तरह से वास्तविक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : डिप्टी स्पीकर मैडम, मलिक साहब को यह भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार आने से पहले लगातर 10 साल इनकी पार्टी की सरकार हरियाणा में सत्तारूढ़ रही। उस दौरान इन्होंने क्या किया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, ऐसी बात नहीं थी कि पूर्व की सरकार ने बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भर्ती किये हों और बाद में वे छोड़कर भाग गये हों। यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं कि इस समय हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि इन्हें मेडिकल कालेज, खानपुर से हटाकर करनाल में डॉक्टर्स को नहीं ले जाना चाहिए था बल्कि इनको वहां के लिए नये डॉक्टर्स भर्ती करने चाहिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, स्वास्थ्य विभाग में 750 डॉक्टरों की कमी है । हम 662 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं तथा उनकी ऐप्लीकेशन्ज रिसीव की जा चुकी हैं । पहली बार पोजीटिव साइन आया है कि 662 पदों के विरूद्ध 1800 आवेदन प्राप्त हुये हैं । हम शीघ्र ही 662 डॉक्टरों की भर्ती कर देंगे और उसके बाद यह शॉर्टेज बहुत कम रह जायेगी । मैं मानता हूं कि हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं नहीं बोल रही हूं इसलिए मेरा टाईम भी श्री जगबीर सिंह मलिक को दे दिया जाये ।

श्री अनिल विज : मैडम किरण चौधरी जी, क्या मलिक साहब आपके ग्रुप में हैं जो आप अपना समय इनको दे रही हैं? जब आपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी उसमें तो कोई विधायक नहीं आया था या आप अपना समय इनको दे कर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, विज साहब मेरी चिन्ता न करें बल्कि अपने विधायकों को सम्भालें इनके 14–14 विधायक सारी–सारी रात मीटिंग करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं विज साहब से कहना चाहता हूं कि किसी ने सरदार जी से कहा कि सरदार जी कड़ा प्रसाद बना हुआ है तो सरदार जी ने कहा कि मैनूं की, फिर उनको बताया गया कि तुहाडे लिए बना है तो सरदार जी ने कहा कि फिर तैनूं की । इसलिए विज साहब का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा समय है हम इनको दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं किरण चौधरी जी को कहना चाहता हूं कि ये जो कह रही हैं कि हमारे 14 एम.एल.ए. सरकार से नाराज हैं और इसीलिए हुड्डा साहब तो रोजाना मुंह खोल कर सोते हैं कि शायद कोई लड्डू मुंह में गिर जाये लेकिन उनके मुंह में लड्डू गिरने वाला नहीं है। इन्होंने करनाल में भी कहा था कि बी.जे.पी. के एम.एल.ए. मेरे सम्पर्क में हैं और मैं सरकार पलट दूंगा लेकिन यह बात सच नहीं है । हमारे सभी एम.एल.ए. मजबूत हैं, सभी एम.एल.ए. सी.एम. साहब के साथ हैं और सभी एम.एल.ए. एक साथ इस सदन को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं । कोई लड्डू इनके मुंह में गिरने वाला नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की बातों से सदन का कीमती समय बर्बाद हो रहा है इसलिए डिस्कशन को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तक सीमित रखा जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं किरण चौधरी जी को कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाये और उसमें कोई विधायक न आये । जब भी सी.एम. साहब मीटिंग बुलाते हैं तो सभी उपस्थित होते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, यदि कोई इस तरह की बात ही नही है तो श्री अनिल विज जी ने अपनी सी.आई.डी. करवाने का आरोप सरकार पर क्यों लगाया था? इनकी सी.आई.डी. कौन करवाता है? हमने अखबारों में पढ़ा था। इसका मतलब इनकी सी.आई.डी. होती है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, हमने कब कहा कि सरकार सी.आई.डी. करवाती है? कुछ अधिकारियों की जूते खाने की आदत होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य बोल रहे हैं और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है । यह गलत बात है । यह हमारी पार्टी का मामला है और पार्टी के लिए हम सभी एक हैं । इस तरह की बात हाउस में नहीं होनी चाहिएं । कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य बोल रहा है और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : बहन जी, विज साहब का यह कहना है कि मलिक साहब आपकी पार्टी में हैं या नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरी : यह पार्टी का ही काम हो रहा है । कोई पार्टी में हो या न हो उससे आपको क्या मतलब । वह देखना मेरा काम है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं किसानों की बात करना चाहता हूं कि सरकार ने अगर सबसे ज्यादा जड़े खोदने का काम किया है तो वह किसानों का किया है । सरकार ने किसानों की जड़ें खोद कर उनको उखाड़ने का काम किया है । सरकार को जो स्वामी–नाथन आयोग रिपोर्ट लागू करनी थी वह रिपोर्ट कहां गई ? कुरूक्षेत्र वालों से जाकर पूछें तो आज बढ़िया आलू का भाव मैक्सीमम 1 रूपये या 2 रूपये है । गाजर की फसल को किसानों ने खेत में ही बहा दिया है। अब इस सरकार के समय में किसी भी सब्जी का रेट अच्छा नहीं है । **(विघ्न)** यह किसान के जीवन मरण का प्रश्न है लेकिन बी.जे.पी. पार्टी के सदस्यों को इसका मजाक सूझ रहा है । **(विघ्न)**

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, रूलिंग पार्टी के सदस्यों द्वारा बीच में इस तरह की टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है । अगर यह इस तरह ही टोका टिप्पणी करते रहेंगे तो हम मे से कोई भी नहीं बोलेगा और हम वॉक आउट कर जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक जी, आप कॉन्टीन्यू करें । **(विघ्न)**

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, इनकी पार्टी के लोगों द्वारा तो आलू को तीन फुट का बताया गया है कि आलू तीन फुट का पैदा हुआ है। **(विघ्न)**

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे साथी नायब सैनी के क्षेत्र में तो आलू सबसे ज्यादा उगाया जाता है । इनको तो हमसे ज्यादा पता है लेकिन ये भी

इस बात पर हंस रहे हैं । सैनी जी, आपको तो इसके बारे में सोचना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, किसान के बारे में बात करते हैं तो बी.जे.पी. पार्टी के सदस्य मजाक करते हैं । इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं है । आज किसान के पास जितनी जमीन है और उसमें जितनी पैदावार होती है उसके हिसाब से किसान का खर्चा भी पूरा नहीं होता । आप उस परिवार से पूछ कर देखें जिसको घर का खर्चा खेती से ही चलाना है वह कहां से घर का खर्च चलाएं। जो किसान ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाने के लिये पैसा लगाता है तो वह किसान तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है और सरकार कहती है कि हम वर्ष 2022 में किसान की इन्कम डबल कर देंगे । कैसे डबल होगी, कितनी डबल होगी यह देखने की बात है । अब मैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बताता हूं जिसमें यह है कि एक फसल में पानीपत के किसान को एक साल में 1354 रूपये, करनाल में 1880 रूपये, रोहतक में 1747 रूपये आमदनी के मिलेंगे । उसमें किसान के परिवार की मजदूरी नहीं लगा रखी है । यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है जिसमें जिले वाईज रिकॉर्ड दे रखा है । सरकार कहती है कि हम वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे । यह बड़ा गम्भीर विषय है इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है । इस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ।

श्री महीपाल ढांडा :उपाध्यक्ष महोदया, आप इनसे पूछिये कि वर्ष 2012–13 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या रिकॉर्ड था वह भी आया होगा । उसके बारे में भी एक बार बता दें । **(विघ्न)**

श्री जगबीर सिंह मलिक : उसके बारे में भी बताएंगे ।

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मलिक साहब से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2010–11, वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 में यह कितना था क्योंकि आप बता रहे हैं कि आगे इतना आएगा तो आप ये भी बताईये । **(शोर एवं व्यवधान)**

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2010–11, वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 में हरियाणा में एक नारा लगता था कि – ' हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में ।' **(शोर एवं व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदया : कुलदीप जी, प्लीज आप बैठ जाईये ।

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। यदि वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक की फसलों के रेट्स की कंपैरेटिव स्ट्डी करा ली जाये तो स्वयं ही पता चल जायेगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी किसान हितैषी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह यादव जी ने फसल बीमा योजना के बारे में सदन में बड़ी अच्छी बात कही थी। सरकार ने किसानों की फसल का बीमा कर दिया, यह बड़ी अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदया, पॉलिसी तो ठीक है लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है? सरकार की नीयत किसानों से लेने की तो बनी है परन्तु उनको कुछ दे देने की इनकी नीयत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि किसान खुद जाकर बीमा करवाये। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने चौधरी जगबीर सिंह जी को अपनी बात रखने के लिए फिराखदिली से जो समय दिया था, वह अब इस समय का गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं और जो बात आंकड़ों से शुरू हुई थी, उससे दूर जा रहे हैं और गलत स्टेटमैंट देने लग गए है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त किसान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो साल के कार्यकाल में 2800 करोड़ रूपये देने का काम किया है जबकि इनकी सरकार का एक साल का औसत 70–75 करोड़ रूपये से ज्यादा का नहीं हुआ करता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः जगबीर जी, आप बीच में इंट्रप्ट मत कीजिए। माननीय मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, अतः आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों की फसल खराब होने की एवज में जो पैसे दिए जाने थे वह इन्होंने नहीं दिए और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही 243 करोड़ रूपये किसानों को उनकी खराब फसलों के मुआवजे के तौर पर दिए थे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलत आंकड़े प्रस्तुत करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, अगर दिया है तो क्या किसानों पर अहसान किया है? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दांगी जी को मुझे बीच में इंट्रप्ट नहीं करना चाहिए। सदन में इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, किसी माननीय सदस्य को उसकी बात कहने से रोकना ठीक नहीं है। ऐसा करके एक तरह से सदन की व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः किरण जी, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से तो व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है लेकिन आपकी तरफ से लगातार व्यवस्था खराब होती नज़र आ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के साथ मज़ाक ठीक बात नहीं है। किसानों को पांच–पांच रूपये के चैक देना मज़ाक नहीं तो और क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, किसानों को पांच–पांच रूपये के चैक दिए गए यह बात कुलदीप शर्मा जी ने भी मानी है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार में तो किसानों को उनकी फसल के बहुत अच्छे दाम दिए जाते थे।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, कुलदीप शर्मा जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके राज में अर्थात 2009 से 2014 तक किसानों की फसलों की जो कीमत थी और भारतीय जनता पार्टी के राज में फसलों की जो कीमत है यदि इसकी कंपैरेटिव स्ट्डी करा ली जाये तो सब कुछ क्लीयर हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं इस बारे में अब सब कुछ साफ–साफ बताना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, बड़ी विडम्बना है कि किसानों को मजाक का विषय बनाया जा रहा है। भगवान न करे कि किसी किसान की फसल खराब हो? किसानों की फसल खराब हुई है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः दांगी जी, प्लीज बैठिए। मंत्री जी को अपना उत्तर देने दीजिए?

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, अब जबकि किसानों की फसलों से संबंधित विषय चल रहा है तो उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि किसानों की प्राकृतिक फसलों व मौसम के बारे में सारा रिकॉर्ड सदन में रखा गया। इनके समय में तो किसानों की खराब फसलों की एवज में 5–5 रूपये के चैक दिए जाते थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ये बातों की पुनरावृत्ति मत करें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय दांगी जी को आश्वस्त करता हूँ कि मैं बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। वर्ष 2014–15 में जब इनकी सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी उस समय हरियाणा की कृषि विकास दर –2% हुआ करती थी जिस पर हमने सदन में बाकायदा तौर पर वाईट पेपर पर इंडिकेट भी किया था और इसी महान सदन में कृषि से जुड़े वास्तविक आंकड़े रखे थे। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार द्वारा सत्ता प्राप्ति के अगले साल में कृषि विकास दर को 3% से ऊपर लाया गया। इस साल कृषि विकास दर में 7% तक ग्रोथ का अनुमान आया है जोकि कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से बहुत अधिक है जिससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश ने कृषि विकास की दर में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने आज सदन में यह कहा था कि वर्ष 2009 से 2014 तक फसलों की जो कीमत हमारे कांग्रेस पार्टी के शासन काल में थी और जो कीमत भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में है, यदि इसकी कंपैरेटिव स्ट्डी करा ली जाये तो वास्तविकता का पता चल जायेगा। अगर किसान ने दिन रात मेहनत करके अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाया है तो उसमें सरकार का क्या योगदान है?

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदय, अब तो शायद कांग्रेस को एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा तभी जाकर ये लोग मानेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, रिकॉर्ड तो मेरे पास भी है। सरकार चाहे तो मैं इस रिकॉर्ड को देने के लिए तैयार हूँ। इसको पढ़कर सब कुछ क्लीयर हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, शायद मलिक साहब को मालूम नहीं कि रिकॉर्ड हमारे पास भी मौजूद है। (शोर एवं व्यवधान)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्णदेव कम्बोज): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय धनखड़ साहब से अनुरोध है कि संबंधित विषय पर जो रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है, उसके बारे में मुझे सदन को अवगत कराने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, किस–किस समय में फसलों के क्या–क्या एम.एस.पी. रहे हैं, मैं उन आंकड़े के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वर्ष 2006–2007 में गेहूं का रेट 650 + 50 रूपये बोनस प्रति क्विंटल था और कॉमन धान का मूल्य 580 + 40 रूपये बोनस प्रति क्विंटल था और 40 रूपये उस समय बोनस के रूप में दिए गए थे यानि धान के 'ए' ग्रेड का मूल्य 610+ 40 रूपये बोनस प्रति क्विंटल था। वर्ष 2009–10 में गेहूं का रेट 1080 रूपये प्रति क्विंटल था और धान के 'ए' ग्रेड का मूल्य 980 रूपये प्रति क्विंटल हुआ करता था और 50 रूपये बोनस के रूप में दिए गए थे। वर्ष 2011–12 में गेहूं का रेट 1120 रूपये प्रति क्विंटल था और धान के 'ए' ग्रेड का मूल्य 1110 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। वर्ष 2012–13 में गेहूं का रेट 1285 रूपये प्रति क्विंटल था और कॉमन धान का मूल्य 1250 रूपये रखा गया था और कॉमन धान 'ए' ग्रेड का मूल्य 1280 रूपये रखा गया था। वर्ष 2013–14 में गेहूं का रेट 1350 रूपये प्रति क्विंटल था, कॉमन धान का रेट 1310 रूपये प्रति क्विंटल और धान के 'ए' ग्रेड का मूल्य 1345 रूपये रखा गया था। उपाध्यक्ष महोदया वर्ष 2014–15 में जब हमारी सरकार आई तो उस समय गेहूं और पैडी के जो दाम थे वह इन्हीं की सरकार के तय किए गए थे। इसके हिसाब से गेहूं का एम.एस.पी. 1400 रूपये प्रति क्विंटल और कॉमन धान का एम.एस.पी. 1400 रूपये प्रति क्विंटल तथा 'ए' ग्रेड धान का एम.एस.पी. 1400 रूपये प्रति क्विंटल तय किया था । हमारी सरकार ने वर्ष 2016–17 में सामान्य गेहूं का एम.एस.पी. 1525 रूपये

क्विंटल, 'ए' ग्रेड गेहूं का एम.एस.पी. 1510 रूपये प्रति क्विंटल और 'बी' ग्रेड गेहूं का एम.एस.पी. 1470 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । ये कह रहे हैं कि हमने रेट बढ़ाने का काम किया है । (विघ्न) मेरे पास ये आंकड़ें हैं । यदि इनको आंकड़ों की जरूरत हो तो मैं इनके पास भिजवा देता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ये मुझे बीच में इंट्रप्ट न करें । माननीय सदस्य सारी बात सुनने का माद्दा रखें और अच्छे श्रोता बनें । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा प्रदेश का गन्ना यू. पी. में गया है। इस बार यू. पी. में गन्ना ले जाने वालों की लाइनें लगी हुई थी क्योंकि हरियाणा की मिलों में गन्ने का बोंड 300 क्विंटल से घटाकर 150 क्विंटल कर दिया गया है और गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ाया गया । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, अगर कोई किसान अपना गन्ना लेकर रूड़की जाता है तो उसका वहां तक आने–जाने में 7–9 हजार रूपये तो किराया ही लग जाता है । आज हमारे इलाके का गन्ना यू. पी. में जा रहा है । यहां हरियाणा में कुछ समय पहले तक गन्ने का 300 क्विंटल का बोंड भरवाया जाता था अब उसको घटाकर 150 क्विंटल कर दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदया, एक एकड़ खेत में लगभग 400 क्विंटल गन्ना पैदा होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सारे गन्ने को अगर हरियाणा की मिलें नहीं लेती तो फिर वह गन्ना कहां जाएगा (विघ्न) पहले यू.पी. का गन्ना हरियाणा में आता था । ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा का गन्ना यू.पी. में जा रहा है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, अब आप कन्कल्यूड कीजिए । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह कहते हैं कि किसान अपनी नपुंसकता और प्रेम–प्रसंग की वजह से मरते हैं । ऐसी तो इनकी सोच है । इसी तरह आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में भाजपा के एम.पी. गोपाल सेठी जी कहते हैं कि किसान मरता है तो मरने दो । कर्ज से दुःखी होकर आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों को मरने का शौक है । हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में धनखड़ साहब कहते हैं कि किसान तो कायर हैं । कुछ समय पहले इन्होंने यह बयान दिया था । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मलिक साहब को वही बताना चाहिए जो मैंने कहा था । माननीय सदस्य जगबीर सिंह मलिक जी सदन में मेरी बात को बदलकर न कहें । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, आज किसान कर्ज से बहुत दुःखी है । फसल बीमा योजना के तहत एक करोड़ किसानों के खाते से 990 करोड़ रूपये काटे गए हैं । सरकार यहां प्राइवेट कम्पनी के हाथों किसानों का पैसा लुटवा रही हैं । मेरा कहना है कि जो किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहे सरकार को केवल उसी की फसल का बीमा किया जाना चाहिए । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब हुड्डा साहब की सरकार किसानों की फसलों का बीमा कर रही थी तब हरियाणा प्रदेश में कौन सी कम्पनियां बीमा कर रही थी ? उस समय माननीय सदस्य मलिक साहब सरकार में थे और इन्होंने उस समय यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया ? पिछली सरकार के समय में भी जब फसल बीमा योजना बनाई जाती थी तो उस समय भी रिलायंस, आई.सी.आई.सी.आई. और बजाज इत्यादि कम्पनीज़ को फसलों का बीमा करने का काम सौंपा जाता था । माननीय सदस्य को सदन में कम से कम अपनी बात तो आंकड़ों सहित ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए । आदरणीय सदस्य हुड्डा साहब की सरकार जब किसानों की फसलों का बीमा कर रही थी तब हरियाणा में कौन–सी कम्पनियां थी ? उस समय भी यही सब कम्पनियां थी । (शोर एवं व्यवधान) उस समय भी इन्हीं कम्पनीज़ को बीमा दिया जा रहा था । मलिक साहब को पहले पूर्व मुख्य मंत्री हुड्डा साहब की निन्दा करनी चाहिए कि उन्होंने गलत काम किया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार अपनी कमियों को नहीं सुनना चाहती है । (विघ्न) मेरा माइक बंद कर दिया गया है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे इसलिए आपका माइक एक मिनट के लिए बंद कर दिया था । अब आप प्लीज कन्कल्यूड कीजिए क्योंकि आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं । (विघ्न) आप प्लीज वाइंड अप कीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिए । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, अब आप कन्कल्यूड कीजिए क्योंकि सदन के बाकी सदस्यों को भी बोलने के लिए समय चाहिए । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, अगर ये सदस्य यूं ही खड़े रहेंगे तो मैं कन्कल्यूड नहीं कर पाऊँगा । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, जब आपने नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए एक घंटे का समय दिया है तो he is starting from his Party. जबकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओपनर स्पीकर हैं इसलिए आप उनको और ज्यादा बोलने का समय दें। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, आपकी पार्टी से और सदस्य भी तो बोलना चाहेंगे । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मलिक साहब को बोलने के लिए समय तो अवश्य ही देना चाहिए । (विघ्न) ये पार्टी के मेन स्पीकर हैं ।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने अपना जीवन बीमा करवा रखा है ? (विघ्न) यदि माननीय मंत्री जी ने अपना जीवन बीमा करवा रखा है तो वह इन्होंने अपनी मर्जी से ही करवाया होगा । इनका जीवन बीमा किसी ने जबरदस्ती से तो नहीं किया होगा । माननीय मंत्री जी ने अपना जीवन बीमा अपनी मर्जी से ही तो करवाया होगा लेकिन किसान की फसल का बीमा जबरदस्ती किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदया, आज किसानों को यह भी नहीं पता कि कौन सी कम्पनी फसल बीमा कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः दांगी साहब, तथ्यों को गुमराह करके सदन को मत बताइये बल्कि सही बात सदन को बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषाण में जीरो टॉलरैंस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है लेकिन पिछली बार जीरो टॉलरैंस पर सरकार ने बहुत जोर दे रखा था। (शोर एवं व्यवधान) यह बात भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजेंः उनके नाम बताएं जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, श्री उमेश अग्रवाल के मुखर रवैये पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) बिजली के मीटरों के घोटाले का मुद्दा उठाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) ग्वाल पहाड़ी का करोड़ों रूपयों का मुद्दा उठाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) मैडम, मैं जीरो टॉलरेंस पर ही बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह के बहुत सारे स्कैम अखबारों में जगजाहिर हुए हैं। जैसे ग्वाल पहाड़ी और मैट्रो का रूट बदलकर बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने का आरोप– भाजपा विधायक, उमेश अग्रवाल। उपाध्यक्ष महोदया, जमीन घोटाले के बहुत सारे सबूत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिए गए हैं। उन पर कार्रवाई करना या ना करना सरकार का काम है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक कार्यकर्त्ता की बात भी सदन को बताता हूँ जिसने कहा है कि कांग्रेस के राज में कोई काम पहले 1 हजार रूपये में होता था लेकिन अब वह काम 4 हजार रूपये में होता है। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदया, मलिक साहब इस बात को तो मान गए हैं कि उनके राज में 1–1 हजार रूपये रिश्वत ली जाती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, आप मलिक साहब को वाईंड अप करने के लिए कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी को पता होगा कि एक–दो ट्रांसफर के कितने–कितने पैसे लिए जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की बातों से सदन की गरिमा गिर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, एक अखबार में वित्त मंत्री महोदय के बारे खबर छपी थी । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः मलिक साहब, क्या आपने सारे अखबारों की कटिंग इक्ट्ठी की हुई है?

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, कुछ खबरें मैंने आर.टी.आई. के माध्यम से ली हुई है लेकिन फिशर मैन भर्ती की खबर मेरी है। (शोर एवं व्यवधान) इस

भर्ती को सरकार ने क्यों वापिस लिया और इस घोटाले में कौन–कौन शामिल था। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 97 के अनुसार–

"Whilst the Assembly is sitting, a member-

(i) shall not read any book, newspaper, or letter except in connection with the business of the assembly;"

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। अगर मैं गलत हूं और अखबार में छपी खबर गलत है तो अखबार वालों के साथ–2 मुझे भी पार्टी बनाएं। मैं फेस करूंगा। I will face defamation case मैं सारी बातें अखबार के माध्यम से कह रहा हूं। अब सरकार कान ही बन्द करना चाहती है तो बेशक करे और चाहे कितना ही गोल–माल करें। हम उनको रोकना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सरकार और ज्यादा ऐसे काम करे ताकि वह बदनाम हो जाए।(शोर एवं व्यावधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक और नये स्कैम के बारे में बताना चाहता हूं। इस सरकार में विधायक और अधिकारी सी.एम. विंडों को गम्भीरता से नहीं लेते। इस सरकार के मंत्री अपने लोगों को डी.सी. रेट पर नौकरी लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, नौकरी लगवाने के लिए बैक डोर से एन्ट्री पूरे हरियाणा में हो रही है। किसी भी कारपोरेशंज में या मार्केटिंग बोर्ड में या किसी भी दूसरे दफ्तर में बिना सिफारिश के नौकरी नहीं लग रही है। (विघ्न) यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह कार्यकर्ता का ऑब्जैक्शन है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले दिनों एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ जिसमें एक बी.जे.पी. के लीडर का नाम आया था। उसका संबंध पानीपत जिले से था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तो पानीपत में ठहरते भी होंगे क्योंकि पानीपत में इनका पुराना याराना है इसलिए इनकी जानकारी में वह सारा मामला है। अध्यक्ष महोदय, एक आर.टी.आई. के द्वारा इस सरकार के मंत्रियों की सम्पति का ब्यौरा मांगा गया था। यह ब्यौरा देना मैनडेट्री है लेकिन आज तक यह ब्यौरा किसी मंत्री ने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब के समय में सभी मंत्रियों की सम्पति का ब्यौरा आर.टी.आई के द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया था। लेकिन

इस सरकार में अभी तक यह ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसके अलावा इस्माईलाबाद में 18 करोड़ रूपये का गेहूं के बारदाने का स्कैम हुआ था। इस तरह के स्कैम में पता नहीं बाद में सरकार की तरफ से क्या समझौता हो जाता है कि ऐसे केस खत्म हो जाते हैं जबकि कोई आम आदमी फंस जाता है तो ये उसके पीछे लग जाते हैं। सरकार ऐसे नहीं चलती। (शोर एवं व्यावधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनका समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः कैप्टन साहब आप जो क्रैशर चला रहे हैं मुझे उसका पता है। मुझे सबका पता है। किसके भाई और किसके साले प्रोपर्टी के काम में लिप्त हैं। मैं सभी के नाम बता सकता हूं। यह तो वही बात है कि धन माया की लूट है लूट सके तो लूट फिर पाछे पछताएगा जब सरकार जाएगी छूट। (शोर एवं व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः मलिक जी, आप वाईंड अप करो आपको 55 मिनट बोलते हुए हो चुके हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, मेरी 20 साल की पब्लिक लाईफ है। एक आदमी बता दे कि मैंने अपनी पब्लिक लाईफ में कभी पैसे या भ्रष्टाचार किया हो। मैंने बहुत मुकदमें भी सहे हैं तथा मेरे खिलाफ दस एफ.आई.आर भी दर्ज हुई हैं। एक आदमी भी सिद्ध नहीं कर सकता कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। यह सरकार आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की बेइज्जती कर रही है। उनके ऊपर एक सुशासन सहयोगी बैठा दिया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों पर एक निगरानी कमेटी बनाई हुई है। मतलब यह है कि कंस्टीच्यूशनल चुने हुए मैम्बर/लोगों के ऊपर लगाम लगा रखी है। ये सब क्या करते हैं ? ये उनको ब्लैकमेल करते हैं ? ये सब पैसे कमाने के धन्धे बना रखे हैं। आज इतना बुरा हाल है कि कोई रजिस्ट्री बिना पैसे के नहीं होती। (विघ्न) इसके बारे में सी.एम. साहब क्या बोलेंगे क्योंकि इसमें सबका इन्ट्ररस्ट एक ही है। (शोर एवं व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः मलिक साहब, आप वाईंड अप करें। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः सी.एम. साहब, मैं नहीं बल्कि यह तो पब्लिक बोलती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं जिसका संबंध सोनीपत के कार्पोरेशन से संबंधित

है। उपाध्यक्ष महोदया, जबरदस्ती उन गांवों को इस कार्पोरेशन में शामिल कर रखा है, जो 20 किलोमीटर दूर के गांव हैं और वे ऐसा नहीं चाहते। अब यह कह दिया गया है कि आपका 2 साल का टैक्स माफ है लेकिन वह प्रॉब्लम 2 साल के बाद फिर आयेगी। आप उन लोगों का रेफरेंडम कराओ और यदि वे कॉर्पोरेशन में आना चाहते हैं तो उनको कार्पोरेशन में लो। यदि वे नहीं आना चाहते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। उन लोगों की भावना को समझना चाहिए।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : जब कांग्रेस सरकार में 9 नगर निगम बनाए गए थे तो क्या गांव वालों से पूछा गया था जबकि वे विरोध कर रहे थे। जबरदस्ती कई गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था। रोहतक के कई गांव नगर निगम में शामिल किये गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि मैंने दो बार स्टेटमैंट अखबार में दिए थे कि जबरदस्ती न करें, रेफरेंडम करा लें। फिर अब टैक्स के नोटिस गए और कविता जैन जी ने 2 साल का माफ करवा दिया । 2 साल का तो माफ हो गया। लेकिन आगे क्या होगा टैक्स देना तो पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : माननीय उपाध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि वे सदन को गुमराह ना करें अभी जिन गांवों का जिक्र किया गया इनको निगम में शामिल करने के लिए बाकायदा एक कमेटी का निर्माण किया गया था और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर और बाकायदा सभी गांव के रिप्रजेंटेटिव से उनकी ऐप्रूवल लेकर ही उन गांवों को कार्पोरेशन में शामिल किया गया था। पूरे कानूनों के तहत और नियम के तहत ही कार्पोरेशन का निर्माण किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, पहले सिर्फ एक ही कार्पोरेशन थी फरीदाबाद कार्पोरेशन। पिछली सरकार ने एक साथ 8 कार्पोरेशन गठित की थी जैसा कि अभी हमारे साथी मंत्री ने जिक्र किया। वे बताए कि वह किस आधार पर बनी और वो कैसे बनी क्या वह बनने लायक थी और आज तक भी 8 कार्पोरेशन जो पहले बनी थी, उनमें शामिल हुए गांवों में आज भी विकास के काम नहीं हुए जबकि ये दूसरों पर उगलियां उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, उन गांव के अंदर भी टैक्स आज तक नहीं लिया जा रहा और हमने अभी फिर से ये नए निगम के अंदर दो साल के टैक्स माफ किए हैं और पहले के पुराने गांवों के अंदर

भी पहले के टैक्स माफ किए हैं, इसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, आपको बोलते हुए पूरा एक घंटा हो जाएगा, 2 मिनट में आप कनक्लूड करो।

श्रीमती किरण चौधरी : अगर ऐसी बात है तो मैं भी बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, आज ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं, ट्रांसफर रुकवाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। हमारे गोहाना में बी.जे.पी का एक बड़ा लीडर है उसने एक बी.डी.ओ का ट्रांसफर रुकवाने के लिए 1 लाख रुपया लिया है और न हुआ हो तो नायब सैनी जी बतायेंगे, इनकी ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग में यह बात ओपन हुई थी।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : मेरे पास ग्रीवैंसिज कमेटी में ऐसा कोई मामला आया है तो उनमें हमने कार्रवाई की है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सैनी साहब, खजान सिंह बी.डी.ओ का ट्रांसफर रुका था और ये कहा था कि ये कैसे रुक गया।

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे सोनीपत में ग्रीवैंसिज कमेटी में मेरे सामने भ्रष्टाचार का कोई मामला मेरे सामने आया तो उसके ऊपर हम ने तुरन्त कार्रवाई की है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, ये पब्लिकली जानकारी है।

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, पता नहीं इनके पास कहां से ये जानकारी आई, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इनके पास इस प्रकार की जानकारी कहां से आती है ? माननीय सदस्य इस प्रकार से सदन को गुमराह न करें, ये गलत तथ्य पेश कर रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में एफीडेविट दे दें और मैं भी एफीडेविट दे देता हूं। आप इस बारे में इनक्वायरी करवा लें। सदन की एक कमेटी बना दे। मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है और न जिंदगी में मैने कभी झूठ बोला है, यह रिकार्ड की बात है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एफीडेविट लाकर दे दूंगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जगबीर जी से एफिडेविट ले लिया जाए। मलिक साहब, आप एफीडेविट दीजिए। मलिक जी, सदन को गुमराह मत कीजिए वरना ऐफीडेविट दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, ये बहुत देर से सदन में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, आप अपना ऐफीडेविट सदन के सामने रखिए। यह प्वॉयंट कार्यवाही में नोट किया जाए कि मलिक साहब अपना ऐफीडेविट देंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सदन को बेवजह गुमराह न करें। किसी पर बेवजह आरोप लगाए और वापस हट जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनको सिद्ध करें सदन का समय खराब न किया जाए। ये आरोप लगाएं तो स्टैंड करें और आरोप को साबित करें।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब , आप एफीडेविट दें । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया जी, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि कहीं पर कोई कमी है तो माननीय सदस्य वह बात यहां पर उठायें । यही लोकतंत्र है । इस महान सदन का भी यही काम है लेकिन माननीय सदस्य यहां जो बात कहें उसके प्रमाण भी साथ लेकर आयें । यदि कोई बगैर प्रमाण के अपनी बात कहता है तो उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदया : यदि मलिक साहब एफिडेविट देंगे तभी उनकी यह बात रिकार्ड पर आयेगी वरना इनकी यह बात सदन की कार्यवाही से निकाल दी जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, जो ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके रिकार्ड में सारी बातें होंगी । उस दिन की ग्रीवैंसिज कमेटी का रिकार्ड मंगवा लिया जाये । उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, ग्रीवैंसिज कमेटी का रिकार्ड यहां मंगवा लिया जाये । यदि उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होगी तो मलिक साहब के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, ग्रीवैंसिज कमेटी का रिकार्ड मंगवा लिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, आप एफीडेविट दे दें । उसके बाद ग्रीवैंसिज कमेटी का रिकार्ड भी मंगवा लिया जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने किसानों को कहा था कि गेहूं का 2100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जायेगा लेकिन किया कुछ भी नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी के पी.ए. का मैटर है । ये ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे । अखबार में यह खबर आई हुई है कि ***

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी साहब, आप पेपर देखकर पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी बात रिकार्ड नहीं की जा रही । दांगी साहब जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य कह रहे थे कि वित्त मंत्री ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे । ईमानदारी की बात ये स्वयं कह रहे हैं। वे दोनों लोग इन्हीं के भेजे हुए थे जो कि इनके हल्के के गिरावड़ गांव के हैं। वे लोग इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको कहा कि वे जो बात कह रहे हैं वह लिखित में दे दें मैं तुरंत कार्यवाही करूंगा और एफ.आई.आर. दर्ज करवाउंगाा। लेकिन उन लोगों ने लिखित में नहीं दिया। मैंने बाद में भी उनके पास मैसेज भिजवाया और उनसे रिकवैस्ट भी की कि वे लिखित में अपनी शिकायत दे दें, मैं कार्यवाही करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने लिखित में नहीं दिया। मैंने उनको यहां तक कहा कि वे बिना नाम के लिखित में दे दें लेकिन तब भी उन्होंने लिखित में नहीं दिया। वे दोनों माननीय सदस्य के हल्के के गांव गिरावड़ के हैं और इनके कार्यकर्ता भी हैं । मैंने इनसे बाद में भी रिकवैस्ट की। अगले दिन भी मैसेज भेजा। उसके बाद एक बार फिर मैसेज भेजा। मैं इनसे एक बार फिर से रिकवैस्ट करता हूं कि ये अपने उन कार्यकर्ताओं को दोबारा से मेरे पास भेज दें,

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

मैं दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दूंगा। यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वे माननीय सदस्य श्री दांगी जी के कार्यकर्ता हैं।

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया जी, जिस प्रकार कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य व्यवहार कर रहे हैं इससे यह ज़ाहिर होता है कि इनके पास यहां पर बात करने के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाये। ये हाउस के समय को अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं। जितने घोटाले इनकी सरकार में हुए हैं अगर हम उनकी यहां पर चर्चा करें तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप कृपया करके बैठ जायें। मलिक साहब, विपक्ष के नेता ने अपनी बात 66 मिनट में पूरी कर दी थी लेकिन आपको बोलते हुए 67 मिनट हो गये हैं इसलिए आप एक मिनट के अंदर वाईंड–अप करें।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। महोदया जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रदेश के लिए शिक्षा सबसे जरूरी, अहम और बड़ा मुद्दा है। आज प्रदेश में शिक्षा की क्या हालत है यह किसी से छिपा नहीं है। आज प्रदेश के 9100 जे.बी.टी. टीचर्स सड़कों पर हैं। आज स्कूलों में टीचर्स नहीं है। सरकार को इलीजिबल कैंडीडेट्स को तो नौकरी दे देनी चाहिए। अगर स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे और किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे? पिछले गवर्नर एड्रैस में सरकार द्वारा 1647 लैक्चरार्ज और असिसटैंट लैक्चरार्ज भर्ती करने की बात कही गई थी। आज तक इस बारे में सरकार के स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आज गैस्ट लैक्चरार्ज धरने पर बैठे हैं। एग्जाम का समय है अगर लैक्चरार्ज नहीं होंगे तो कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होगी। सरकार के स्तर पर इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। प्रदेश में आज ड्रॉप–आउट रेट निरंतर बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में कैग की रिपोर्ट ने एक गम्भीर सच्चाई भी उजागर की है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया जी, जगबीर सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि ऐक्सटैंशन लैक्चरार्ज की कोई मांग नहीं थी। पिछली सरकार ने तीन हजार ऐक्सटैंशन लैक्चरार्ज को 18000/– रूपये प्रति महीना की कंसोलिडेटिड तनख्वाह पर रखा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमण्डल ने बैठकर यह विचार किया कि यह 18,000/– रूपये का वेतन बहुत कम है इसलिए इसको बढ़ाया जाये। इस प्रकार से हमने उनके वेतन को बढ़ाकर 25,000/– रूपये प्रति महीना कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) जगबीर सिंह जी अगर आप इन लैक्चरार्ज का हित चाहते हैं तो मेरी बात को शांति के साथ सुनने की कृपा करें। मैं

आपको यही बता रहा हूं कि सरकार ने इन लैक्चरार्ज के हित में कितना बड़ा फैसला लिया है। हमने उनका वेतन उनके खातों में डलवाया और साथ ही उनसे यह भी कह दिया कि वे राजनीतिक लाभ उठाने वाली राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं के झांसे में न आयें। हुड्डा साहब के झांसे में आकर 17 हज़ार गैस्ट टीचर्स पंत नगर में इनके निवास स्थान पर आमरण अनशन पर बैठे थे। मैंने उनको वहां से उठवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया जी, जिस प्रकार से मलिक साहब अब प्रदेश में शिक्षा की बदतर हालत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल तक इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी क्या इनको इस दौरान इस बारे में कोई विचार नहीं आया।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, लैक्चरार्ज की बात चली थी जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने उनका वेतन 18,000/– रूपये प्रति महीना से बढ़ाकर 25,000/– रूपये प्रति महीना कर दिया। मैं इनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार के समय में भर्ती हुए 17000 गैस्ट टीचर्स जंतर–मंतर, नई दिल्ली में धरने पर बैठे थे। उस समय माननीय शिक्षा मंत्री भी वहां पर जाकर उनको आश्वस्त करके आये थे। हम भी वहां पर जाकर उनको आश्वस्त करके आये थे। इन्होंने उनको यह आश्वासन दिया था कि इनकी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आप सभी को पक्का कर दिया जायेगा। आज वर्तमान सरकार को बने दो वर्ष से ऊपर का समय हो गया है लेकिन अभी तक एक भी गैस्ट टीचर को पक्का नहीं किया गया है। सरकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि वे 20–21 नये कॉलेज बनाने जा रही है। एक तरफ तो सरकार ने यह घोषणा कर दी कि सरकार इतने नये कॉलेज बनायेगी और दूसरी तरफ आज हरियाणा प्रदेश के लैक्चरार्ज जिनके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि हमने उनका वेतन 18 हजार रुपए से बढ़ा कर 25 हजार रुपये कर दिया है वे इस बात को लेकर स्ट्राइक पर हैं कि हमें भी पक्का किया जाये क्योंकि आपकी सरकार ने शुरू में उनसे यह वायदा किया था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो जितने भी गैस्ट टीचर्स हैं चाहे लैब असिस्टैंट हैं या नर्सिंग स्टाफ है सबको रेगुलर कर देंगे । आज आप भी उसी ठेका प्रथा को चालू रख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने चालू की थी । आप भी आज उसी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं । उसको बढ़ावा देने की बजाय उन लैक्चरार्ज को रेगुलर किया जाये ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके । आज कॉलेज और स्कूलों के एग्जाम

सिर पर हैं । आज लड़के–लड़कियां इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे अपनी पढ़ाई कहां पर करें । अगर आपके टीचर और लैक्चरार्ज लम्बे समय तक हड़ताल पर रहे तो आप यह मान कर चलो कि आपका रिजल्ट फिर से जीरो आयेगा । आज बच्चों के मां–बाप को इस बात की चिन्ता है कि इन टीचर्स के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और वे सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं या वहां से निकाल कर प्राइवेट में दाखिल करवा दें ताकि वे अच्छे ढंग से पढ़ सकें । शर्मा जी, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर कॉलेज खोल दिये, यूनिवर्सिटी खोल दी या कोई यूनिवर्सिटी का सैन्टर खोल दिया तो वहां पर स्टाफ पूरा होना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो तथा उसका लाभ हरेक को मिल सके । मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप उन 3 हजार लैक्चरार्ज को पक्का करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सरकार ने गैस्ट लैक्चरार्ज का वेतन बढ़ा कर 25 हजार रुपये कर दिया है जबकि लैक्चरार्ज का कहना है कि सरकार हमें कंसोलिडेटिड वेतन दे दे । अगर आप उनको कंसोलिडेटिड 25 हजार रुपये वेतन दे देंगे तो उनको फायदा होगा । उनका यह भी कहना है कि जब तक मैटर सबज्यूडिश है तब तक सरकार उनको 25 हजार कंसोलिडेटिड दे दे और वे 6 पीरियड लेने के लिए तैयार हैं । आप उनको 6 पीरियड लेने के लिए भी कह दें लेकिन उनकी फिक्स सैलरी कर दें । उनका बस इतना सा मसला है । आप यह काम कर दीजिए उनकी डिमांड खत्म हो जायेगी ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, एक्सटैन्शन लैक्चरार्ज के लिए यू.जी.सी. के नॉर्म्स 1 हजार रुपये प्रति पीरियड हैं और हरियाणा सरकार उनको 250/– रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से दे रही है । आप उनको यू.जी.सी. के नॉर्म्स के मुताबिक 1 हजार रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से दे दीजिए उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा । आज जो पी.जी.टी. के गैस्ट लैक्चरार्ज को हरियाणा सरकार 34–35 हजार रुपये वेतन दे रही है और उनसे ज्यादा योग्यता वाले नैट क्वालिफाईड और पी.एच.डी. लैक्चरार्ज को कम वेतन दिया जा रहा है । हमें यह भेदभाव समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष और बहन किरण चौधरी जी व श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने गैस्ट टीचर्स के बारे में कहा है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि गैस्ट टीचर्स का हुड्डा साहब की सरकार के समय दिल्ली में पंत मार्ग पर आमरन अनशन का 16वां दिन था तब उनको हम मना कर लाये थे । हमने चीफ सैक्रेट्री के खिलाफ कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट करवाया था । हुड्डा साहब के समय में श्रीमती सुरीना राजन सैक्रेट्री एजुकेशन थीं और उन्होंने कोर्ट में यह ऐफीडेविट दिया था कि हम इन गैस्ट टीचर्स को 340 दिन के बाद हटा देंगे और Government is a continuous process और वह 340 दिन का टाईम इनके समय में ही पूरा हो गया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हमने एक भी गैस्ट टीचर को हटने नहीं दिया । आज 28 महीने इस सरकार को बने हुए हुए हैं । चौधरी अभय सिंह जी, हमने एक भी गैस्ट टीचर को हटने नहीं दिया । जो ढुल साहब की एक्सटैंशन लैक्चरर्ज की चिन्ता है और जो बहन किरण चौधरी की चिन्ता है उसमें इनकी 18 हजार रूपये से 25 हजार रूपये सैलरी देने की मांग नहीं थी । हमने सुओमोटो अपनी उदारवादी भावना को देखते हुए इन लैक्चरर्ज की सैलरी 25 हजार रूपये प्रति मास की है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : शर्मा जी, बात तो सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस की सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी उस संबंध में आपके मैनीफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे । आपने तो उसको खत्म करने की बजाए उसको बढ़ावा दे दिया । आप नये कॉलेज खोलने जा रहे हो, आप नये इंस्टीच्यूट बनाने जा रहे हो लेकिन स्टाफ आपके पास है नहीं । लोग स्ट्राईक पर जा रहे हैं । तो इस प्रकार सारी चीजें कैसे निपटाई जाएंगी । जो नये कॉलेज बनाए जाएंगे उसका क्या फायदा होगा जब तक उनके अन्दर स्टाफ ही नहीं होगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : अभय जी, उसका भी हमने प्रावधान किया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : आप यह बताईये कि क्या प्रावधान किया है ? हजारों की संख्या में लोग धरनों पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं जिससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अभय जी, उनकी स्ट्राइक का मुद्दा यह नहीं था । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, मलिक साहब को वाइंडअप करने दो ।

श्री जगबीर सिंह मलिक :उपाध्यक्ष महोदया, राज्यपाल अभिभाषण में लिखा है कि हरियाणा कर्मचारियों को 7th पे कमीशन देने वाला पहला स्टेट है । उस संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पुलिस वाले रोते घूम रहे थे कि हमारा रिस्क अलाउंस करने से हमारी तनख्वाह तो 7th पे कमीशन मिलने के बाद 500 रूपये कम हो गई । क्या यह 7th पे कमीशन है ? मेरे पास यह कर्मचारियों का रैज्योल्यूशन है । वह कहते हैं कि हमारा दो हजार रूपये का जो अंतरिम भत्ता था वह भी काट दिया गया है । वे कहते हैं कि इस अंतरिम भत्ते को भी हमारी बेसिक में मर्ज किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, आज हर आदमी 7th पे कमीशन से असन्तुष्ट है । उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं । आज सबसे बड़ा बुरा हाल कानून व्यवस्था का है । सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदया, इनको बोलते हुए बहुत समय हो गया है । इन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात की इसलिये मैं कहना चाहती हूं ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आज सदन में सारे आंकड़े दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक साहब, आपको बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर बोलने के लिये एक मिनट का समय और दिया जाता है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास इतने आंकड़े हैं अगर मैं इन सबको यहां रखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदया : मलिक जी, आप इन आंकड़ों को हाउस की टेबल पर रख दो । हम इनको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लेंगे ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा, हिमाचल, जम्मु–कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश साथ लगती स्टेट्स हैं इन सभी में क्राईम का क्या रेट है । उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, आप महसूस करोगे कि हरियाणा में वॉमैन के अगेंस्ट 9446 केसिज हैं और percentage contribution to the Indian index 2.9 है । हरियाणा की टोटल पॉपूलेशन 124.7 करोड़ है और इसका काग्जीनिबल रेट 75.7 है ।

उपाध्यक्ष महोदया : जगबीर मलिक जी, आपको बोलते हुए 70 मिनट हो गये हैं । आपके जो बाकी इशूज हैं उनको हमें दे दीजिये इनको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, क्या मुझे लॉ एण्ड ऑर्डर पर बोलने का समय नहीं दिया जा सकता ? (शोर एवं व्यवधान) मुझे बोलने के लिये केवल आधे घण्टे का समय और दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जगबीर मलिक जी, आपको बोलते हुए 70 मिनट हो गये हैं । अब आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है । प्लीज अब आप बैठ जाईये । आपकी जो बाकी बातें हैं उनको हमें दे दीजिये इनको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा ।

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, अगर आप कहती हैं तो मैं अपनी सारी बातों को सदन के पटल पर रख देता हूं । आप इनको हाऊस की प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा देना ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप ये दे दें हम इनको हाऊस की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : ठीक है, मैं अपने कागजात सदन के पटल पर रख देता हूं ।

(इस समय श्री जगबीर सिंह मलिक ने अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख दी।)

***श्री जगबीर सिंह मलिक :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के गोहाना की समस्यायें इस प्रकार हैं –

सड़क निर्माण–मार्केटिंग बोर्ड़ के द्वारा निम्नलिखित सड़कों का निर्माण करवाया जाये–

1. न्यात से गढ़ी सराये नामदार खाँ।
2. न्यात से खानपुर कलाँ।

.....

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।

3. जाजी से गोहाना।
4. सलीमसर माजरा से गोहाना।
5. बोहला से दोदवा।
6. हुल्लाहेड़ी से रेलवे स्टेशन बड़वासनी।
7. भठगाँव धर्मशाला से खेड़ी दहिया वाया हसनपुर तिहाड़ कलॉ।
8. जाजी से भठगाँव।
9. कांसड़ा स्कूल से सरगथल।
10. गामड़ी से न्यात।
11. महमूदपुर से गढ़ी उजाले खाँ।
12. दुभेटा से बजाना कलाँ।
13. चिटाना से पांची।
14. चिटाना से हुल्लाहेड़ी।
15. लुहारी टिब्बा से जाजी।
16. बोहला से नैना तातारपुर।
17. बोहला से कटवाल तक।

सड़क मुरम्मत–

मार्केटिंग बोर्ड़ की जो सड़के खराब हो चुकी है उनकी मुरम्मत कराई जावे।
जनस्वास्थय विभाग–

1. रतनगढ़ गाँव में डिग्गी का निर्माण।
2. खिजरपुर जाट माजरा में डिग्गी का निर्माण।
3. ककाना भादरी में डिग्गी का निर्माण।

पीने के पानी के लिये नये ट्यूबवैल–

1. नगर के वाटर वर्क्स से सीधी नगर गाँव में सप्लाई की जावे।

पशु अस्पताल–

बीधल, मोहाना, चिटाना, व हुल्लाहेड़ी में पशु अस्पताल बनाये जाये व रोलद लतीफपुर में पशु अस्पताल में डाक्टर लगाया जाये।

खेल स्टेड़ियम–

मोहाना, सलारपुर माजरा, बड़वासनी, गुहाणा, बादशाहपुर माच्छरी, न्यात, गामड़ी, दुभेटा मोई व भादी में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये।

बिजली घर–

जुआंव मोई (माजरी) गाँव में बिजली के सब स्टेशन बनवाये जाये।

नहरी विभाग–

1. जौली लाठ (रिठाल माईनर) की रिमाडलिंग की जाये ताकी खेतों में पानी पहुँच सके।
2. तिहाड़ माईनर का लेवल ठीक करवाया जाये।

स्वास्थय विभाग–

1. मोहाना में मजूर सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 का निर्माण किया जाये।
2. सिटावली में आर्युवैदिक डिस्पैंसरी, जौली में सब हैल्थ सेंटर का निर्माण कराया जाये।

गोहाना हल्के में चौपाल अधूरी पड़ी हैं। सरकार का काफी पैसा लगा हुआ है। उन्हें पूरा करवाया जाये और जो खेल स्टेडियम अधूरे हैं उन्हें पूरा करवाया जाये और उनमें कोंच नियुक्त किये जाये।

फिरनी–

पंचायती राज विभाग से निम्नलिखित फिरनी पूरी करवाई जाये–
गंगेसर, खंदाराई, हसनगढ़, वजीरपुरा, गामड़ी, कांसडी, ककाना भादरी, जौली, लुहारी टिब्बा, नैना तातारपुर, माजरा, बादशाहपुर माच्छरी, तिहाड़ खुर्द, महलाना, हुल्लाहेड़ी, व खानपुर कलाँ में धानकों से स्टेडियम तक फिरनी बनवाने बारे।

पानी निकासी के लिये नाला निर्माण–

पंचायती राज विभाग द्वारा खानपुर कलाँ में चमारों वाली चौपाल व दूसरी जगह से गंदे पानी की निकासी के लिये नाला बनाया जाये।
कांसड़ा में ड्रेन के साथ–साथ नाला बनाया जाये। महलाना में नहर के साथ–साथ नाला बनाया जाये।

महिपुर में वैस्ट जुआं न0 6 ड्रेन पर गाँव के साथ वाले रास्ते पर पुल का निर्माण करवाया जाये।
दुभेटा गाँव में तालाब की चारदीवारी का निर्माण।

गामड़ी गाँव में तालाब की चारदीवारी का निर्माण।
माजरी में आंगन बाड़ी केन्द्र का निर्माण करवाया जाये।
मोहाना गाँव में सब यार्ड़ घोषित करके पक्का बनाया जाये।
जुआं, जोहाना, भठगाँव में आई0टी0आई0 स्थापित की जाये।
मोहाना में लड़कियों का कालेज खोला जाये।
सिटावली में प्राईमरी स्कूल की बिल्ड़िग बनाई जाये।
जिन गाँव के तालाब रद्ध हो चुके है उनका भरत करके पार्कों का निर्माण करवाया जाये।
प्रत्येक गाँव में सालाना एक करोड़ की ग्रांट दी जावे।

<u>गोहाना शहर की समस्यायें–</u>

1. गोहाना शहर का पश्चिमी साइट का बाईपास बनाया जाये।
2. मिनी बाईपास जींद रोड़ से महम रोड़ तक बनाया जाये।
3. ड्रेन न0 8 को पक्का करके पटरी पर लाईट लगवाई जाये।
4. पानीपत रोहतक रोड़ को चौड़ा किया जाये।
5. हुड्डा सेक्टर 7 की सड़कों व पार्क के लिये पैसा दिया जाये।
6. गोहाना में नया बड़ा खेल स्टेड़ियम बनाया जाये।
7. नई कालौनियों में सीवरेज व पानी के लिये पैसा दिया जाये।
8. गोहाना में बरोदा व महम रोड़ पर आर0ओ0बी0 बनाया जाये।
9. पुरानी तहसील की बिल्डिंग में शापिंग काम्पलैक्स बनाया जाये।
10. गोहाना बाईपास पर टूरिज्म काम्पलैक्स बनाया जाये जहां पर वैंक्वेट हाल भी बनाया जाये।
11. गोहाना शहर में नगर परिषद में सालाना 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जावे।
12. सोनीपत वाया गोहाना–जींद रेल के कम से कम 3 चक्कर आने व जाने के करवाये जाये तथा गरीब रथ का ठहराव गोहाना में किया जावे।
13. **भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे के अनुसार गोहाना को जिला घोषित करे।**

गोहाना हल्का के अति महत्वपूर्ण कार्य–

1. रेल कोच फैक्टरी लाठ–जौली में लगनी चाहिये।
2. आई0एम0टी0 लाठ जौली में लगनी चाहिये।
3. lllTM.At Kilorad (sonipat) में पी. पी. पी. मोड में बननी चाहिये।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, आज हमारे सम्मानित साथी श्री जगबीर सिंह मलिक ने राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सी.ए.जी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लैपटॉप, बैग्स व अन्य सामग्री खरीदे जाने के विषय पर सवाल उठाये है और स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटी

बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लैपटॉप, बैग्स व अन्य मदों की खरीद में अनियमित्तताएं बरती गई हैं। अतः इस अवस्था में सम्मानित सदन के समक्ष मुझे अपनी बात रखना बहुत जरूरी हो गया है। उपाध्यक्ष महोदया, जनवरी, 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटियों के मान–सम्मान को बढ़ाने व दिन–प्रतिदिन गिरते जा रहे लिंगानुपात पर रोक लगाने के लिए जिला पानीपत में एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री व तकरीबन 21 राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भारत सरकार के विभिन्न राज्यों से आए हुए अधिकारियों को शामिल होना था। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदर्शी सोच व बेटियों के स्वाभिमान के रक्षार्थ देश की इस आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए 20, 21 तथा 22 जनवरी, 2015 को जिला पानीपत में एक राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयोजित हुआ। चिंतन शिविर में दो दिन की कांफ्रेंस रखी गई थी जिसके तहत बेटियों के जन्म से रिलेटिड अपराध, घरेलू हिंसा तथा ट्रैफिकिंग व बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों जैसी समस्यायें उभरकर सामने आई थी और इनको दूर करने संबंधी उपायों पर भी इस चिंतन शिविर में मंत्रणा हुई। 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री जी ने बेटियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण संबंधी अभियान की शुरूआत की थी। इस चिंतन शिविर में देश भर के 100 ऐसे जिले आईडेंटिफाई किए गए जहां पर लिंगानुपात पूरे देश की एवरेज रेशो से भी कम था तथा एक डाटा यह भी निकलकर सामने आया कि लिंगानुपात कम होने के मामले में हरियाणा के 12 जिले भी शामिल हैं और यह वे जिलें है जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे। मैं इस चिंतन शिविर का यहां पर वर्णन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि श्री जगबीर सिंह मलिक ने कैग रिपोर्ट के द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लैपटॉप व मग्गे खरीदने संबंधी जो मामला उठाया है, उस मामले का संबंध कही न कहीं इस चिंतन शिविर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इतना सब बताने के बाद मैं अब मूल विषय पर आती हूँ कि क्यों और किस लिए 1800 लैपटॉप व बैग्स खरीदे गए थे। उपाध्यक्ष महोदया, बेटियों के मान–सम्मान से जुड़े इस राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर को व्यापक प्रचार की जरूरत थी। संभव है कि इस तरह के चिंतन शिविर के लिए आए हुए अतिथियों के लिए प्रचार सामग्री संबंधी मैटेरियल देने की आवश्यता तो होनी ही थी और इन सबका प्रबंध करने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करके सरकार द्वारा

सर्टीफाईड एजेंसी के माध्यम से लैपटॉप, बैग्स और अन्य सामग्री खरीदी गई थी। अब रही बात गाईडलाईन्ज की। जिन गाईडलाईन्ज का जिक्र सी.ए.जी. की रिपोर्ट में किया गया है वह गाईडलाइन्ज बाकायदा तौर पर 20 व 21 जनवरी, 2015 के चिंतन शिविर की बैठक के बाद 22 जनवरी, 2015 को तैयार की गई थी। उपाध्यक्ष महोदया, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में चार बातें और कही गई हैं। मैं समझती हूँ कि इस अवस्था में इनको क्लीयर करना भी बहुत जरूरी है कि सी.ए.जी. ने कहीं भी फंडस के दुरुपयोग की बात नहीं की है क्योंकि कल फिर और कोई साथी इस तरह की बात उठायेगा। (विघ्न) ये केवल डिवीजन ऑफ फंड़ज है।

उपाध्यक्ष महोदयाः कविता जी, आप संक्षिप्त करें क्योंकि इस तरह की चीजें सरकार के जवाब में भी आ ही जायेंगी। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है, लेकिन आप शार्ट में अपनी बात कहें।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है मैं संक्षेप में अपनी बात कहती हूँ। ऑन लाईन शिकायतों का निवारण करने संबंधी भी एक बात उठी है कि शिकायत निवारण के लिए कोई पोर्टल नहीं बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार द्वारा शिकायत निवारण के लिए बाकायदा तौर पर सी.एम. पोर्टल की व्यवस्था की गई है। (शोर एवं व्यवधान) इसके साथ–साथ हमारी सरकार ने पुलिस विभाग का 'हर समय' पोर्टल भी बनाया हुआ है । उस पोर्टल पर भी शिकायतों को दर्ज करवाया जा सकता है । (विघ्न) मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूं जो आपने बात रखी थी । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : कविता जी, आप जो कह रही हैं ये सारी बातें सरकार के जवाब में आ जाएंगी । अतः अब आप वाइंड अप कीजिए ।

श्रीमती कविता जैन : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कह रही हूं । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि जो लिंगानुपात पर काम न होने और बच्चियों की एनरोलमैंट कम होने की बात कही गई है तो मैं कहना चाहती हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है । इसकी सत्यता के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार को हमारे देश के राष्ट्रपति ने खुद 'नारी शक्ति सम्मान' अवार्ड से नवाजा है । इसके अतिरिक्त अगर आप पिछले 15 सालों का

रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाएंगे कि हरियाणा का लिंगानुपात पहली बार 900 को क्रौस कर गया है । उसके साथ–साथ बच्चियों की ऐनरोलमैंट और शिक्षण स्तर के बारे में जो आवाज उठाई गई है उस विषय पर मैं सदन को बताना चाहूंगी कि इस वर्ष बेटियों की ऐनरोलमैंट के विषय में बेटी दिवस पर भी भारत सरकार के द्वारा यमुनानगर जिले को पुरस्कृत किया गया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मुझे भी इस बारे में अपनी बात कहनी है। (विघ्न)

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । (विघ्न) किरण जी, आप सदन में कल से बोल रहे हो । आप जब से आए हो बोल ही रहे हो । मेरा आपसे निवेदन है कि अब हमें बोलने दीजिए। आप हर एक सदस्य के समय पर बोलते हो। मुझे पता है कि आप अपनी पार्टी की लीडर है लेकिन अब आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। यह मेरे बोलने का समय है। देखिये, यह गलत बात है । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के समय दिया । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : असीम जी, किरण जी को एक मिनट में अपनी बात कहने दें ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर लूंगी । मेरे ध्यान में ये तीन रिप्रेजेंटेशंज आए हैं – पहला हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन, दूसरा हरियाणा पुलिस एसोसियेशन और तीसरा मिड डे मिल वर्कर्स यूनियन का । इन्होंने कहा है कि इनको सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिला है । राज्यपाल के अभिभाषण में सातवें वेतन आयोग के बारे में मैंशन किया गया है इसलिए मैं कह रही हूं कि इन तीनों सगंठनों को सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी देने के जो वायदे किये थे वे पूरे किये जाएं । (विघ्न)

श्री असीम गोयल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं । इस समय हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है और इस साल हरियाणा की स्थापना को 50 साल पूरे हुए हैं । इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार ने जनता को इस वर्ष को मनाने के

लिए 'सर्व हरियाणा, गर्व हरियाणा, पर्व हरियाणा' का नारा दिया है । सभी हरियाणावासी इस पर्व को मना रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, इस महान सदन की आज की इस कार्यवाही में आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं । इस साल हमारे सिख गुरू साहिब–ए–कमाल सरबंसदानी गुरू गोविन्द सिंह जी का 350 वां प्रकाश वर्ष और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 300वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है । हमारी सरकार ने श्री गुरू गोविन्द सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में लखनौर साहब जो उनका ननिहाल है मेरे इलाके में पड़ता है में एक वी.एल.डी.ए. प्लस कॉलेज और पॉलीक्लीनिक माता गूजरी कौर जी के नाम पर स्वीकृत किया है । वहां पर जो मार्ग अम्बाला से लखनौर साहब को जाता है हरियाणा सरकार ने उस मार्ग को भी माता गूजरी कौर जी के नाम पर रखने का काम किया है । हरियाणा प्रदेश के अम्बाला शहर में पहले सिख म्यूजियम की स्थापना करने की घोषणा 12 फरवरी को करनाल की अनाज मण्डी में की गई । इसके अतिरिक्त अम्बाला शहर में हरियाणा स्टेट में श्री गुरू गोविन्द सिंह के नाम पर अभी तक एकमात्र लाइब्रेरी है । उसके जीर्णोद्धार के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं मैं उन सबके लिए पूरी सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । अभी मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यगण एस.वाई.एल. कैनाल पर बहुत लम्बा व्याख्यान देकर गए हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चॉकलेट बॉय ने हमें दूध और जलेबी खिलाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी जिन्दगी के 30 वर्ष गांव में गुजारे हैं। जो बाजरा उम्र के हिसाब से उन्होंने खाया हुआ है उसी तरह से अपनी उम्र के हिसाब से ज्वार और बाजरा मैंने भी खाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: ज्वार नहीं खाया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, ज्वार भी मैंने खाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. कैनाल के लिए ठीक है विपक्षी पार्टियों ने प्रयास किया होगा लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में हरियाणा प्रदेश के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, जब फैसला हरियाणा के पक्ष में आ गया तब विपक्षी पार्टी ने फावड़े और कुदाल निकाल लिए। जब फावड़े और कुदाल निकालने का समय था तो उस समय मैच फिक्सिंग की तरह समझौता कर लिया और कहा कि मुद्दो को खत्म नहीं

करते बल्कि धरती में गाढ़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उन मुद्दों को उखाड़ेंगे और राजनीतिक रंग दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आज एक परिवार की चौथी पीढ़ी एस.वाई.एल. कैनाल पर राजनीति करती–करती हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनेता बन गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोजः उपाध्यक्ष महोदया, असीम जी को चौधरी देवी लाल की पीढ़ी के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः कम्बोज साहब, जब मुझे चॉकलेट बॉय बोला था तो उस समय मैंने कुछ नहीं कहा था लेकिन अब बोलने का समय मेरा है इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. कैनाल के ऊपर जो सर्कस बाजी पुरानी सरकारों ने की है, वह सारे प्रदेश के लोगों को पता है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, आज ये लाखों आदमियों की भीड़ की बात कर रहे हैं जबकि मात्र पांच हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। मेरे पास रिकॉडिंग है। इन लोगों का शो फ्लॉप हो गया। (शोर एवं व्यवधान) डेढ़ महीने तक पूरे प्रदेश को बांटने का काम किया गया। उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. कैनाल नहर की खुदाई हुई या नहीं इस बात का तो पता नहीं लेकिन विपक्षी पार्टी ने स्वयं राजनीतिक जड़े जरूर खोद ली है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधुः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधुः उपाध्यक्ष महोदया, जब हम 23 फरवरी, 2017 को एक जनसभा करके एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे को लेकर के पंजाब की सीमा की ओर जा रहे थे, तो असीम गोयल जी ने कटाक्ष किया था कि मैंने आप लोगों के लिए दूध और जलेबी का इंतजाम किया हुआ है। उसी आधार पर नेता प्रतिपक्ष ने असीम गोयल जी को चॉकलेट बॉय कहा था। लेकिन आज असीम जी ने कहा है कि एक परिवार की चार पीढ़ियों ने लगातार एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे को उठाकर रखा है। असीम जी, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवी लाल ने अपने 15वें वर्ष में जंगे आजादी से पहले लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी देने को काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः संधु साहब, आप अपने नेता का कितना मर्जी गुणगान करें इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मैं नेता प्रतिपक्ष के सामने जवाब देना चाहता था लेकिन वो जवाब सुनने से पहले ही चले गए, जो आप लोगों की पुरानी आदत है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः संधु जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। सभी दलों को इस बात की खुशी मनानी चाहिए और सदन में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टी ने तो खुशी मनाने की बजाय फावड़े और कुदाल निकाल लिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी दुकानदारी बन्द हो गयी है। (विघ्न) मैं इनैलों के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमारी चिन्ता न करें। (विघ्न) इस बात का भी पता चल जाएगा कि रानिया से कितने आदमी वहां आये थे क्योंकि मेरे पास एक–एक आदमी की रिर्काडिंग है। इनैलो के सदस्य बार–बार लाखों लोग अम्बाला पहुंचने की बात कह रहे हैं, जितनी बार इनके द्वारा लाखों लोग कहा गया है अगर इन सबका जोड़ कर लिया जाए तब भी सारे लोग उतने नहीं थे। मेरे पास इसकी पूरी रिर्काडिंग है। उपाध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार ने अन्तोदय योजना बनाई है। (शोर एवं व्यवधान) गंगवा जी, कुछ इंतजार तो करो। आपने तो फावड़े कुदाल बगैरह निकाल लिए। जब इनको निकालने का समय था तब क्यों नहीं निकाले ?

श्री रणबीर गंगवाः उपाध्यक्ष महोदया, जब हमारी पार्टी की सरकार थी तब वर्ष 2002 में एस.वाई.एल. नहर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. नहर में पानी तो आ ही जाएगा लेकिन इन लोगों का जोर सबने देख लिया। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवाः उपाध्यक्ष महोदया, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गंगवा जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यावधान) अब जो भी गंगवा जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री रणबीर गंगवाः उपाध्यक्ष महोदया, * * *

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं गंगवा जी की ईमानदारी की दाद देता हूं कि इन्होंने यह तो मान लिया कि वहां संख्या कम थी। मैं इसके लिए इनको सैल्यूट करता हूं, और धन्यवाद करता हूं। इन लोगों ने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए यह ड्रामा किया था। पूरे प्रदेश की जनता ने इनको अच्छी तरह से देखा है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार ने आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलते हुए अन्तोदय योजना को लागू किया। उस सूत्र का प्रतिपादन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जिसके पैरों में बिवाई फट्टी हुई है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है तथा पेट में खाना नहीं है उस तक मद्द पहुंचे। जब तक सरकार के अच्छे कार्यों की छाया, रोटी, कपड़ा, मकान, पढाई और दवाई आदि मूलभूत सुविधाएं इस प्रदेश के हर नागरिक को नहीं मिलेगी तब तक यह स्कीम कामयाब नहीं होगी। हमारी सरकार अन्तोदय कार्यक्रम के सूत्र पर चलते हुए लाईन में बैठे आखिरी व्यक्ति से लेकर पहले व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, आज हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सबका साथ सबका विकास', 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' का नारा दिया है। मैं तो कहता हूं कि जो पुराने समय की पिता –पुत्र और चाचा – भतीजों की सरकारें थी। उन सरकारों से निजात दिलाकर आज प्रदेश के अन्दर ढाई करोड़ आम लोगों की सरकार बनाने का काम किया गया है। मेरा सीधा यह कहना है कि 90 विधानसभाओं में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घूम–घूम कर हरेक इलाके के लिए करोड़ों रूपये की घोषणाएं की हैं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धरती की कोख से उगे सूरज की रोशनी ने अपने और पराये में फर्क नहीं समझा। इस क्षेत्रवाद, वंशवाद और भेदभाव का दंश हरियाणा ने झेला है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, इस समय 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' की बात कुछ माननीय सदस्यों

.....

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

ने उठाई है। मेरा मानना है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से ऊपर भी आज बेटी अपनाओ को लेकर एक योजना सरकार ने प्रदेश में चलाने का काम किया है। हमने एक समारोह किया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ। समाज के जितने भी अमीर और संपन्न मां–बाप हैं जो कहते हैं कि वे अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमने उनसे निवेदन किया था कि आप यह कसम लें कि जिस दिन वे अपनी बेटी की शादी करेंगे उसी दिन उसी मंडप के अन्दर एक जरूरतमंद बेटी की शादी करके अपनी बेटी के साथ–साथ उस बेटी को भी विदा करेंगे। 14 फरवरी को 51 लोगों ने इस फार्म को भरकर इस योजना की शुरूआत की है तथा और लोग भी इस योजना से जुड़ रहे हैं। साक्षी मलिक और दीपा मलिक, दोनों बेटियों ने ओलंपिक और रियो पैरा ओलंपिक के अन्दर पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारी सरकार ने उन बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया, उनके मां–बाप का सम्मान किया, उनका सम्मान किया ताकि हरेक बेटी के मां–बाप को लगे कि मेरी बेटी बेटे से कम नहीं है। आज प्रदेश के अंदर ई–गवर्नेंस–स्टैंपिंग की योजना हमने लागू की है। मलिक साहब, अभी कह रहे थे कि तहसीलों के अंदर रजिस्ट्रियां बिना पैसों के नहीं होतीं। मैं यहां खुला चैलेंज देता हूं कि अम्बाला शहर की तहसील में आप किसी व्यक्ति को बिना नाम बताए भेज दें, अगर उसका एक रुपया भी रजिस्ट्री करने में लगेगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा। आज तहसीलें जन–सेवा का माध्यम बनी हैं। मलिक साहब, पहले रसूखदार और मंत्रियों को मंथली पहुंचाने का समय था परंतु जैसे ही हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की सरकार को तिलांजलि दी, उसी समय से इन रसूखदार लोगों की मंथली खत्म हो गई थी। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हुआ है। मेरा सीधा–सीधा कहना है कि जो इस प्रदेश के अंदर पुरानी सरकारें रही हैं, वे भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं लेकिन तोता कपास के पहाड़ में से निकल जायेगा, कपास की ढेरी में से निकल जाएगा तो कौन–सी अपनी रजाई बनवा लेगा। उपाध्यक्ष महोदया, पुरानी सरकारों में बहुत ज्यादा अनदेखी की गई है और पूरे प्रदेश के कोने–कोने को बेचने का काम किया गया था। चाहे थाना हो, तहसील हो, बी.डी.ओ ऑफिस हो, कॉर्पोरेशन का ऑफिस हो या कमेटी का ऑफिस हो, सभी विभागों में अपने हिस्से रखे हुए थे। (विघ्न) अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी बता रहे थे कि गड्ढ़े यहीं छोड़ दो, क्योंकि उनको और गड्ढा खोदना है ताकि नीचे उनको और मेहनत न करनी पड़े। हमारी सरकार

ढाई साल में इन गड्ढ़ों को भर देगी तो आने वाली सरकार को नए सिरे से भ्रष्टाचार के मामले सोचने पड़ेंगे। जो बिजली की उपलब्धता की बात है, (शोर एवं व्यवधान) नागर साहब आप अपनी चिंता करो, उसके बाद दूसरों की कर लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, मुझे भी इस बारे में अपनी बात कहनी है (शोर एवं व्यवधान)।

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदया, हमारे बहुत अच्छे साथी श्री ललित नागर जी फरीदाबाद के तिगांव से विधायक बनकर आये हैं। अभी फरीदाबाद नगर–निगम के चुनाव थे, उनमें 40 वार्डों में से 30 पर कमल का फूल खिला है और इंडीपेंडेंट 9 खिलें, उनमें भी भाजपा कार्यकर्ता ज्यादा थे। इसी तरह भिवानी नगर–निगम चुनाव में हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, इस बार होली का त्यौहार 12 मार्च को है। उत्तर से दक्षिण तक, मणिपुर से लेकर उत्तराखंड तक बी.जे.पी. की लहर होगी। आज बहन किरण चौधरी जी यहां नहीं बैठी हैं, मैंने पहले भी नाम नहीं लिया था और कहा था कि एक साइकिल पर 2 छोरे बैठे थे, वो साइकिल पंक्चर हो गई है । मैडम, आप देखना इस बार जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं वहां कमल का फूल ही खिलेगा। लोगों ने पहले ही केसरिया रंग बाजारों में भर दिया है। इस बार ललित नागर को होली के दिन मैं गुलाल से रंग कर आऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा :– उपाध्यक्ष महोदया, ललित जी का जो डी.एन.ए. है वह कांग्रेस पार्टी के विरोध का है और बेरंग है । मैं इनको, गंगवा जी को, संधू साहब को और डाक्टर कादियान जी को कहना चाहूंगा कि–

पुरानी यादों के उजालों को आखों में महफूज रखना,

दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी,

फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी ।

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत विद्वान और सीनियर मैंबर हैं । मंत्री जी ने जो नगर निगम के चुनावों की बात कही है कि फरीदाबाद, भिवानी आदि शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस और इनैलो पार्टी ने अपने कैंडीडेट्स खड़े ही नहीं किए थे । अकेली भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही थी । इसमें तो इनकी जीत होनी ही थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्ष के साथी पहले ही रणछोड़ हो गये थे क्योंकि इनको मालूम था कि इनकी जीत नहीं होनी ।

उपाध्यक्ष महोदया : नागर जी, प्लीज आप बैठें । आपको बाद में बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्ष के साथी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जबकि मैं इनको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार प्रदेश में फिर से बनेगी । मैं इनको कहना चाहूंगा कि–

तेरी मोहब्बत भी किराये का घर थी,

कितना भी सजाया, अपना नहीं हुई ।

विपक्ष के साथी मेरी इस बात को समझ लें । इनको आज जो कुर्सी मिल गई वह आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी कुर्सी किराये के घर जैसी ही है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं बिजली की उपलब्धियों के बारे में जिक्र कर रहा था । आज प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 23 से साढ़े 23 घंटे बिजली दी जा रही है । जहां पहले गांवों में 6 से 8 घंटे बिजली दी जाती थी वहीं आज लगभग 15 से 18 घंटे गांवों में बिजली दी जा रही है । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, 20 फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे गांवों में बिजली दी जा रही है । यह रिकार्ड की बात है । अखबार केवल हमारे विपक्ष के साथियों के पास ही नहीं आते बल्कि हमारे पास भी आते हैं । आज पंचकूला ऐसा जिला है जहां पूरे जिले में 24 घंटे बिजली दी जा रही है । पंचकूला यहां से दूर नहीं है मेरे विपक्ष के साथी वहां जाकर पता कर सकते हैं ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, पंचकूला शहर के अंदर तो पहले भी 24 घंटे बिजली मिलती थी । इसमें नई बात नहीं है ।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय संधू साहब को बताना चाहूंगा कि मैं केवल पंचकूला शहर की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे पंचकूला जिले की बात कर रहा हूं जिसमें गांव भी आते हैं । पिछली सरकारों के समय में बिजली को लेकर बिजली स्टेशनों पर मेले लगते थे और बिजली न मिलने के कारण लोग सड़क जाम कर देते थे लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लोगों को ठीक से बिजली दी जा रही है जिसके कारण कहीं कोई जाम नहीं लगता । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमारी सरकार ने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए स्कूलों की बेहतरी के लिए भी बहुत कदम उठाये हैं । अम्बाला शहर में 4 सरकारी स्कूलों के अंदर देश में पहली बार स्मार्ट इंट्रैक्टिव वर्चुअल क्लास रूम चलाने का कार्य किया गया है जिसमें 1500 बच्चे साईंस और मैथ्स की शिक्षा ले रहे हैं। जहां पर आकाश और फिटजी संस्थाओं जैसी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं । सरकारी स्कूलों में ऐसा देश में पहली बार हमारे अंबाला शहर में हुआ है । यह सब शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है जिसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं । जिसके लिए यदि किसी ने ट्रायल लेना है तो नन्योला, पुलिस लाईन और प्रेम नगर में जो स्कूल हैं उनमें जाकर कभी भी देखा जा सकता है । इसी तरह से 21 नये महाविद्यालयों का एक दिन में शिलान्यास करके बजट में पैसे का प्रोविजन किया गया है । ऐसा भी प्रदेश में पहली बार हुआ है ।

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । (विघ्न)

(शिक्षा मंत्री) श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, एक माननीय सदस्य पहली बार मैंबर बनकर आया है जो कि बहुत अच्छी बातें सदन में रख रहा है । गंगवा जी एम.पी. रहे हैं और विधायक भी हैं लेकिन एक नये मैंबर को बोलने नहीं दे रहे । मेरी इनसे विनती है कि ये अपनी बारी आने पर बोलें । इस तरह से किसी सदस्य को डिस्टर्ब न करें । यह प्रश्नकाल नहीं है । This is not the question hour.

श्री सुभाष बराला : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, गंगवा जी को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि इनकी पार्टी के माननीय विधायक श्री बलवान सिंह जी के हल्के में सरकार द्वारा एक कालेज खोला गया है जिसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान) चेयर की परमिशन के बिना जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। असीम जी, आप कृपया कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया जी, हैपनिंग हरियाणा को लेकर इस सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है। जिन प्रवासी हरियाणावासियों ने विदेशों में जाकर अपने व्यापार का लोहा मनवाया उन सभी को अपनी जड़ों से वापिस जोड़ने के लिए हैपनिंग हरियाणा नाम से हरियाणा प्रवासी प्रोग्राम का आयोजन सरकार के स्तर पर किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : सभी माननीय सदस्यगण, कृपया सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी माननीय सदस्यगण बिना चेयर की परमिशन के न बोले। (शोर एवं व्यवधान) जो माननीय सदस्य चेयर की परमिशन के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) असीम जी, आप कृपया जल्दी वाईंड–अप करें। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में बात न करें। (शोर एवं व्यवधान) असीम जी, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma : Madam Deputy Speaker, Smt. Kiran Chaudhary is our Hon'ble C.L.P. Leader. She is so senior most. Our party MLA Shri Aseem Goel is speaking very well. This is not a good practice. किसी भी दृष्टि से यह अच्छी बात नहीं है कि सदन के कुछ सम्मानित सीनियर सदस्य नये सदस्यों को अपनी बात न कहने दें और बार–बार बिना किसी वजह के डिस्टर्ब करें। सीनियर सदस्यों को यहां पर एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि नये सदस्य भी उनका अनुसरण कर सकें। कुछ माननीय सीनियर सदस्य सदन में कभी भी क्वैश्चन ऑवर की स्थिति पैदा कर देते हैं और आपस में ही सवाल–जवाब करना शुरू कर देते हैं। यह एक अच्छी परम्परा कभी नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदया : असीम जी, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं अपनी बात कंक्ल्यूड करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरियों में जो दंश क्षेत्रवाद का–भाई–भतीजावाद का हमारी सरकार आने से पहले चलता था । पिछली सरकारों के समय में पैसे और सिफारिश के बल पर ही नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भर्ती पूरी तरह से ट्रांसपैरेंट पॉलिसी के तहत की जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से हरियाणा सरकार में तीन उम्मीदवारों की एच.सी.एस. के पद पर भर्ती हुई है। इसके बाद मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे यह पूछा कि क्या मैं उनके घर पर बधाई देने के लिए गया? मैंने कहा कि बाबू जी मैं नहीं गया। इस पर उन्होंने मुझे फिर से कहा कि मैं वहां पर जाकर आऊं। मैं जब वहां पर गया तो मैंने यह पाया कि उनमें से जो एक उम्मीदवार है वह बेटी है जो कि इस समय दिल्ली पुलिस में ए.सी.पी. के पद पर कार्यरत है। उसका हरियाणा प्रदेश में एच.सी.एस. के पद पर सिलैक्शन हुआ है। मुझे बताते–बताते उसकी मां के आंसू निकल आये। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी बेटी का चौथा अटैम्पट् था। हमारे पहले तीन अटैम्पट पुरानी सरकारों के समय के थे। उस समय न हमारे पास किसी की सिफारिश थी और न ही रिश्वत देने के लिए पैसा था इसलिए उनकी सलैक्शन नहीं हो पाई लेकिन यह पहली ऐसी सरकार आई जिसमें न तो हमने किसी को सिफारिश की और न ही किसी को कोई पैसा दिया इसके बावजूद भी मेरी बेटी की सलैक्शन हो गई। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि पहले तीन अटैम्पट में किन्हीं कारणों से सफल न हो पाने के कारण उनकी बेटी ने बड़े अनमने मन से इस बार का एग्जाम दिया था। उसे यह डर था कि पता नहीं इस बार भी वह सिफारिश और रिश्वत के अभाव में असफल न हो जाये लेकिन जब एच.सी.एस. के एग्जाम का रिजल्ट आया और मेरी बेटी का सिलैक्शन हुआ तो हमारे पास आपकी सरकार को धन्यवाद करने के लिए काई शब्द नहीं हैं। हमारी सरकार ने ट्रांसपैरेंसी को पूरी तरह से लागू किया है। जिस प्रकार से हमारी सरकार के समय में आम जन का बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है। जो पहले सरकारी पदों पर भर्तियां होती थी उनमें से भ्रष्टाचार की बदबू आती थी। हमारी सरकार द्वारा आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता की व्यवस्था को लागू किया गया है। मैं इतनी बात कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

बोलने के लिए समय दिया। इसी के साथ मैं दो लाईनें जरूर अपनी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा कि :–

बहादुर कब किसी का आसरा–अहसान लेता है,
वो कर गुजरता है जो दिल में ठान लेता है।
और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती,
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।।
धन्यवाद। जय हिन्द। जय हरियाणा।

श्री तेजपाल सिंह तंवर (सोहना) उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । यहां पर 2–2 पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं । हम तो पहली बार चुन कर आये हैं । जिस तरीके से आज हमारी विधान सभा चल रही है उससे वास्तव में दुख होता है क्योंकि जिस तरह की बात हम सभी लोगों को करनी चाहिएं वे बातें हम नहीं कर पा रहे हैं । हमारी 13वीं विधान सभा का यह 8वां सत्र है लेकिन जिस तरह से हमारे बड़े–बड़े नेता, अच्छी–अच्छी बातें करने वाले नेता यहां पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वे हमारी समझ से बाहर की बातें हैं । मैं सबसे पहले एस.वाई.एल. नहर पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । एस.वाई. एल. नहर का मुद्दा बहुत पुराना है और इसके लिए बहुत से नेताओं ने संघर्ष किया है चाहे वे चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे चौधरी बंसी लाल जी हों या डॉक्टर मंगल सैन जी हों, सभी ने अपने–अपने प्रयास किये हैं लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया । उपाध्यक्ष महोदया, हम भी काफी दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं । यहां पर भले ही हम पहली बार चुन कर आये हैं लेकिन हमने मजदूरों की राजनीति की है, हम गरीब किसानों में भी रहे हैं और सभी के साथ मिल कर कार्य किये हैं । प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तथा हमारी सरकार को बने लगभग अढ़ाई साल होने वाले हैं । मैं अपने सभी विधायकों से कहना चाहता हूं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छे कार्य हों । हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं और न ही हम दोषारोपण करने आये हैं । हम यह कह रहे हैं कि हमने कुछ काम किये हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। अगर दूसरी पार्टियों के नेता हमें कुछ सुझाव दें कि यहां पर गलत काम हो गया है इसको ठीक करो तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे । हम यहां पर बैठ कर और अच्छी–अच्छी विचारधारा वाले हमारे जो नेता हैं वे अगर ऐसी बात

करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस प्रदेश को जो देना चाहते हैं क्या वह दे रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने कई अच्छे–अच्छे कार्य किये हैं अगर कोई उनको अच्छा न समझे और उनकी खिल्ली उड़ाए तो यह अच्छी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि उन कार्यों में कोई दिक्कत है या कमी है तो उसको सुधारें और अच्छे सुझाव दें तो अच्छा काम होगा । एस.वाई.एल. नहर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है और मुझे लगता है कि अब यह मामला 100 प्रतिशत सुलझ जायेगा तथा एस.वाई.एल. नहर का पानी हमारे दक्षिण हरियाणा में अवश्य पहुंच जायेगा । हमें पूरा भरोसा है कि हम एस.वाई.एल. नहर का पानी लेकर आयेंगे तथा इस कार्य की शुरूआत हो चुकी है । अब इसमें कोई देरी नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दे दिये हैं कि हरियाणा के लिए एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करवा कर पानी हरियाणा में पहुंचाया जाये । अब हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमें एस.वाई.एल. नहर का पानी जरूर मिलेगा । हमारी सरकार ने कई अच्छे–अच्छे कार्य किये हैं चाहे वे किसानों के लिए हों चाहे गरीबों के लिए हों । चाहे हॉस्पिटल के लिए हों चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हों या बिजली के क्षेत्र में हों, हम सभी क्षेत्रों में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं । इसी प्रकार से जहां तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात है तो हम उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं । यह भ्रष्टाचार का कुंआ आज प्रदेश में इतना गहरा हो गया है कि उसको साफ करने में वास्तव में कुछ समय लगेगा इसमें कोई दो राय नहीं है । आज हरियाणा प्रदेश के कई नेताओं पर संगीन आरोप भी लगे हैं और वे उनकी सजा भुगत रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कई और नेताओं को भी भुगतना पड़ सकता है । अगर हम भी ऐसी गलती करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। जो भी इस प्रदेश के साथ अत्याचार और अनाचार करेगा उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी । आज इस प्रकार की घटना न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी देखी जा सकती हैं कि जो बहुत बड़े–बड़े नेता थे उनको जेल की हवा खानी पड़ी है । उनको जेल का खाना भी खाना पड़ा क्योंकि उनको लम्बी–लम्बी सजा हुई हैं । उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं बुढ़ापा पैंशन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । पहले की सरकारें इसके लिये थोड़े–थोड़े रूपये बढ़ाती थी लेकिन हमारी सरकार ने बुढ़ापा पैंशन को सीधा दो हजार रूपये कर दिया है। अब मैं किसानों के मुआवजे की बात करता हूं कि जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो पिछली

सरकारें किसानों के मुआवजा राशि में केवल पांच–पांच रूपये ही बढ़ाती थी और किसानों को मुआवजा राशि के रूप में पांच–पांच रूपये के चैक मिलते थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : तेजपाल जी, आपकी सरकार ने बुढ़ापा पैंशन दो हजार रूपये कहां बढ़ाई है?

श्री तेजपाल तंवर : बहन जी, आप देख लेना यह बुढ़ापा पैंशन कुछ दिनों में दो हजार रूपये हो जाएगी । आप शांति रखो, हमारी सरकार ने दो हजार रूपये बुढ़ापा पैंशन देने की बात कह रखी है । जहां तक बिजली की बात है । हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कई नये पावर हाऊसिज लगाये हैं जिससे गांव में जो बिजली की दिक्कत थी वह दूर हो गई है । हमारी सरकार ने बिजली को दुरूस्त करने के लिये कुछ बड़े पावर हाऊस भी लगाये हैं । हमारी सरकार ने 33 के.वी.ए., 66 के.वी.ए. और 220 के.वी.ए. के सब–स्टेशंज लगाए हैं ताकि हमारे सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो सके । हमारी सरकार ने खम्बों की लाईने खिंचवाने का काम भी किया है और जो तारें जर्जर हो गई थी उनको ठीक करके उनको जुड़वाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से हो सके और हमारे गांवों और शहरों में ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके । हमारे जिन गांवों में पीने के पानी की किल्लत थी । वहां जो पीने के पानी की सप्लाई के लिये पाइप थे उन पाईपों से हमें गन्दा पानी पीने को मिलता था । हमारी सरकार ने हमारे क्षेत्र के कई गांवों की पीने के पानी की पाईप लाईनें बदलवाने का काम किया है ताकि वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। हमारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिये हमारी सरकार ने अस्पताल खोलने की कोशिश भी की है । लेकिन हम यह मानते हैं कि आज भी हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत कमी है । यह कमी इसलिये है क्योंकि डॉक्टर लोग सरकारी अस्पतालों में लगना नहीं चाहते क्योंकि उनको प्राईवेट अस्पतालों में ज्यादा तनख्वा मिलती है और हमारे सरकारी अस्पतालों में कम तनख्वाह मिलती है । मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में अच्छे–अच्छे डॉक्टरों की भर्ती की जाए ताकि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत सुधरे । हमारे प्रदेश में और भी कई चीजों की दिक्कत है । उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में जो नौजवान शहीद हो जाते थे उनको पहले की सरकारों के समय कुछ नहीं मिलता था लेकिन आज हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रूपये देने का प्रावधान किया

है। **(विघ्न)** इसमें कोई झूठ की बात नहीं है । पिछली सरकार के समय में शहीदों के परिवारों को 20 लाख रूपये दिये जाते थे लेकिन अब हमारी सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रूपये कर दिया है । अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने ये पैसे दिये हैं । हम अपने शहीदों का सम्मान करेंगे और कोशिश है कि उनके परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी जाए क्योंकि वे देश के रखवाले हैं । **(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए।)** जब वे देश की रक्षा के लिये सीमाओं पर बर्फ में खड़े रहते हैं उस समय हम अपने घरों में सुख चैन की नींद सोते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कुछ बातों को खिल्ली में न उड़ा कर के उसमें कुछ सुझाव दिये जाएं ताकि सरकार उन बातों को ठीक कर सके । आज हम प्रदेश के मुख्य नागरिक हैं । अगर हम कोई छोटी सी बात करते हैं तो उसकी हवा पूरे प्रदेश में जाती है । हमारे किसानों की हालत पीछे बहुत खराब रही । जब ओले पड़े और बारिश से किसान की खेती खराब हो गई तो हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को काफी मुआवजा दिया और आगे के लिये फसल बीमा योजना बनाई । अगर फसल बीमा योजना में कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा भी है कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं । आप लोगों ने ज्यादा राजनीति की है । हमें तो अभी ढ़ाई साल ही हुए हैं इसलिये हमें राजनीति का तजुर्बा कम है इसलिये हमें आपके तजुर्बे की भी जरूरत है । इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जो हमारी सरकार गरीबों के लिये करना चाहती है। हमारे प्रदेश में बसों की बड़ी भारी कमी थी और हमारे सारे रोड्ज टूटे पड़े थे। हमारे सभी पुल टूटे हुए थे उन सबको हमारी सरकार ठीक कर रही है । आज पूरे प्रदेश में कहीं भी भेदभाव की बात नहीं है । हमारी पार्टी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, इसलिये हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम होगा । (हंसी) इसमें हंसने की तो कोई बात है ही नहीं । हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी 90 विधान सभाओं में जाकर के सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिये समान पैसे दिये हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र में गये हैं अगर उस क्षेत्र का विधायक वहां नहीं गया तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको नहीं बुलाया । मुख्यमंत्री जी ने तो उस क्षेत्र के विधायक को जरूर बुलाया होगा लेकिन वह जान बूझकर नहीं गये क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि वहां बी.जे.पी. पार्टी का मुख्यमंत्री आ रहा है लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तो सबका होता है और वह किसी एक पार्टी का नहीं

होता । **(विघ्न)** अगर हमसे कोई गलती होती है तो आगे हम उसको सुधारेंगे । आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम भी अपील करेंगे कि आगे जिस भी क्षेत्र में वे जायें तो वहां के विधायक को अपने प्रोग्राम्ज में जरूर बुलायें ताकि उस क्षेत्र की जो भी समस्यायें हैं, उनके उपर गौर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकास के क्षेत्र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भी विधायक उनके पास जाते हैं, चाहे वह पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी की बातों को ठीक से सुनते हैं और यथासंभव काम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अब ज्यादा कुछ न बोलते हुए, मैं आप सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि इस महान सदन के सदस्य हैं, अतः आपको अच्छी तरह व सोच समझकर जनता की भलाई के कार्य करने चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी बात को बड़ी ही शांति के साथ सुना। आप सबका बहुत –बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ढुल साहब, अब आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो उतना समय आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों के बोलने के समय से काट लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविंन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लिए तो आप बहुत मेहरबान हो रहे हैं और जब विपक्ष को बोलने का समय देते हैं तो कंडीशंज लगा दी जाती है। यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः संधू जी, इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आप देखिये आपके नेता प्रतिपक्ष बोले तो मैंने उनको बोलने के लिए पूरा समय दिया। वे 66 मिनट तक बोले, जगबीर मलिक जी 80 मिनट तक बोले यह तो विपक्ष की बात रही और अब मैं आपको सत्ता पक्ष के बोलने के समय के बारे में बताता हूँ। असीम गोयल जी को बोलने के लिए 26 मिनट तथा तेजपाल तंवर जी को 11 मिनट दिए गए है। मैं आपको दूसरे सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए दिए गए समय के बारे में भी बता सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए जितना समय बोलने के लिए सत्ता पक्ष को दिया जायेगा उतना ही समय विपक्ष को भी दिया जायेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब आप अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ समय की खुद मैनेजमैंट करो। यदि सभी सदस्य 6–6 मिनट बोलेंगे तो संभव है कि सब सदस्यों

को बोलने का बराबर समय मिलेगा और सब सदस्य अपनी बात अच्छी तरह से रख सकेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर कोई विशेष बात देखने को नहीं मिली। आज प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ यूनियन के लोग मुझसे आकर मिले हैं चाहे वह आशा वर्कर्ज यूनियन हो, भवन निर्माण व कामगार यूनियन हो, पुलिस कर्मचारी यूनियन हो सबके सब सरकार से दुखी हैं और उन्होंने दुखी होकर मुझे अपनी समस्या के बारे में लिखकर रैजोल्यूशंज भी दिए हैं कि सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। सांतवां पे–कमीशन देने के बाद भी पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह को कम कर दिया गया है जिससे उनमें रोष व्याप्त है। आज प्रदेश का किसान मजबूर होकर सड़कों पर आ चुका है। आलू की फसल की कीमत और पॉपुलर की हालत बहुत विकट स्थिति में पहुंच गई है जिसकी वजह से किसानो में रोष फैल चुका है और यह धारणा घर कर गई है कि न जाने किस प्रकार की यह सरकार आई है? महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने के उपरांत भी कुछ नहीं मिला। यह आज क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी स्वयं अभिभाषण को पढ़ने से इंकार कर दिया और पढ़ा हुआ समझ लिया जाये कहकर चले गये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के तहत महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, ग्रामीण विकास और शहरी विकास संबंधी योजनाएं को नव ग्रह का नाम दिया है। मेरा ख्याल है कि नव ग्रह लिखते ही इन पर राहू की टेढ़ी नजर लग चुकी है। अब इस नव ग्रह की किस प्रकार से पार पड़ेगी यह तो भगवान ही जाने? अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना की शुरूआत के समय बहुत ही बढ़ा–चढ़कर तारीफ की गई थी। सदन में जब यह कहा गया कि फसल बीमा योजना को और अधिक सार्थक बनाने की दिशा में सुझाव दिए जायें तो मुझे वह बात याद आ गई जो मैंने पिछले सैशन में कही थी। पिछले सैशन में जब कृषि मंत्री जी फसल बीमा योजना के बारे में बता रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि इस योजना पर सदन में एक बार चर्चा करवा ली जाये ताकि इस योजना के संबंध में सदन के सभी सदस्यों के सुझाव सामने आ सकें। आज जब यह योजना कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है तो फिर दुखी हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत 44% क्लेम पैंडिंग पड़े हुए हैं। इसका सीधा सा कारण है कि योजना में कहीं न कहीं कमियां जरूर हैं। फसल बीमा योजना के द्वारा प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा राशि चार्ज की जाती है। इस योजना के तहत जब नुकसान का आकलन करते हैं तो पूरे गांव में खराब हुई फसल के नुकसान को इकाई माना जाता है। यह सबसे बड़ी खामी इस योजना की है और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। अगर किसान से एक एकड़ के हिसाब से बीमा राशि चार्ज की जाती है तो खराब फसल का आकलन भी प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। अगर खराब फसल का नुकसान पूरे गांव को इकाई मानकर किया जायेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। (विघ्न)

कृषि मंत्री(श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खराब फसल का मुआवजा दने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह बात समझ में नहीं आयेगी तो इससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जायेगा। किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। यदि किसी बात को गलत समझ लिया गया तो उसके गम्भीर परिणाम निकलते हैं। फसल बीमा योजना सभी प्रकार से किसान के हित व फायदे की योजना है। अतः मैं माननीय ढुल साहब को इस योजना के फायदे के बारे में बताना उचित समझता हूँ। यदि यह स्वयं इस योजना की बाबत कंफ्यूज्ड हैं तो सीधी सी बात है यह इस योजना की वास्तविकता के बारे में लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पायेंगे। इस योजना में दो तरह की यूनिट्स हैं और इनको हम सबको समझना चाहिए क्योंकि कोई बात जब हमारी समझ में अच्छी तरह से आती है तभी जाकर हम उस बात को जनता के बीच में अच्छी तरह से बता पायेंगे। (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः मंत्री जी, अगर मैं एक बार सारी बात कह दूं तो आप उसके बाद आप कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ढुल साहब, किसान के फायदे की बात है अतः मंत्री जी को अपनी बात रखने दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दो बातें बताना चाहता हूं । ये दोनों ही बातें किसान के फायदे की हैं । अगर खेत में पानी भरा है, ओलावृष्टि हुई है या अनसिजनल बारिश हुई है तो एक खेत इकाई है । जिस किसान के खेत में कोई ऐसी घटना होती है तो उसे तुरंत एस.

डी.एम. को सूचना देनी चाहिए । (विघ्न) इसकी अथॉरिटी एस.डी.एम. है और एस. डी.एम. को इसकी 48 घंटे में रिपोर्ट लेने की जिम्मेवारी दी गई है । खेत में इंस्पैक्शन के समय एस.डी.एम. के साथ तहसीलदार और डिप्टी डायरैक्टर एग्रीकल्चर भी जाएंगे । चाहे 5 एकड़ खेत में पानी भरा हो, 7 एकड़ खेत में भरा हो, 10 एकड़ खेत में भरा हो, 25 एकड़ खेत में भरा हो, 25 एकड़ खेत में ओले पड़े हों या चाहे कितने खेत में भी पड़ें उस सबका एस.डी.एम. जो नक्शा बनाकर देगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी । उस रिपोर्ट के हिसाब से किसान को फसल के नुक्सान का पैसा मिलेगा । इस बार 9 करोड़ रूपये मुआवजा हमने दिया है । (विघ्न) ओलाग्रस्त खेत भी एक एकड़ इकाई माना गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह संधू जी, आपने किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा नहीं देखा । मुआवजा इसी हिसाब से मिला है । गांव में अगर एक एकड़ खेत खराब था तो उसका भी मुआवजा दिया गया है । (विघ्न) मुआवजा ऐसे ही दिया गया है । मेरे इलाके में पानी भरा हुआ था इसलिए मुझे इसकी अच्छी तरह से जानकारी है । (विघ्न) किसानों को काफी ज्यादा मुआवजा मिला है । हम आपको खराब फसल का मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, ...(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मलिक साहब, मुआवजे के संबंध में आप मेरे पास आकर डिस्कस कर लेना । मैं और आप दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगे और इस संबंध में प्वायंट टू प्वायंट डिस्कस कर लेंगे । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को फसल बीमा के लिए ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे किसान खुद अपनी फसल का बीमा करवा सके । इसके लिए किसान को किसी भी प्रकार से फोर्स न किया जाए । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इन तीनों तरह से होने वाले नुक्सान पर एक खेत इकाई है । इस बार किसानों को 9 करोड़ रूपये से ज्यादा मुआवजा इसी तरह से होने वाले नुक्सान का दिया गया है । दूसरी तरह का जो मुआवजा है वह पूरे गांव का इकट्ठा है और अब पूरे गांव में गिरदावरी नहीं की जाएगी । बलवान सिंह जी, पूरे गांव से केवल 4 सैम्पल लिए जाएंगे और वे सैम्पल ए.डी.ए. के द्वारा लिये जाएंगे । एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का कृषि विकास

अधिकारी गांव से उन सैम्पल्स को लेने आएगा । उसको कहीं न कहीं हमने यह भी कहा है कि किसान की फसल जहां कमजोर हो वहां से सैम्पल्स लेना । अगर उन चार सैम्पल्स में यह नजर आ गया कि यहां 20 क्विंटल अन्न होना था और 15 क्विंटल अन्न हुआ है और इस तरह से किसान की फसल का उत्पादन 25 परसेंट कम हुआ है तो पूरे गांव को 25 परसेंट फसल के नुक्सान का कंपनसेशन मिल जाएगा फिर चाहे उसकी फसल कोई भी हो । इस तरह से पूरे गांव की फसल का औसत नुक्सान तय हो जाएगा । ये दोनों ही सिस्टम्ज बहुत अच्छे ढंग से विचार करके बनाए गए हैं । इनका किसान को अवश्य ही बैनीफिट होगा । अगर एक–एक खेत को इकाई मान लिया जाएगा तो फिर सारे गांव को फसल का मुआवजा नहीं मिल पाएगा । खेत में फसल का नुक्सान मुख्यतः तीन तरह से ही होता है । तीनों तरह से होने वाले नुक्सान के संबंध में पूरे गांव के खेत को एक इकाई मान लिया है । गर्म हवा निकलने से, पाला पड़ने से, लम्बी अवधि तक बारिश न होने से आदि जिन कारणों से पूरे गांव की फसल खराब होती है तो उसमें पूरे गांव को एक इकाई मान लिया गया है । यदि पूरे गांव में खराब फसल के केवल चार सैम्पल्स से पूरे गांव के किसानों की फसल का मुआवजा तय हो जाएगा तो वह अच्छी बात है । वह बुरी बात नहीं है । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आग लगने से क्षति होती है उसके बारे में क्या निर्णय लिया है ? (विघ्न) सरकार ने बागवानी के बारे मे क्या प्रीमियम रखा है ? उसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, अगर प्राकृतिक बिजली पड़ने से फसल में आग लगती है तो वह फसल बीमा योजना में शामिल है । बाकी दूसरी तरह से लगने वाली आग इस बीमा योजना में शामिल नहीं है । मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने बागवानी खेती को इस बीमा योजना के तहत नहीं लिया है । हम अगले सालों में बागवानी खेती को भी इस फसल बीमा योजना के तहत लेंगे ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि पिछले साल जो 3,229 क्लेम रिजैक्ट किये थे ये क्लेम किस कारण से रिजैक्ट किये गए थे ? (विघ्न) मुझे एक जानकारी और लेनी है कि पिछली बार फसल बीमा योजना के तहत कितने बीमा स्वेच्छा से करवाए गए थे और इस बार कितने बीमा स्वेच्छा

से हुए। पिछली योजना में कितने ऐसे किसानों की फसलों के बीमे किए गए जिनके पास ये चार फसले नहीं थी। पिछले साल गन्ना की फसल का बीमा भी जबरदस्ती किया गया और अब भी किया जा रहा है। मेरे हल्के के बहुत से किसानों की गन्ना की फसलों का बीमा जबरदस्ती किया गया है, जिनकी शिकायत उपायुक्त महोदय के माध्यम से डिप्टी डायरैक्टर के पास पैंडिंग पड़ी है। इस बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। चूंकि गन्ने की फसल इस योजना में कवर नहीं है जिसका सबको पता है। किसान बैंक का कर्जदार है, इसलिए उसका जबरदस्ती बीमा कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बीमा योजना नई नहीं है। बीमा योजना पिछली सरकारों में भी रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मैं भी पक्षधर हूँ उसमें भी कहा गया है कि फसल बीमा योजना लानी चाहिए। इस नई फसल बीमा योजना की खामियों को दूर करके किसान के हित के लिए योजना बनानी ही पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, बैंक का मैं भी कर्जदार हूँ और फसल बीमा मेरा भी कटा हुआ है। वर्तमान में यह योजना किसान के हित में नहीं है बल्कि किसान से जबरदस्ती पैसे लूटने का काम हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा मलिक साहब भी उठा रहे हैं और ढुल साहब भी उठा रहे हैं। एक बात समझिए कि इसमें बीमा पॉलिसी का संबंध कम है और बैंक की व्यवस्था का ज्यादा है। दुनिया में कोई भी किसी भी चीज का लोन लेता है तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक बिना बीमा किए बगैर लोन नहीं देता है। चाहे वह मकान का लोन हो, चाहे वह कार का हो, चाहे वह किस भी चीज का हो। जिस भी चीज का लोन अगर हम लेते हैं और बीमा होने की व्यवस्था उस बैंक की सीमाओं में है तो वह बैंक अपनी पूंजी को सुरक्षित करने के लिए कम्पलसरी बीमा करता ही करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः यह फसल बीमा का पैसा सरकार तो दे सकती है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः मलिक साहब, वह अलग विषय है। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन यह व्यवस्था बैंकिंग की है और वह अपनी पूंजी सुरक्षित करने के लिए बीमा करता है। दूसरी बात मलिक साहब सुन लीजिए कि जब हम यह योजना लेकर आए तो एक साल में 1095 करोड़ रूपये बीमा के रूप में देना पड़ा। दूसरी साल 295 करोड़ रूपये बीमा के रूप में देने पड़े। भगवान की कृपा से पिछले साल की

अपेक्षा इस साल हालात काफी अच्छे रहे। अगर पहली वाली हालत हो जाती तो सभी बीमा कम्पनियों को उतना पैसा देना पड़ता । लगभग 600 करोड़ रूपया इन कंपनियों को छत्तीसगढ़ में बीमा के रूप में देना पड़ा। बहुत मोटी राशि इन्हीं कम्पनियों को मध्यप्रदेश में देनी पड़ी है। आज हमको लग रहा है कि हमें बीमा की राशि कम मिली है लेकिन भगवान की कृपा से इस बार हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यदि किसानों की फसलों पर कोई भी संकट आयेगा तो जिस तरह से सरकार ने बड़ी रकम निकाल कर मुआवजे के तौर पर दी थी, उसी तरह बीमा कम्पनियों को भी बड़ी रकम निकाल कर बीमा के रूप में किसानों को देनी पड़ेगी। जहाँ हम केवल 12 हजार रूपये तक खड़े थे वहाँ अब 25 हजार रूपये तक मुआवजा के देने पड़ेंगे। बीमा की व्यवस्था उस समय काम में आनी की है जिस समय फसलों का नुकसान ज्यादा हो। यह व्यवस्था सरकार की नहीं है बल्कि बैंक की व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। दूसरा कारण यदि किसी ने बैंक से लोन ले लिया और कह दिया कि मैं गन्ना की फसल बोऊँगा तो बैंक ने गन्ने की फसल का बीमा कर दिया। सही जानकारी आपने बैंक को दी नहीं और किसान ने धान की फसल बो दी। जब धान की फसल के लिए लोन लिया तब किसान ने गन्ने की फसल बो दी। कई बार बैंक को सही जानकारी दिए बिना यह अंतर रह जाता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः मंत्री जी, मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ही कह रहा हूँ। आप चाहे तो एक व्यक्ति का मोबाईल नं0 9813105496 नोट कर लें। उससे आप फोन करके पता कर ले। मेरी उस व्यक्ति से बात हो चुकी है, वह कहता है कि उसने फसल चेंज करने के लिए 10 बार एप्लीकेशन दे दी लेकिन बैंक वाले भी नहीं सुनते और विभाग का एस.डी.ओ. कहता है कि मेरे पास अब इसको बदलने की पॉवर नहीं है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः ढुल जी, वह जानकारी मेरे पास पहुँचवाएं। अध्यक्ष महोदय, एक काम और अच्छा हमने किया कि सारे बैंकों में यह जानकारी पहुँचाई कि मान लो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है और मैंने क्रॉप लोन नहीं लिया तो मेरे बीमा के पैसे नहीं कटेंगे। मैंने अपनी सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, जब मुझे लोन चाहियेगा तब लोन ले लूंगा। यदि मैंने लोन नहीं लिया तो बैंक बीमा के पैसे नहीं काटेगा। यदि मैं अपनी मर्जी से कटवाना चाहूं तो वह अलग

बात है। यह व्यवस्था भी इसी से जुड़ी हुई व्यवस्था है। यदि इसमें सुधार नहीं हो रहा है और गड़बड़ी हो रही हो तो इस व्यवस्था को ठीक करवायेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, बिजली का बड़ा गुणगान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, आज बिजली के दाम बढाये जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली की स्थिति बड़ी खराब है।

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं ढुल साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः स्पीकर सर, सात बड़े पावर प्रोजेक्ट पानीपत, यमुनानगर, झज्जर, खेदड़, फरीदाबाद आदि जगहों पर लगे हुए हैं। उनकी टोटल कैपेसिटी 4720.7 मैगावाट है तथा वे 1597 मेगावाट बिजली जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब लगभग 18 प्रतिशत के हिसाब से हम जनरेट कर रहे हैं। मैंने सी.ए.जी. की रिपोर्ट में देखा है कि किस प्रकार बिजली निगमों के कुप्रबन्धन के कारण जो कर्जा बिजली निगम पर चढा हुआ था उसको उदय योजना के नाम पर जनता पर थोप कर जनता को ही भार दिया गया है इस प्रकार बिजली निगमों का घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। इन बिजली निगमों के कुप्रबन्धन के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि उनको मंहगी बिजली दी जा रही है तथा फ्यूल सरचार्ज लगाये जा रहे हैं। अपने कुप्रबन्धन के कारण बिजली निगम घाटे की पूर्ति बिजली के रेट बढ़ा कर की जा रही है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस प्रकार से यह बिजली का कुप्रबन्धन चल रहा है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आज बिजली निगम का कर्जा लगभग 30 हजार करोड़ से भी अधिक हो गया है, सरकार ने इसे अपने ऊपर भी ले लिया है। माननीय मंत्री जी, आपने रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट से लगभग 37 हजार कनैकशंज वे पैंडिंग कर दिए गए हैं जिन किसानों ने कई साल पहले अपनी सिक्योरिटी भरी हुई थी। डार्क जोन तो इस प्रदेश में शुरू से ही थे। सरकार ने टयूबवैल कनैक्शन लेने पर भी सिक्योरिटी में काफी वृद्धि की है और किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। नहर का पानी तो पहले ही नहीं आ रहा है। नहर का पानी भी धीरे–धीरे कम भी हो रहा है। पहली बार ऐसा कानून बना जो आपने 10 साल से पीछे से लागू कर दिया जबकि यह कानून आज के बाद से लागू होना चाहिए था पीछे से नहीं होना चाहिए। यह भी किसान के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पीछे

प्रदेश में काफी घोटाले चल रहे हैं जैसे ग्वाल पहाड़ी हो, चाहे मैट्रो रूट का हो तथा दूसरे घोटाले हों। पूरे घोटाले इस प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं। ग्वाल पहाड़ी का घोटाला तो 5 से 7 हजार करोड़ रूपये का है। सन् 1940–41 में यह जमीन शामलात देह की थी। उसके बाद 1989 में कलैक्टर गुड़गावं ने इस जमीन को मुस्तरका मालका में बदल दिया। दिनांक 28.12.2011 में नगर निगम, कमीशनर ने अपनी एप्लीकेशन दी की इस जमीन का इंतकाल निगम के नाम कर दो। इस पर तहसीलदार, सोहना ने उस जमीन का इंतकाल उनके नाम कर दिया। तब से इसमें घोटाला चल रहा है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रिट नं 3442 ऑफ 2014 में 24.2.2014 को पंजाब विलेज कामन लैंड एक्ट के तहत सैक्शन 13 के तहत कहा कि कलैक्टर महोदय इसका फैसला करें। कलैक्टर ने दिनांक 17.10.2014 को मालिकाना हक नगर निगम को दिया। फिर हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की कारगुजारी के चलते अंतिम आदेश 23.11.2016 को इंतकाल नं 3249 से नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा दिये गए। यह आदेश मैट्रो वैली नामक कम्पनी के प्राईवेट बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। यह किसके आदेश पर दिया गया ? इसके अन्दर हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्वाल पहाड़ी में 5 से 7 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है । यह किसकी जबावदेही है यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के घोटाले रोकने के लिए सरकार किस प्रकार की कार्रवाई करेगी?

श्री अध्यक्षः ढुल जी, सरकार इस बारे में जरूर जवाब देगी।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, जिस घोटाले की बात ये आज कर रहे हैं। इसके बारे में कल सदन में चर्चा की जाएगी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मुझे कल बोलने का मौका नहीं मिलेगा। (विघ्न)

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, कल इस बारे में जब चर्चा होगी उस समय ये अपनी बात कह लें (विघ्न)। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यावधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः सैनी साहब, मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। इस बारे में तथ्य मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कल दूसरे सदस्य इस बारे में तथ्य पेश करेंगे। मेरे पास इससे संबंधित सभी तथ्य हैं।

कोई भी मंत्री/अधिकारी मेंरे पास ये तथ्य आकर देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी यह सारा रिकार्ड मैंने अपने स्तर पर इकठ्ठा किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कल नहीं मैं आपको इन तथ्यों को अलग से आकर दे दूंगा।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहिए कि ये इन तथ्यों को कल ही लेकर आयें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, ढुल जी, आप वाइंड अप करें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी शहीदों के बारे में गुणगान किया गया है कि शहीदों के परिवारों को जो राशि दी जानी है वह सरकार ने 50 लाख कर दी है। मेरे हल्के में कैप्टन पवन खटकर और मेजर संदीप लाठर दो व्यक्ति शहीद हुए थे। कैप्टन पवन खटकर जब शहीद हुए थे तो उनके गांव में दो–तीन मंत्री गए हुए थे। वहां उस भदाना गांव ने 28 एकड़ जमीन भी दी थी कि इन शहीदों के नाम से वहां पर कुछ बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक साल हो गया, अभी तक वहां पर कुछ नहीं बनाया गया है। उसके पिताजी अपना तबादला करवाने के लिए काफी डिप्रेशन में थे। वह अपना तबादला करवाने के लिए 1 साल तक हर मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खटखटाता रहा। जब अखबारों में यह खबर छपी और हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर उनका तबादला हुआ। क्या यही शहीदों का सम्मान है? मेरे हल्के के मेजर संदीप लाठर जब शहीद हुए उस समय हमारे को–ऑपरेटिव मिनिस्टर वहां गए थे, मैंने भी यह खबर अखबार में पढ़ा था। तो वहां पर गांव वालों ने मांग की थी कि मेजर संदीप लाठर शहीद हुए हैं, इनकी यादगार में गांव में एक स्टेडियम बना दिया जाए तो मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए जमीन दे दीजिए। गांव वालों ने जमीन भी दे दी परन्तु अभी तक उनकी कोई यादगार में कुछ नहीं बना है। नौकरियां देने के लिए भी आज उनके परिवारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। मेरी आपसे मांग है और मैं यह सुझाव भी देता हूं कि शहीदों के परिवारों को नौकरी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को देखते हुए दी जाए ताकि उनको सम्मान प्राप्त हो। अगर हम शहीदों के परिवारों को नौकरी नहीं देंगे तो हम शहीदों का किस प्रकार से सम्मान करेंगे। जब तक हम शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी।

श्री अध्यक्ष : परमिंद्र ढुल जी आपके 10 मिनट हो गए। अब 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करो।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की बात करना चाह रहा हूं। पीने के पानी की समस्या है तो पूरे हरियाणा में लेकिन मेरे हल्के के अंदर बहुत भयंकर है, 50 गांवों में पीने का पानी नहीं है। अभी गुणगान हो रहा था कि पिछले 23 मई को मुख्यमंत्री जी हर हल्के में गए, मेरे हल्के में भी आये थे। बाकी सब हल्कों में तो बड़ा फायदा हुआ होगा लेकिन जब मेरे हल्के में आये तो साथ इतना बड़ा तूफान लेकर आये कि कम–से–कम 25 से 30 करोड़ का नुकसान हुआ। ये आप पता कर लें, मंत्री जी को भी पता है और मुख्यमंत्री जी को भी पता है। उससे एक हफ्ता पहले निडाना गांव के अंदर धानकों के 7 लड़के पीने के पानी के कुएं में केवल सफाई करते हुए मरे थे। आज उसी गांव की हालत बहुत दयनीय है, इतना समय बीतने के बाद भी उस गांव के अंदर आज भी कैंसर के 16 मरीज हैं और 7 की डैथ हो चुकी है। जो मरीज हैं उनकी हालत खराब है। इसी प्रकार दर्जनों गांवों में पीने के पानी के अभाव की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री ललित नागर (तिगांव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, जब राज्यपाल महोदय जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा तो वह काफी लम्बा था। 127 उसमें कॉलम थे और पढ़ते–पढ़ते उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत तरक्की हो रही है और हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर उस अभिभाषण को सुनता या पढ़ता है तो ऐसा ही लगता है कि हां हरियाणा प्रदेश में बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हरियाणा प्रदेश में अगर हम धरातल पर देखते हैं तो कोई ऐसा खास काम नहीं, जिससे हरियाणा प्रदेश सरकार की कोई ख्याति हो रही हो या उसकी कोई वाहवाही हो रही हो। मैं बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 वर्ग हैं जिनमें एक किसान वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, एक कर्मचारी वर्ग है और एक व्यापारी वर्ग है। आज ये चारों के चारों वर्ग बहुत ही दुखी है और सड़कों पर है। आज इन वर्गों की ये हालात है कि हर एक आदमी यह कहता है कि इस सरकार ने जितने गलत काम किए हैं, जितने हम इस सरकार से दुखी हैं, अब से पहले उतने दुखी नहीं थे। आज यह चारों वर्ग बहुत बुरी तरह से दुखी है।

हम अगर हरियाणा के किसानों की बात करते हैं तो किसान बिजली के लिए परेशान है। अभी सत्तापक्ष के किसी साथी ने कहा था कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली कई गांवों में दी जा रही है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी गांव में 6 से 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही । चाहे ट्यूबवैल को बिजली देने की बात हो चाहे घरेलू बिजली की बात हो । इसी तरह से किसानों को भी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं । न तो किसानों को समय पर बीज मिल रहा है, न खाद मिल रहा है । इसी तरह से किसानों को पॉपुलर, गन्ने, गेहूं और धान आदि का सही मूल्य नहीं मिल रहा है । सब्जियों की हालत तो बहुत खराब हो रखी है । सही भाव न मिलने के कारण किसानों को सब्जियां सड़कों पर डालनी पड़ रही हैं । अध्यक्ष महोदय, दूसरा मजदूर वर्ग आता है । जब से केन्द्र सरकार ने नोट बंदी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मजदूर वर्ग भी बहुत दुखी है । इसका कारण यह है कि प्रदेश में फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं । फैक्ट्रीज बंद होने के कारण गुरूग्राम और फरीदाबाद में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं । छोटी–छोटी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई हैं और उन्होंने मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है । जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होकर घरों में बैठें हैं।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, नोट बंदी के बारे में माननीय साथी ने जिक्र किया है । इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जिन फैक्ट्रीज ने मजदूरों को नोट बंदी के बाद निकाला है उसकी लिस्ट सदन में दें । माननीय सदस्य गलत ब्यानी कर रहे हैं ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, लाखों मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है यह बात बिलकुल सही है । इसी तरह से तीसरा कर्मचारी वर्ग आता है । जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है । आज गैस्ट टीचर्ज और कम्प्यूटर टीचर्ज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं । सरकार उनकी बात नहीं सुन रही । इसी तरह से सभी कर्मचारी सरकार से असंतुष्ट हैं । आज हालत यह है कि प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं । सरकार कर्मचारियों को तरह–तरह की सौगातें देने की बात कर रही है लेकिन कर्मचारी वर्ग सरकार से दुखी है । अध्यक्ष महोदय, चौथा व्यापारी वर्ग आता है । आज व्यापारी वर्ग भी सरकार से दुखी है । हम सभी सौचते थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है लेकिन सच्चाई यह है कि आज

व्यापारी वर्ग भी दुखी है । चाहे जूते वाला है, चाहे पनवाड़ी है, चाहे कपड़े वाला है और चाहे नाई है यानि हर व्यापारी सरकार की नीतियों से दुखी है । जो बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज वाले हैं वे भी आज दुखी हैं । जगह–जगह पर व्यापारी यह कहते हुए मिल जायेंगे कि जहां पहले उनकी सेल 10 हजार रुपये की थी वह कम होकर 2 हजार रुपये रह गई है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के क्रम संख्या–20 पर लिखा हुआ है कि सरपंचों को 5–5 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण लेने के बाद सरपंच गांवों में काम करवा रहे हैं । सरकार ने सरपंचों को प्रशिक्षण तो दे दिया लेकिन वे काम कहां से करवायेंगे । मैं अपने हल्के की बात करता हूं कि मेरे हल्के के सरपंचों को एक पैसा भी ग्रांट का नहीं दिया गया और न ही डिवैल्पमैंट के पैसे दिए गए फिर वे काम कहां से करवायेंगे ? पहले ही पंचायत के चुनाव एक साल बाद करवाये गये उसके बावजूद भी गांवों में ग्रांट नहीं दी जा रही तो वे काम कहां से करवायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के क्रम संख्या–22 में लिखा हुआ है कि 14 जिलों के सभी गांवों को इस महीने से खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज भी गांवों में मजदूर और गरीब लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं । सरकार की यह गलत जानकारी है कि 14 जिलों को शौच मुक्त कर दिया गया है । इसी तरह से राज्यपाल महोदय के क्रम संख्या–25 में लिखा हुआ है कि फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है । फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए हुए साल हो गया लेकिन वहां की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं और वहां के पार्क भी बहुत खराब हालत में हैं । आज फरीदाबाद शहर की हालत बहुत खराब है । सरकार जो दावा कर रही है यह केवल कागजों में है और सरकार अखबारों में खबर बनाने के लिए इस तरह के दावे कर रही है । वहां पर हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा । इसी तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के क्रम संख्या–30 में लिखा हुआ है कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था ठीक की गई है और टेल तक पानी पहुंचाया गया है । मेरे से पहले बोलते हुए हमारे माननीय साथी उदय भान जी ने होडल के बारे में जिक्र किया था कि किसी नहर में, किसी नाले में टेल तक पानी नहीं जाता। टेल तक पानी जाने के लिए नहरों और नालों की सफाई होनी चाहिए और दूसरी व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसी नहीं कोई भी ऐसा माईनर नहीं और कोई ऐसा नाला नहीं जो पूरी तरह से साफ हो जिससे कि पानी टेल के अंत तक चला जाये। आज के दिन टेल तक पानी पहुंचना असंभव हो रहा है। किसान को

पानी नहीं मिल रहा है । वह बुरी तरह से परेशान है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्वायंट नम्बर 40 और 41 में बिजली आपूर्ति के बारे में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रदेश में 24–24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार से कहीं–कहीं पर 22 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं यह बात ऑन रिकार्ड कह रहा हूं कि पलवल और फरीदाबाद के अंदर 6 से 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। चाहे डोमैस्टिक फीडर हो, चाहे एग्रीकल्चर फीडर हो और चाहे इण्डस्ट्रीज़ को दी जाने वाले बिजली की बात हो। एग्रीकल्चर फीडर पर अभी केवल मात्र 6 घंटे ही बिजली की सप्लाई आती है। इसी प्रकार से एक–एक घंटे करके टोटल 8 घंटे के लिए बिजली वॉटर सप्लाई के लिए दी जाती है।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने बिजली के बारे में चर्चा की है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा बिजली वितरण निगम उत्तरी एवं दक्षिणी में एग्रीकल्चर फीडर में 8 घंटे, डोमैस्टिक में 12 घंटे और इण्डस्ट्रीज के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 34 ऐसे फीडर और 100 गांव ऐसे हैं जहां पर हमने "हमारा गांव, जगमग गांव" योजना के तहत 24 घंटे बिजली देनी शुरू की है। इसके तहत हमने एक योजना बनाई है कि जिस गांव में नई केबल लगवाई जायेगी, मीटर बाहर लगवाये जायेंगे, 90 प्रतिशत तक बिजली के बिलों की रिकवरी होगी और लाईन लॉसिज़ 20 प्रतिशत से कम होंगे उस गांव को हम अलग से फीडर निकालकर 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : नागर जी, आप कंटीन्यू करें। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप एक मिनट में कंक्ल्यूड करें ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि आज किसान पूरी तरह से खुश है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि बिजली के मीटर लेने के लिए किसानों को अपने स्तर पर अलग–अलग एक–एक लाख रूपये देने पड़ रहे हैं। ऐसा करने के बाद ही उनके बिजली के मीटर लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और किसानों को इस लूट से मुक्ति दिलवाई जाये। जहां तक स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात है आप हुड्डा साहब के 10 साल के शासन काल की वर्तमान सरकार के ढ़ाई साल के शासन काल से तुलना करके देखें तो आप पायेंगे कि वर्तमान सरकार में हुड्डा साहब की सरकार के मुकाबले 10 गुणा कम स्कूल अपग्रेड हुए हैं। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे साथी ने कहा कि प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश और मैथ्स सहित दूसरे विषयों के भी पूरे टीचर्ज नहीं हैं। अभी मार्च में परीक्षायें आ रही हैं ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि टीचर्ज के अभाव में वे बच्चे कैसे एग्जाम देंगे और कैसे पास होंगे? इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। एक हमारा अहम मुद्दा है नीमका गांव। जहां पर पॉलिटैक्निक कॉलेज बनाया गया । नीमका गांव ने 18.5 एकड़ जमीन इस पॉलिटैक्निक कॉलेज के लिए दी। वहां पर बिल्डिंग तैयार हो गई । 10–15 दिन पहले वहां पर इस बिल्डिंग का उद्घाटन होना था लेकिन कुछ ही समय पहले वहां पर एन.एस.ए.आई.सी. का कोई केन्द्र बना दिया। इस प्रकार से वहां पर बोर्ड लगाकर उसको बदलने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। अगर समय रहते इसके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो इसके आने वाले समय में बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। इसी प्रकार से अब मैं अपने क्षेत्र में जो सरकारी हॉस्पिटल्ज़ हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। इनके अंदर डॉक्टर्ज ही नहीं हैं। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को सिर में चोट लग जाये तो टांके तक लगाये जाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है। अनिल विज जी यहां पर नहीं हैं नहीं तो हम उनको बताते कि वहां पर कैसे हालात हैं? वहां पर कोई ऐसा इक्यूपमैंट नहीं है जिससे मरीजों का प्रॉपर ईलाज हो सके। वर्तमान के हमारे साथी अभी बड़े उत्साह के साथ कह रहे थे कि हम लोगों ने मेक–इन–इंडिया कर दिया, स्किल–इन–इंडिया कर दिया और डिजीटल इंडिया कर दिया। मैं वर्तमान सरकार के साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे इन मामलों में कुछ काम भी करके दिखायें क्योंकि सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलता। अब सभी लोगों को यह पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती ही कहती है काम नहीं करती है। चाहे वह मोदी जी हों या फिर खट्टर जी हों या फिर दूसरे मंत्री हों सभी कहने में बहुत माहिर हैं लेकिन काम करने में माहिर नहीं है। जब करने की बात आती है तो एक वहां एक अंतहीन चुप्पी मिलती है।

श्री अध्यक्ष : नागर जी, कृपया वाइंड–अप करें।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी जैसा कि एक माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वे हुड्डा सरकार के गड्ढ़े भर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि असली गड्ढ़े तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। अगर माननीय मंत्री राव नरबीर जी देखना चाहें तो मैं इनको तिगांव विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा दिखा सकता हूं। वहां पर सड़कों में एक–एक फुट के गड्ढ़े हैं। न ही इन्होंने उन गड्ढ़ों को भरवाया और न ही कहीं कोई नई सड़क ही बनवाई। पिछले दिनों राव नरबीर जी ने कहा था कि 6 महीने में गड्ढे भर जायेंगे

और 1 साल में सड़कें बन जायेंगी । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब मैं बेरोजगारी भत्तों के बारे में बताना चाहता हूं । पिछले दिनों आपने कहा था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और यह आपके मैनीफैस्टो में भी है लेकिन आज तक किसी नौजवान को न तो कोई बेरोजगारी भत्ता दिया गया है और न ही कोई रोजगार दिया गया है । इसी तरह से आपकी सरकार का नारा था कि सबका–साथ, सबका विकास और आपकी सरकार ने यह नारा बहुत जोर–शोर से उठाया था । इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन हम तो श्री रामबिलास शर्मा जी को ही मुख्यमंत्री मान लेते हैं । पिछले दिनों कहा गया था कि 5–5 करोड़ रूपये हर विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए दिये जायेंगे लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि वे 5–5 करोड़ रुपये कहां गये? हम और हमारे इंडियन नैशनल लोकदल के साथी भी रोज देखते हैं कि 5–5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे । सबका साथ और सबका विकास कहां हो रहा है? अब मैं भ्रष्टाचार पर अपने विचार रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कहां पर खत्म हुआ है? मैं फरीदाबाद जिले की बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे जहां पर दिखाई दे रहा है मैं वहीं की बात करना चाहूंगा । यह सच है कि फरीदाबाद में अगर किसी अनअथॉराईज्ड प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो 50 हजार से 1 लाख रुपये कमीशन के रूप में लिये जाते हैं । आर्म लाइसैंस जारी करने के लिए ** लिया जाता है । इसी प्रकार अगर किसानों को मुआवजा दिया जाता है तो मुआवजे में से 1–2 प्रतिशत काट कर किसानों को मुआवजा दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली विभाग के बारे में भी कुछ बात रखना चाहता हूं । जिस व्यक्ति का 40–50 गज का मकान है तो उसका बिजली का बिल विभाग अपने स्तर पर बढ़ा कर 70–70 हजार और 1 लाख रुपये तक दे देते हैं और जब वे जे.ई. और एस.डी.ओ. से या लाइनमैन से ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो जब तक उनको 5–7 हजार रुपये नहीं मिलते तब तक वे बिल को ठीक नहीं करते हैं । यहां पंवार साहब बैठे हुये हैं और बिजली विभाग इनके पास ही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री ललित नागर जी जो ** वाली बात कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न की जाये ।

श्री अध्यक्ष : नागर जी ने जो अनपार्लियामैंटी वर्ड यूज किया है उसे रिकार्ड न किया जाए। ललित जी, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत है और प्रमाण है कि बिजली के बिल ठीक करवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं तो सरकार को भेज दें मंत्री जी उस पर कार्रवाई करवायेंगे । हाउस इसीलिए बैठा हुआ है कि अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर इनके पास कोई प्रमाण है कि किसी से पैसे लेकर उसका बिजली का बिल कम किया गया है तो वे सरकार

को सौंपे, सरकार उस पर कार्रवाई करवायेगी । अगर कोई इस प्रकार का मामला है तो पहले शिकायत भी की होगी तो वह भी बतायें । उनके साथ इनकी मिलीभगत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ललित जी, अगर आपके पास कोई प्रमाण है कि पैसे लेकर लोगों के बिजली के बिल ठीक किये जाते हैं तो आप दीजिए हम उस पर कार्रवाई करवायेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, अगर ललित नागर जी के पास कोई इस तरह की शिकायत है तो बतायें इस प्रकार बेबुनियादी आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी विधायक श्री नागर जी ने छोटे मकानों के बिजली के बिल की चर्चा की । उनके पास जैसा उन्होंने कहा है अगर उसका कोई सबूत हो कि बिजली विभाग के कर्मचारी ने किसी के मीटर की गलत रीडिंग देकर के लाखों का बिल जारी किया है तो वे हमें दे दें हम उसकी जांच करवा कर उस पर कार्रवाई करेंगे ।

.....

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नागर जी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और पिछले दिनों भी मैंने इस बारे में कहा था चूंकि यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है । मेरे क्षेत्र में बहुत सारी कालोनियां हैं जिनमें विकास कार्य की बहुत ज्यादा जरूरत है । वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं और आने–जाने के लिये गलियां भी पक्की नहीं हैं। वहां पर कालोनियों की बहुत बुरी हालत है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम बहुत जल्द विकास दर के लिये कालोनाईजर से कुछ पैसे लेंगे और अपनी तरफ से कुछ पैसे उनको देंगे और उन कालोनियों में काम चालू करवा देंगे । उन बातों को भी लगभग पूरा एक साल हो गया आज तक उनमें कोई काम नहीं हुआ । पल्लापुल से लेकर सरस्वती कालोनी, श्याम कालोनी, और बसन्तपुर तक इस प्रकार की बहुत सारी कालोनियां हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप ये सारे नाम लिख कर दे दें । हम इनको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लेंगे ।

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी से विनती करूंगा कि बीच में कोई टोका टाकी न करना क्योंकि मैं किसी की बात पर टोका टाकी नहीं करता । मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य परसों से लेकर आज तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं । लेकिन जिनकी बदौलत आज हम खड़े हैं या बैठे हैं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर स्वर्ण जयंती का नाम भी आया । गुरू गोबिन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व की बात आई । गुरू गोबिन्द सिंह जी का 350वां साल प्रकाश पर्व करनाल में मनाया गया है, इसके लिये मैं हरियाणा प्रदेश को बहुत–बहुत बधाईयां देता हूं । अध्यक्ष महेादय, हरियाणा को बने हुए 50 साल हो गये हैं। आज तक कभी भी किसी ने यह कोशिश ही नहीं की कि उन महापुरूषों की याद उसी तरह मनाई जाये, जिस तरह गुरू गोबिन्द सिंह जी के जन्म की याद मनाई जाती है । (विघ्न) सरदार जसविन्द्र सिंह जी मुझसे सीनियर मैंबर हैं । ये चार बार विधायक भी बन चुके हैं अर्थात् संधू साहब चार बार विधान सभा के मैंबर रहे हैं और ये मंत्री भी रहे हैं लेकिन गुरू गोबिन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व की छुट्टी हरियाणा सरकार के कलैंडर में आज तक कभी नहीं आई । इस बार हरियाणा सरकार ने हमारी छोटी सी विनती पर यह छुट्टी की है । हमने मुख्यमंत्री

जी को यह विनती पिछले साल नवम्बर–दिसम्बर मास में की थी । इस बार हरियाणा सरकार द्वारा पांच जनवरी की छुट्टी वर्ष 2017 के कलैंडर में दर्शाई गई है । हरियाणा को बने हुए 50 साल हो गये हैं लेकिन किसी ने भी इसकी कोशिश नहीं की । एक–दो बार कोशिश की गई तो उस समय उनकी चली नहीं । मैं गुरू गोबिन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यह बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया पवित्रता के साथ हमारी बहुत सी मांगे मानी हैं जो नई यूनिवर्सिटी बनेगी उसका नाम गुरू गोबिन्द सिंह के नाम से रखा जाएगा । मेरे असन्ध क्षेत्र में बाबा फतेह सिंह के नाम पर एक महाविद्यालय बनाया गया है । नाडा साहिब से लेकर रायपुर रानी, नारायण गढ़, सढ़ौरा और गोपाल सड़क का नाम गुरू गोबिन्द सिंह मार्ग रखा गया है । वी.एल.डी.ए. कॉलेज जिसका जिक्र कल श्री असीम गोयल जी भी कर रहे थे । उसका नाम माता गुर्जर कौर के नाम पर रखा गया है । जो लाईब्रेरी गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम पर चल रही थी वह कई सालों से कंडम पड़ी थी । उनकी रेनोवेशन करने की मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है इस पर 65 लाख रूपये लगने है। इसी तरह और भी कार्य हैं जैसे लौहगढ़वाले बाबा बन्दा सिंह जी बहादुर के भी स्मारक बनाने के लिये कहा गया है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं बढ़खालसा की बात बताता हूँ जोकि एक बहुत ही बढ़िया स्थान है। हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए गुरू तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश तक कलम करवा दिया था लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटे थे। उनके कटे हुए शीश को एक टोकरी में रखकर जब भाई जयता सिंह बढ़खालसा के जंगलों में से छिपते–छिपाते हुए आनन्दपुर साहिब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें खुशहाल सिंह दहिया नाम का एक शख्स मिला। उसने भाई जयता सिंह से पूछा कि तुझे ऐसा कौन सा खतरा है जिसकी वजह से तुम जंगलों में से छिपकर जा रहे हो। भाई जयता सिंह ने बताया कि उसके सिर पर जो टोकरी रखी है उसमें गुरू तेग बहादुर जी का शीश है जिसको वह आनन्दपुर साहिब ले जाना चाहता है लेकिन उसके पीछे जालिम सरकार की फौज लगी है इसलिए वह जंगलों से छिपते–छिपाते जा रहा है। खुशहाल सिंह दहिया ने जब टोकरी से कपड़ा उठाकर कटे हुए शीश को देखा तो पाया कि कटे हुए शीश की शक्ल उसकी स्वयं की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती थी। खुशहाल सिंह दहिया ने आंव देखा न तांव और भाई जयता सिंह को आदेश दिया कि वह अपनी तलवार से उसका सिर कलम करके यहां पर रख दे

और गुरू तेगबहादुर जी के शीश को आनन्दपुर साहिब ले जाये। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के समक्ष इतिहास की बात बता रहा हूँ। इतिहास को समझना बहुत मुश्किल होता है। आज हम एक दूसरे के साथ लड़ते–झगड़ते हैं और उन महान आत्माओं को भूल चुके हैं जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर गुरू तेग बहादुर जी अपना शीश कलम न करवाते और गुरू गोबिन्द सिंह जी अपने पूरे परिवार की कुर्बानी न देते तो आज हमारा धर्म परिर्वतन हो जाना था और आज हमें कोई और ही भाषा बोलनी थी। आज हम स्वच्छ व स्वछंद हवा में सांस ले रहे हैं यह सब उन महान लोगों की देन व कृपा की वजह से संभव हो सका है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अहसान मानते हैं जिन्होंने करनाल में प्रदेश स्तरीय गुरू गोबिन्द सिंह प्रकाश उत्सव की 350वीं वर्षगांठ का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। हरियाणा के पिछले 50 वर्ष के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा इस तरह का भव्य कार्यक्रम मनाने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, करनाल की मंड़ी में समस्त हरियाणा से सभी जातियों व संप्रदायों के भाई–बहन, समाजिक संगठन व राजनीति से संबंध रखने वाले भाई–बहन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम की सफलता को देखकर वाहवाही करे बिना नहीं रह सके। अध्यक्ष महोदय, पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी, जोकि पटना साहब से चलकर करनाल में आए थे, ने अपने भाषण में यह बात कही थी अगर गुरू गोबिन्द सिंह प्रकाश उत्सव की 350वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन पटना साहब में जोकि 5 तारीख को हुआ था, उतना ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन अगर कोई दूसरा हुआ है तो वह हरियाणा प्रदेश में हुआ है। जब पंजाब के शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाल सिंह बढूंगर यहां पर आए तो उन्होंने भी यह बात मानी थी कि यद्यपि पंजाब पंजाबियों का सूबा है लेकिन बावजूद इसके वे आज तक भी पंजाब प्रदेश में इतना भव्य आयोजन नहीं मना सके हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? हम छोटी छोटी बातों पर बेमतलब लड़ते–झगड़ते हैं। यह बहुत गलत बात है। हमें देश व प्रदेश के हित में काम करने चाहिएं। अभी सदन में ललित नागर जी कह रहे थे कि लाईसेंस जारी करने की एवज में पैसे वसूले जाते है। इस संदर्भ में मैं एक बात सदन के समक्ष बताना चाहता हूँ। मुझे कैथल जिले में ग्रीवैंसिज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जब मैं चेयरमैन बनकर पहली बार

वहां पर गया तो पिछली सरकारों के शासन काल के दौरान बिगड़े हुए कुछ लोग जिनको काम के बदले पैसे लेने की आदत पड़ चुकी थी, का मामला मेरे संज्ञान में आया। कोई एक–दो हजार नहीं बल्कि लाख–डेढ लाख रूपये तक लिए जाने के बारे में मुझे बताया गया। नागर जी की बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को काम करवाने की एवज में पैसे लेने की आदत पड़ी हुई होती है। हमारी सरकार आने के बाद इस तरह के लोगों पर एक तरह से अंकुश लगाने का काम किया गया है। एक बार मैंने ऐसे ही किसी केस में एक अधिकारी को पकड़ा और अपने पास बुलाकर लास्ट वार्निंग देते हुए समझाया कि यदि आईन्दा लाईसैंस देने के बदले कभी पैसे लेने की बात मेरे संज्ञान में आई तो तुम्हारा कुछ और ही इलाज किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में चहुमुंखी विकास हो रहा है। हम प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाते है और पाते हैं कि प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। चाहे डबवाली जाकर देख लो, होडल जाकर देख लो या नारनौल अथवा कालका जाकर देख लो समस्त हरियाणा में बराबर विकास हो रहा है। कैथल से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी विधायक हैं। मैं कैथल का प्रभारी था और एक बार मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे। मैं हैरान रह गया जब मुख्यमंत्री महोदय ने कैथल के विकास कार्यों के लिए 185 करोड़ रूपये देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया है। भाई जयप्रकाश जी यहां बैठे हैं जोकि आजाद उम्मीदवार है, इनके हल्के को मुख्यमंत्री जी 215 करोड़ रूपए देकर आए हैं। कहां– कहां की बात करू? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यो के लिए दिल खोलकर पैसा न दिया हो। अगर हम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं तो पाते हैं कि इन्होंने प्रदेश के 89 विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर केवल 90वें विधान सभा क्षेत्र अर्थात किलोई विधान सभा क्षेत्र में करोड़ों–करोड रूपये दिए। अतः मेरा इतना ही कहना है कि भाईयों इनकी बातों पर विश्वास मत करा करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्क्लः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, विर्क साहब तो सबका साथ–सबका विकास वाली अवधारणा की बात कर रहे है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गृह क्षेत्र में आए थे। मुझे उम्मीद थी कि कोई न कोई सौगात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए देकर जायेंगे परन्तु मुख्यमंत्री महोदय ने एक चवन्नी तक नही दी। यही नहीं मुख्यमंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कॉलेज के लिए पोस्ट्स सैंग्शन करने तक की घोषणा नहीं की तो क्या इस चीज को सबका साथ–सबका विकास की मूर्त अवधारणा माना जा सकता है?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, हमारे सी.पी.एस. सरदार बख्शीश सिंह विर्क ने साढ़े तीन सौ सालों प्रकाशोत्सव पर बड़ा प्रकाश डाला है । हरियाणा और पंजाब पहले दोनों ही एक प्रांत होते थे।जैसा माननीय सदस्य ने गांव बढ़खालसा का जिक्र किया तो यह हरियाणा प्रदेश के जिले सोनीपत का गांव है। इसी तरह गांव लाखनमाजरा जिला रोहतक का गांव है । हमने सारे हरियाणा के बीच सरदार सुरजीत सिंह बरनाला को श्रद्धांजलि दी थी । उनका जन्म अटेली में हुआ था । मुझे यह बात जानकर आज बड़ा अच्छा लगा कि आदरणीय बहन गीता भुक्कल भी पंजाबी के सैंटैंस बोल लेती है । (विघ्न) गीता जी, आप कोई बात तो माना करो । आप हमारी समझदार बहन हो । कभी–कभी आप भी किरण चौधरी का अनुसरण किया करो । (विघ्न) स्पीकर सर, साढ़े तीन सौ सालों की इतनी बड़ी विरासत केवल पंजाब में नहीं है बल्कि यह बिहार की राजधानी पटना तक फैला हुआ है । गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म पटना शहर में हुआ था । नीतीश कुमार जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं । हमारी सरकार ने वहां जाकर अपने इतिहास को उजागर करने के वास्ते करोड़ों रूपया खर्च किया है । इस अवसर पर मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा –

सूरा सो पहचानिये जो लड़े दीन दे हेथ

पुरजा–पुरजा कट मरे

कबहूं न छोड़े खेत

हमारा ग्रंथ कहता है कि –

एक नूर ते सब जग उपजा

सब कुदरत के बंदे ।

अध्यक्ष जी, कुछ लोग इन साढ़े तीन सौ सालों का मतलब नहीं समझते है । हमने अपनी विरासत को उजागर करने के वास्ते सरदार बख्शीश सिंह विर्क जैसे योग्य व्यक्ति जो सिखी को मानता है, जो सिखी को जानता है, जो सिखी में श्रद्धा रखता है उनको उसका चेयरमैन बनाया है यह हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी बात है (विघ्न)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कौन–सा गांव गोद लिया हुआ है । मैंने इन्हें बताया कि मैंने गांव बाण्सा गोद लिया हुआ है । इसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि अब तक वहां पर विकास कार्यों के लिए कितने पैसे पहुंच चुके हैं । अध्यक्ष जी, ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी वहां पर कई रिश्तेदारियां भी अवश्य होंगी । मैं आपके माध्यम से इन्हें कहना चाहता हूं कि ये वहां पर जाकर देख लें । वह गांव इण्डियन नैशनल लोकदल का रहा है । इसके अतिरिक्त वह गांव पहले रिजर्व हल्के में आता था । मैंने जब उस गांव में जाकर पहली बार वर्ष 2009 में चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव में उस गांव से जीत हासिल की थी । इस बार भी जब मैंने एम.एल.ए. का चुनाव लड़ा तो मैं फिर वहां से एक नम्बर पर रहा हूं । मैं सदन में यह बात पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि यहां पर हरियाणा प्रदेश की एक पूरी पंचायत बैठी हुई है और जो आदमी पंचायत में झूठ बोलता है वह बाहर कहीं पर जाकर अपनी बात नहीं रख सकता । उस गांव की विकास की गति कोई भी माननीय सदस्य जाकर देख सकता है । कल जो नौकरियों की लिस्ट लगी है तो उस गांव के दो बच्चे उसमें सलैक्ट हुए हैं । इसके अतिरिक्त चार दिन पहले जो नौकरियों की लिस्ट लगी थी उसमें भी दो बच्चे सलैक्ट हुए थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, विर्क साहब का कहने का मतलब है कि वहां पर शिक्षा का सिस्टम पहले से बेहतर हो गया है और वे बच्चे मैरिट के बेस पर नौकरियों में सिलैक्ट हो रहे हैं । इनका कहने का अर्थ है कि वे बच्चे अब मैरिट बेस पर लग रहे हैं लेकिन इससे पहले वे मैरिट में आने पर भी सिलैक्ट नहीं होते थे । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष जी, उस गांव के लड़के पहले भी पढ़ाई–लिखाई में अच्छे थे लेकिन अब इस सरकार की कोशिशों से उस गांव के

लड़के नौकरियों में सलैक्ट हो रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) उन लड़कों को नौकरियां मैंने नहीं दिलवाई है लेकिन उनके नौकरियों में सलैक्ट होने से इस सरकार का नाम ऊंचा हो रहा है । मेरा कहना है कि उस गांव के गरीब लड़के भी नौकरी लग रहे हैं, मीडियम वर्ग के लड़के भी नौकरी लग रहे हैं, पढ़े–लिखे लड़के भी नौकरी लग रहे हैं । (विघ्न) इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि उस गांव के लड़के अपनी योग्यता के बल पर नौकरी लग रहे हैं । कोई भी उस गांव में जाकर देख ले उसको पता चलेगा कि हमने कितने काम करवाए हुए हैं। मैं शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती सुमिता सिंह को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भेजा (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दोनों सरपंचों के खाते में 88 लाख रूपये भेज गए दिए हैं, जिसे पंचायती राज विभाग विकास के कार्यों पर खर्च करेगा। विपक्ष के साथी हल्के में पिछले दो सालों में करवाये गए कामों को भी जाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसी कवि ने श्री गुरू गोविन्द सिंह जी के बारे में लिखा है कि –

**बात करूँ मैं जब की, बात करूँ मैं तब की, बात करूँ मैं अब की, अगर गुरू गोविन्द सिंह जी ना होते तो कुमति होती सबकी !''

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने को समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 2 मार्च, 2017 को प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक वीरवार, 2 मार्च, 2017, प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

*07:00 बजे

.....